रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)—73

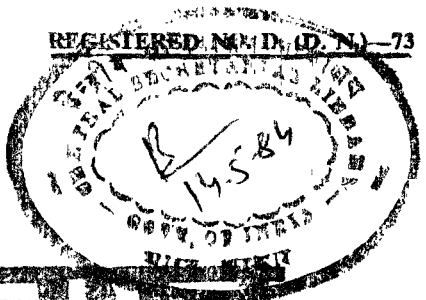

B 14.5.84

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1984/चैत्र 11, 1906

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1984/CHAITRA 11, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1984

का०आ० 1020.—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री दिनेश चन्द्र माथुर, अधिवक्ता को दिल्ली जिला और सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में विशेष पुलिस स्थापन नियमित मामला आर०सी० 2/80-सी०आई०यू० (ए) में अभियुक्तों के और दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले से उत्पन्न विषयों के अभियोजन के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[संख्या 225/2/84-ए०वी०डी०-II(1)]

एच०के० वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 19th March, 1984

S.O. 1020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Dinesh Chander Mathur, Advocate, as Special Public Prosecuter for conducting the prosecution of the accuseds in the Delhi Special Police Estabilshment Regular Case R.C. 2/80-CIU(A) in the Court of District and Sessions Judge, Delhi as well as in the Delhi High Court in the matters arising out of this case.

[No. 225/2/84-AVD.II(i)]

H. K. VERMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1984

का०आ० 1021.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) संशोधन नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के पांचवीं अनुसूची के पैरा 2 के अंत में और उसमें के पहले परन्तुक के पहले निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

"निदेशक, प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत, प्रकाश स्तम्भ और प्रकाशपोत विभाग (नौवहन और परिवहन मंत्रालय) जामनगर,

मुम्बई, कोचीन, मद्रास, कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर, उनके नियंत्रण के अधीन समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों की बाबत"

[सं० एफ० 13(1)-पेंशन/84]

ए०एन० साहनी, अवर सचिव

टिप्पण : साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 तारीख 1-12-1960 के एस०ओ० 3000 के रूप में प्रकाशित किए गए थे। इन नियमों का तीसरा पुनर्मुद्रण (30-11-1978 तक संशोधित) वर्ष 1979 में छपा था। बाद में नियमों का संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया :—

1. एफ 13/(8)/77-ई०बी० (बी) तारीख 13-12-1978
2. एफ 13/(5)/78/ई०बी० (बी) तारीख 23-4-1979
3. एफ 13/(11)/78/ई०बी० (बी) तारीख 30-5-1979
4. एफ 13/(7)/78-ई०बी० (बी) तारीख 18-6-1979
5. एफ 17/(5)-ई०बी० 78(बी) तारीख 18-6-1979
6. एफ 19/(15)/पेन० 76/जी०पी०एफ० दिनांक 9-8 1979
7. एफ 9(2)/ईबी(बी)/पेन/78-जी०पी०एफ० तारीख 13-11-1979
8. एफ 10(10 पेन/79/जी०पी०एफ० तारीख 3-3-1980
9. एफ 20(22)/ईबी(बी)/पेन/79/जी०पी०एफ० तारीख 18-4-80
10. एफ 13(6)/पेन/79/जी०पी०एफ० तारीख 18-4-1980
11. एफ 16(2)-पेन 79-जी०पी०एफ० तारीख 12-6-1980
12. एफ 11(1)-पेन/77-जी०पी०एफ० तारीख 1-10-1980
13. एफ 16(3)/पेन/79/जी०पी०एफ० तारीख 13-10-1980
14. एफ 10(2)-पेन/81-जी०पी०एफ० तारीख 21-12-1981
15. एफ 13(1)-पेन/82 तारीख 8-9-1982
16. एफ 13(3)/पेन/82/जी०पी०एफ० तारीख 30-4-1983
17. एफ 19(2)/पेन/80-जी०पी०एफ० तारीख 10-5-1983
18. एफ 16(3)-पेन/77-जी०पी०एफ० तारीख 19-5-1983
19. एफ 13(2)-पेन-80-जी०पी०एफ० तारीख 20-5-1983
20. एफ 19(1)-पेन-83-जी०पी०एफ० तारीख 20-5-1983
21. एफ 20(10)-पेन-81-जी०पी०एफ० तारीख 30-5-1983

New Delhi, the 19th March, 1984

S.O. 1021.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These Rules may be called the General Provident Fund (Central Services) First Amendment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gaette.

2. In para 2 of the Fifth Schedule to the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, the following entries shall be inserted at the end and before the first proviso therein, namely :—

"Directors of Lighthouses and Lightships, Department of Lighthouses and Lightships (Ministry of Shipping and Transport) Jamnagar, Bombay, Cochin, Madras, Calcutta and Port Blair, in respect of Group 'C' and 'D' employees under their control".

[No. F. 13(1)-Pension/84]

A. N. SAWHNEY, Under Secy.

NOTE :—General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 were published as S.O. 3000 dated 1-12-1960. The Third reprint (Corrected upto 30-11-1978) of the rules was printed in 1979. The rules were subsequently amended vide notifications mentioned below :—

1. F. 13(8)/77-EV(B) dated 13-12-1978.
2. F. 13(5)/78-EV(B) dated 23-4-1979
3. F. 13(11)/78-EV(B) dated 30-5-1979
4. F. 13(7)/78-EV(B) dated 18-6-1979
5. F. 17(5)/EV(B)/78 dated 18-6-1979
6. F. 19(15)-Pen/76-GPF dated 9-8-1979
7. F. 9(2)-EV(B)/Pen/78-GPF dated 13-11-1979
8. F. 10(10)-Pen/79-GPF dated 3-3-1980
9. F. 20(22)-EV(B)/Pen/79-GPF dated 18-4-1980
10. F. 13(6)-Pen/79-GPF dated 18-4-1980
11. F. 16(2)-Pen/79-GPF dated 12-6-1980
12. F. 11(1)-Pen/77-GPF dated 1-10-1980
13. F. 16(3)-Pen/79-GPF dated 13-10-1980
14. F. 10(2)-Pen/81-GPF dated 21-12-1981
15. F. 13(1)-Pen/82 dated 8-9-1982
16. F. 13(3)-Pen/82 dated 30-4-1983
17. F. 19(2)-Pen/80-GPF dated 10-5-1983
18. F. 16(3)-Pen/77-GPF dated 19-5-1983
19. F. 13(2)-Pen/80 dated 20-5-1983
20. F. 19(1)-Pen/83-GPF dated 20-5-1983
21. F. 20(10)-Pen/81-GPF dated 30-7-1983.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 7 फ़रवरी, 1984

आय-कर

का० आ० 1022.—इस कार्यालय की दिनांक 25-2-82 की अधिसूचना सं० 4488 (फ़ा० सं० 203/68/81-आ० क० नि०-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (II) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "विश्वविद्यालय" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(1) यह कि विश्व भारती, शान्ति निकेतन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(2) यह कि उक्त विश्वविद्यालय अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए ;

(3) यह कि उक्त विश्वविद्यालय अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसम्पत्तियों, देनदारियों

दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

विश्व भारती, शान्ति निकेतन

यह अधिसूचना 1-4-1983 से 31-3-1986 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 5702/फा० सं० 203/16/84-आ० क० नि०-II]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 7th February, 1984

INCOME TAX

S.O. 1022.—In continuation of this Office Notification No. 4488 (F. No. 203/68/81-ITA. II) dated 25-2-82, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "University" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Visva Bharati, Santiniketan will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said University will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every Financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said University will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

VISVA BHARATI, SANTINIKETAN.

This notification is effective for a period of three years from 1-4-1983 to 31-3-1986.

[No. 5702/F. No. 203/16/84-ITA. II]

नई दिल्ली 24 फरवरी 1984

शुद्धि-पत्र

का० आ० 1023.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 6-12-1980 की अधिसूचना सं० संख्या 3758 में अनुसंधान परियोजना समय-अवधि को निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

के लिए	पढ़िये
1-8-1980 से तीन वर्ष	1-8-1980 से 29-2-1984 तक।

[सं० 5662/फा० सं० 203/160/80-आ० क० नि०-II]

New Delhi, the 24th February, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 1023.—It is hereby notified for general information that in Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 3758 dated 6th December, 1980, the duration of research project may be read as under :—

For	Read
3 years with effect from 1-8-1980.	1-8-1980 to 29-2-1984.

[No. 5662/F. No. 203/160/80-ITA.II]

नई दिल्ली 7 मार्च 1984

आय-कर

का० आ० 1024.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को आयकर नियम 1962 के नियम 6(4) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है :—

वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना का नाम :	डिवेलपमेंट आफ नो-हाऊ फार मेकिंग सोल्युबल हाइड्रोक्सी एथिल सेलूलोज।
प्रायोजक का नाम	मेसर्स श्रीराम रेयन्स, कोटा
कार्यान्वित करने वाली प्रयोगशाला	श्री राम इंस्टिट्यूट फार इंडस्ट्रियल रिसर्च दिल्ली।
प्रारम्भ करने की तारीख :	1-11-1983
पूरा करने की तारीख	30-6-1984
अनुमानित परिव्यय :	70,000/- रु०

श्रीराम इंस्टिट्यूट फार इण्डस्ट्रियल रिसर्च दिल्ली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(1)(ii) के अंतर्गत अनुमोदित है देखिए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 1-2-1965 की अधिसूचना संख्या का० आ० 475

[सं० 5705/फा० सं० 203/20/84-आ० क० नि०-II]

New Delhi, the 7th March, 1984

INCOME TAX

S.O. 1024.—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purpose of sub-section (2A) of the Section 35 of the Income-Tax Act, 1961 read with rule 6 (iv) of the Income-tax Rules, 1962 by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi.

Name of the scientific research project	Development of know-how for making water soluble hydroxy ethyl Cellulose.
Name of sponsor	M/s. Shriram Rayons, Kota.

Name of implementing lab	Shriram Institute for Industrial Research, Delhi.
Proposed date commencement	1-11-1983
Proposed date of completion	30-6-1984
Estimated outlay	Rs. 70,000/-

Shriram Institute for Industrial Research, Delhi is approved under section 35(1)(ii) of I.T. Act, 1961 vide Ministry of Finance Department of Revenue Notification No. S.O. 475 dated 1-2-1965.

[No. 5705 /F.No. 203/20/84-ITA.II]

आय-कर

का० आ० 1025.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को आयकर नियम 1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनार्थ नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है :—

वैज्ञानिक अनुसंधान	जिनेटिक सिलेक्शन एण्ड मेंटेनेंस ऑफ हाई
परियोजना का नाम	प्राफिशिएंसी स्ट्रेंज ऑफ रिजोबियम फॉर विग्ना सिनेंसिस लेंस कलिनरिस।
प्रायोजक का नाम	मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि०
कार्यान्वित करने वाली	वनस्पति विज्ञान विभाग मेरठ विश्वविद्यालय
प्रयोगशाला	मेरठ।
प्रारंभ करने की तारीख	1-2-1984
पूरा करने की तारीख	31-1-1987
अनुमानित परिव्यय	3.13 लाख रुपये।

2. मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(1)(ii) के अंतर्गत अनुमोदित है देखिए वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बैंकिंग विभाग) की दिनांक 1-11-1976 की अधिसूचना सं० 1545 (फा० सं० 203 114/76-आ०क०नि०-II] ।

[सं० 5703/फा० सं० 203/23/84-आ० क० नि०-II]

INCOME TAX

S. O. 1025.—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purpose of sub-section (2A) of the section 35 of the Incometax Act, 1961 read with rule 6(iv) of the Income-tax Rules, 1962 by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi:

Name of the scientific research project	Genetic Selection and Maintenance of High Proficiency Strains of Rhizobium for Vigna Sinensis Lens Culinaris.
Name of the sponsor	M/s. Hindustan Lever Lt., Bombay.
Implementing Lab	Department of Botany, Meerut, University Meerut.
Date of commencement	1-2-1984
Date of completion	31-1-1987
Estimated outlay	3.13 lakhs.

2. Meerut University, Meerut stands approved under section 35 (1) (ii) of the Income-tax Act, 1961 vide Ministry of Finance (Department of Revenue & Banking) Notification No. 1545(F.No. 203/114/76-ITA.II) dated 1-11-1976.

[No. 5703 /F.No. 203/23/84-ITA. II]

आय-कर

का०आ० 1026.—इस कार्यालय की दिनांक 2-3-83 की अधिसूचना सं० 5118 (फा०सं० 203/176/82-आ०क० नि०-II) के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात विज्ञान और प्रौदयोगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (II) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है अर्थात :—

1. यह कि आर्गेनन रिसर्च सेंटर, कलकत्ता वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसमें द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

आर्गेनन रिसर्च सेंटर, कलकत्ता

यह अधिसूचना 30-12-1983 से 29-12-1984 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 5701/फा० सं० 203/10/84-आ०क० नि०-II]

INCOME TAX

S.O. 1026.—In continuation of this office Notification No. 5118 (F. No. 203/176/82-ITA. II) dated 2-3-83, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Organon Research Centre, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

ORGANON RESEARCH CENTRE, CALCUTTA

This notification is effective for a period of one year from 30-12-1983 to 29-12-1984.

[No. 5701/F.No. 203/10/84-ITA.II]

आय-कर

का०आ० 1027.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को, आयकर नियम 1962 के नियम 6 (iv) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनार्थ नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है :—

वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना का नाम	डिवेल्पमेंट आफ फ्लेम रिटार्डेंट फिनिशिज फार एक्रिलिक ब्लेंडिड फेब्रिक्स ।
प्रायोजक का नाम	मेसर्स इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०, बड़ौदा ।
कार्यान्वित करने वाली प्रयोगशाला	दि बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन लि० बम्बई ।
प्रारम्भ करने की तारीख	10 जनवरी 1983
पूरा करने की तारीख	9 जनवरी, 1985
अनुमानित परिव्यय	2,22,000/—रु०

बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई आयकर अधिनियम 1922 की धारा 10(2)(xiii) के अंतर्गत अनुमोदित है देखिए अधिसूचना का०आ० सं० 3466 दिनांक 17-11-54।

[सं० 5704/फा०सं० 203/19/84—आ०क०नि०-II]

INCOME TAX

S.O. 1027.— It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purpose of sub-section (2A) of the Section 35 of the Income tax Act, 1961 read with rule 6(iv) of the Income-tax Rules, 1962 by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi;

Name of the scientific research project	Development of Flame retardant finishes for Acrylic blended Fabbrics.
Name of the sponsor	M/s. Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Baroda.
Implementing lab.	The Bombay Taxtile Research Association Ltd., Bombay.
Date of commencement	10th January, 1983
Date of completion	9th January, 1985
Estimated outlay	Rs. 2,22,000/-

Bombay Textile Research Association, Bombay is approved under section 10(2) (xiii) of the Income-tax Act, 1922 vide notification No. S.R.O. No. 3466 dated 17-11-1954.

[No. 5704/F.No. 203/19/84-ITA. II)]

आय-कर

का०आ० 1028.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को, आयकर नियम, 1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है :—

वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना का नाम	पोलिमर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पिनिंग परफार्मेन्स आफ पोलियस्टर्स ।
प्रायोजक का नाम	मेसर्स स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड, यू कवि नगर गाजियाबाद—201002
कार्यान्वित करने वाली प्रयोगशाला	इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालोजी, नई दिल्ली ।

प्रारम्भ करने की तारीख	जनवरी, 1984
पूरा करने की तारीख	अगस्त, 1984
अनुमानित परिव्यय	65 000 रु० (पैंसठ हजार रुपये केवल)

2. भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, नई दिल्ली आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) (ii) के अंतर्गत अनुमोदित है, देखिए, वित्त मंत्रालय (राजस्व एवं बैंकिंग विभाग) की अधिसूचना सं० 1502 (फा०सं० 203/122/76-आ०क० नि० II, दिनांक 25-9-1976 ।

[सं० 5706/फा०सं० 203/22/84-आ०क०नि०-II]

मदन गोपाल चंद गोयल, अवर सचिव

INCOME TAX

S. O. 1028.— It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purpose of sub-section (2A) of the Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6(iv) of the Income-tax Rules, 1962 by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi:

Name of the scientific research project	Polymer Characteristics and Spinning Performance of Polyesters.
Name of the sponsor	M/s. Swadeshi Polytex Limited, New Kavi Nagar, Ghaziabad-201002
Implementing Lab.	Indian Institute of Technology, New Delhi.
Date of Commencement	January, 1984
Date of completion	August, 1984
Estimated outlay	Rs. 65,000/- (Rupees Sixty-five thousand only).

2. Indian Institute of Technology, New Delhi stands approved under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 vide Ministry of Finance (Deptt. of Revenue & Banking) Notification No. 1502 (F.No.203/122/76-IIA.II) dated 25-9-1976.

[No. 5706/F.No. 203/22/84-ITA. II]

M.G.C. GOYAL, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली 15 मार्च 1984

स्टाम्प

का०आ० 1029.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उस शुल्क को माफ करती है जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, द्वारा केवल तैंतीस करोड़ रुपये के मूल्य के ऋण पत्रों (बीसवीं श्रृंखला) के रूप में जारी किए जाने वाले बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है ।

[सं० 20/84—स्टाम्प फा० सं० 33/12/83-वि०क०-II]

भगवान दास, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th March, 1984

STAMPS

S.O. 1029.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty within which the bonds in the nature of debentures (tenth series) of the value of rupees thirty three crores only to be issued by the Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi, are chargeable under the said Act.

[No. 20/84-Stamps—F. No. 33/12/83-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1984

सं० 88/84-सीमा-शुल्क

का० आ० 1030.—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापत्तनम विमान पत्तन को, पोतों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित आयातित माल की उतराई के लिए सीमा-शुल्क विमान पत्तन के रूप में नियत करती है ।

[फा० सं० 481/8/83-सीमा-शुल्क-7]

टी० एच० के० घौरी, अवर सचिव

New Delhi, the 31st March, 1984

No. 88/84-CUSTOMS

S.O. 1030.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints Visakhapatnam Airport as customs airport for the unloading of imported goods required for the manufacture of ships.

[F. No. 481/8/83-CUS. VII]

T.H.K. GHAURI, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1983

आय-कर

का० आ० 1031.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "डायोसीज आफ़ तंजाबुर सोसायटी, तंजावुर" को कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5694/फा० सं० 197/74/84-आ० क० (नि-I)]

New Delhi, the 6th March, 1984

(INCOME TAX)

S.O. 1031.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Diocese of Thanjavur Society, Thanjavur" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5694/F. No. 197/82-IT(AI)]

(आयकर)

का० आ० 1032.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "मिलाग्रेस चर्च, मंगलौर" को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5698/फा० सं० 197/158/82-आ० क० (नि०-1)]

(INCOME TAX)

S.O. 1032.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Milagres Church, Mangalore" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 & 1983-84.

[No. 5698/F. No. 197/158/82-IT(AI)]

(आयकर)

का० आ० 1033.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "श्री चन्दर चिनार बड़ा अखाड़ा उदासीन ट्रस्ट, श्रीनगर" को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5699/फा० सं० 197/161/83-आ० क० (नि०-1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1033.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Chander Chinar Bada Akhara Udaseen Trust, Srinagar" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5699/F. No. 197/161/83-IT(AI)]

(आयकर)

का० आ० 1034.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "श्रीमान माधव सिद्धान्तोन्नाहिनी सभा" को कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1985-86 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5695/फा०सं०-197/60/81-आ०क० (नि०-1]

(INCOME-TAX)

S.O. 1034.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sriman Madhwa Siddhantonnahini Sabha" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1985-86.

[No. 5695/F. No. 197/60/81-IT(AI)]

(आयकर)

का० आ० 1035.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "गुरु गोविन्द सिंह फाउण्डेशन, चण्डीगढ़" को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5696/फा०सं० 197/155/82-आ० क० (नि०-1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1035.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Guru Gobind Singh Foundation, Chandigarh" for the purpose of the said section for the period covered by the assesment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5696/F. No. 197/155/82-IT(AI)]

(आयकर)

का० आ० 1036.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "सोसायटी आफ़ दि फ्रांसिसकन ब्रदर्स आफ़ कोटागिरी" को कर निर्धारण-वर्ष 1972-73 से 1974-75 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5697/फा०सं० 197/235/82-आ० क० (नि०-I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1036.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Society of the Franciscan Brothers, of Kotagiri" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1972-73 to 1974-75.

[No. 5697/F. No. 197/235/82-IT(AI)]

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1984

(आय-कर)

का०आ० 1037.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "श्री काममाक्षी त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मद्रास" को समस्त तमिलनाडु राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजा-स्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० 5711/फा०सं० 176/12/84-आ०का० (नि०-I)]

आर०के० तिवारी, अवर सचिव

New Delhi, the 8th March, 1984

(INCOME-TAX)

S.O. 1037.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Karumari Thripurasundari Temple, Madras" to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 5711/F. No. 176/12/84 IT(AI)]

R. K. TEWARI, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1984

(आयकर)

का०आ० 1038.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा दिनांक 3 मार्च, 1982 की, समय-समय पर संशोधित अधिसूचना सं० 4501(फा०सं० 187/41/81-आ०क०नि०-1) में निम्नलिखित संशोधन करता है। अनुसूची की क्रम सं० 23-ङ के सामने स्तम्भ 3 के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी। क्रम सं० 23-ण को इस प्रकार जोड़ा जाएगा।

अनुसूची

आयकर	आयुक्त	प्रधान कार्यालय	क्षेत्राधिकार
1		2	3
23-ङ	जांच-I	कलकत्ता	1. सर्वेक्षण परिमंडल-I, कलकत्ता।
			2. विशेष परिमंडल-VI, कलकत्ता।
			3. विशेष परिमंडल-VII, कलकत्ता।
			4. केन्द्रीय सूचना शाखा, कलकत्ता।
23-ण	जांच-II	कलकत्ता	1. विशेष परिमंडल-IX, कलकत्ता

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1983 से प्रभावी होगी।

[सं० 5712/फा०सं० 187/31/83-आ०का०(नि०-1)]

आर०के० तिवारी, अवर सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 8th March, 1984

(INCOME-TAX)

S.O. 1038.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Notification No. 4501 [F.No. 187/41/81-IT(AI)] dated 3-3-1982 as amended from time to time. The entries under column 3 against S.No. 23-N of the Schedule shall be substituted by the following entries. S. No. 23-O shall be added as follows :

SCHEDULE

Commissioner of Income tax	Head-quarters	Jurisdiction
1	2	3
23-N Investigation I	Calcutta	1. Survey Circle-I, Calcutta.
		2. Special Circle-VI, Calcutta
		3. Special Circle VII, Calcutta
		4. Central Information Branch, Calcutta.
23-O. Investigation-II	Calcutta	1. Special Circle-IX, Calcutta

This notification shall take effect from 1-12-1983

[No. 5712/F.No. 187/31/83-IT(AI)]

R.K. TEWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1983

आयकर

का०आ० 1039.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 1-12-1983 की अधिसूचना सं० 5496 [फा०सं० 187/29/83-आ०क०(नि०)] में निम्नलिखित शुद्धियां की गई हैं।

"अनुसूची" में स्तम्भ (3) में—

"क्षेत्राधिकार" शीर्ष के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार पढ़े।

1. जांच परिमंडल, लुधियाना।
2. सर्वेक्षण परिमंडल, लुधियाना
3. जिला III, अमृतसर।
4. सर्वेक्षण परिमंडल, श्रीनगर।
5. सर्वेक्षण परिमंडल, जालन्धर।
6. जांच परिमंडल, जालन्धर।
7. सर्वेक्षण परिमंडल, फगवाड़ा।
8. सर्वेक्षण परिमंडल, चण्डीगढ़।
9. जांच परिमंडल, करनाल।
10. सर्वेक्षण परिमंडल, गुड़गांव।
11. सर्वेक्षण परिमंडल, हिसार।
12. सर्वेक्षण परिमंडल, रोहतक।
13. सर्वेक्षण परिमंडल, यमुना नगर।
14. सर्वेक्षण परिमंडल, अमृतसर।

परन्तु ऐसे मामलों पर, जहां 1-4-1983 से पूर्व कम से कम एक कर निर्धारण पूरा कर लिया गया है, सर्वेक्षण परिमंडल का क्षेत्राधिकार आयकर आयुक्त (जांच) लुधियाना के पास नहीं रहेगा और इन मामलों के सम्बन्ध में, क्षेत्राधिकार जैसा भी मामला हो, राज्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर आय कर आयुक्त, पटियाला, रोहतक, अमृतसर और जालन्धर में निहित होगा।

आय कर आयुक्त, पटियाला, रोहतक, अमृतसर और जालन्धर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण की सामान्य शक्ति।

अधिसूचना 1-12-1983 की बजाय 1-1-1984 से प्रभावी होगी।

[सं. 5539/फा०सं० 187/29/83-आ०क० (नि०-I)]

बी०वी० श्रीनिवासन, निदेशक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

New Delhi, the 22nd December, 1983

INCOME-TAX

S.O. 1039.—The following corrections are made in the Central Board of Direct Taxes Notification No. 5496 (F. No. 187/29/83-IT(AI) dt. 1-12-1983.

In "SCHEDULE" in Column (3)—under head "Jurisdiction"; for the existing entries; read;—

1. Investigation Circle, Ludhiana.
2. Survey Circles, Ludhiana.
3. District III, Amritsar.
4. Survey Circle, Srinagar.
5. Survey Circles, Jalandhar.
6. Investigation Circle, Jalandhar.
7. Survey Circle, Phagwara.
8. Survey Circle, Chandigarh.
9. Investigation Circle, Karnal.
10. Survey Circle, Gurgaon.
11. Survey Circle, Hissar.
12. Survey Circle, Rohtak.
13. Survey Circle, Yamunanagar.
14. Survey Circle, Amritsar.

Provided that the jurisdiction of survey Circles over the cases where at least one assessment has been completed before 1-4-1983 would cease to be with CIT(Inv.), Ludhiana, and in respect of these cases the jurisdiction would stand vested with the Cs. IT, Patiala, Rohtak, Amritsar and Jalandhar, as the case may be, at the territorial jurisdiction.

General power of Survey in respect of areas comprised in the jurisdiction of Commissioners of Income-tax, Patiala, Rohtak, Amritsar and Jalandhar.

Instead of 1-12-1983, the notification will come into effect from 1-1-1984.

[No. 5539/F. No. 187/29/83-IT(AI)]

V. B. SRINIVASAN, Director

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर 1983

आय-कर

का०आ० 1040.—दिनांक 31-1-1983 की अधिसूचना सं० 5085 (फा०सं० 261/23/82-आ०क०न्या०) और दिनांक 7-11-1983 की अधिसूचना सं० 5445 (फा०सं० 261/23/82-आ०क० न्या०) द्वारा यथा संशोधित बोर्ड की दिनांक 10-11-1982 की अधिसूचना सं० 4966 (फा०सं० 261/23/82-आ०क० न्या०) में आयकर आयुक्त (अपील) हैदराबाद के क्षेत्राधिकार के सामने कालम 2 और 3 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

	कालम-2	कालम-3
17.	निरीक्षी सहायक आयुक्त (कर-निर्धारण)-III हैदराबाद	निरीक्षी सहायक आयुक्त (कर-निर्धारण)-III हैदराबाद

यह आदेश 21-10-83 से लागू होगा।

[सं० 5553/फा०सं० 261/23/82-आ०क०न्या०]

New Delhi, the 28th December, 1983

INCOME- TAX

S.O. 1040.—In the Board's Notification No. 4966 dated 10-11-1982 (F.No. 261/23/82-ITJ) as modified by Notification No. 5085 dated 31-1-1983 (F. No. 261/23/82-ITJ) and by Notification No. 5445 dated 7-11-1983 (F.No. 261/23/82-ITJ), in Column 2 and Column 3 against the jurisdiction of Commissioner of Income-tax (Appeals)-II, Hyderabad the following shall be added.

	Col. - 2	Col. - 3
17.	I.A.C. (Assessment)-III Hyderabad.	I.A.C. (Assessments)-III Hyderabad.

This notification shall take effect from 21-10-83.

[No. 5553/F.No. 261/23/82-ITJ)]

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1984

(आयकर)

का० आ० 1041.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे पूर्व जारी की गई अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा निदेश देता है कि निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट रेंजों का अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, आयकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय का छोड़कर जिन पर अधिकारिता आयकर आयुक्त (अपील) में निहित है, अनुसूची के स्तम्भ (2) की तदनरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमण्डलों, वार्डों और जिलों में आयकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने कार्यों का निर्वहण करेगा।

अनुसूची

रेंज	आयकर परिमण्डल, वार्ड तथा जिले
1. अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'पी' रेंज, नई दिल्ली।	(1) समस्त सर्वेक्षण वार्ड, नई दिल्ली। (2) समस्त विशेष जाँच परिमंडल, नई दिल्ली।

यह अधिसूचना 16 अगस्त, 1983 से प्रभावी होगी।

[सं० 5605/फा० सं० 261/15/83-आ० क० न्या०]

के० एम० सुल्तान, अवर सचिव

New Delhi, the 1sF e bruary, 1984

INCOME-TAX

S.O. 1041.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of the previous notification in this regard, the Central

Board of Direct Taxes hereby directs that Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range specified in column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column (2) thereof excluding all persons and Incomes assessed to Incometax over which the jurisdiction vests in Commissioner of Incom-tax (Appeals).

SCHEDULE

Range	Income-tax Circles, Wards & Districts
1. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'P' Range, New Delhi	(i) All Survey Wards, New Delhi (ii) All Special Investigation Circles, New Delhi.

This notification shall take effect from 16-8-1983
[No. 5605 /F.No. 261/15/83-ITJ)]
K. M. SULTAN, Under Secy.

(सीमा शुल्क समाहर्ता का कार्यालय)

बंगलौर, 11 जनवरी, 1984

अधिसूचना संख्या 1/84

(सीमाशुल्क)

का० आ० 1042—1962 के सीमाशुल्क अधिनियम, की धारा 8 (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, श्री सी० के० गोपालकृष्णन्, सीमाशुल्क के समाहर्ता, बंगलौर, कर्नाटक सीमाशुल्क समाहर्तालय, एतद्द्वारा, कर्नाटक राज्य में स्थित नये मंगलौर के बड़े बंदरगाह में सभी निर्यात आयात एवं तटवर्ती मालों को लादने तथा उतारने के लिए, अनुबन्ध में बताए गए स्थान को अनुमोदित करता हूं।

अनुबन्ध

बंदरगाह का नाम	घाट की संख्या	मालिक का नाम	घाट की सीमाएं जिसमें इसकी परिसीमाओं का पूरा विवरण भी शामिल है	लादने के स्थान का विवरण	घाट की लम्बाई और चौड़ाई	संबंधित माल का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नये मंगलौर का बड़ा बन्दरगाह	7	सरकारी	लम्बाई में 250 मीटर	डाकरम के पश्चिम भाग की तरफ निर्मित घर्थ	लम्बाई 250 मीटर चौड़ाई 33 मीटर	निर्यात/आयात और तटवर्ती वस्तुएं

[सी० नं० VIII/48/13/84 सी० 2/सीमाशुल्क]
सी० के० गोपालकृष्णन, समाहर्ता

(OFFICE OF THE COLLECTOR OF CUSTOMS)

Bangalore, the 11th January, 1984

NOTIFICATION No. 1/84

(CUSTOMS)

S.O. 1042—In exercise of the powers conferred upon me under section 8(a) of the Customs act, 1962, I, C.K. Gopalakrishnan Collector of Customs, Bangalore, Karnataka Customs Collectorate, hereby approve the place as detailed in the Annexure for the loading and unloading of all Export Import and Coastal goods in respect of the Major Port of New Mangalore in the State of Karnataka.

ANNEXURE

Name of Port	No. of the wharf	Name of the owner	Limits of the wharf including full details of boundaries	Details of the loading place	Measurement of the wharf in length and Breadth	Particulars goods dealt with
1	2.	3	4	5	6	7
Major Port of New Mangalore	7	Government	250 Metres in length	Newly constructed berth at the western side of the Dockaram	Length 250 Metres Breadth 30 Metres.	All Export/Import and Coastal goods

[C.No. VIII/48/13/84. C2/Cus.]
C. K. GOPALAKRISHNAN, Collector of Customs

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1984

का० आ० 1043.—सर्वश्री ओरिएन्ट स्टील एंड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, 2 ब्राबौन रोड, कलकत्ता 700001 को 6,78,470/- रु० (35830 पाउंड) के लिए निशुल्क विदेशी मुद्रा विनिमय के अन्तर्गत आयात लाइसेंस संख्या पी०/सी०जी०/2082393/सी०/एक्स एक्स/79/एच/81 दिनांक 16-4-81 प्रदान किया गया था । उन्होंने उपर्युक्त आयात लाइसेंस के अनुलिपि लाइसेंस (केवल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति) के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल आयात लाइसेंस (सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति) सीमा शुल्क प्राधिकारी, बम्बई के पास पंजीकृत कराने के बाद खो गई / अस्थानस्थ हो गई है । अनुलिपि लाइसेंस पूरे मूल्य अर्थात् 6,78,470/-रु० (35830 पाउंड) के लिए चाहिए । यह पार्टी द्वारा पूर्ण रूप से प्रयुक्त है । आवेदक इस बात से सहमति और वचन देता है कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति मिल जाने पर उसे इस कार्यालय के रिकार्ड के लिए वापस कर देगा ।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने शपथ आयुक्त, बल्लभगढ़, फरीदाबाद के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि मूल आयात लाइसेंस खो गया/अस्थानस्थ हो गया है । इसलिए, यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के उप-खंड (9 सी० सी०) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री ओरियन्ट स्टील एंड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता का जारी किए गए उपर्युक्त आयात लाइसेंस संख्या पी०/सी०/जी०/2082393 दिनांक 16-4-81 (केवल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति) एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

3. लाइसेंसधारी को उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि लाइसेंस (सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति) अलग से जारी किया जा रहा है ।

[मिसिल संख्या : 189/81/24/ सी० जी० 4/847]

पॉल बैक, उप-मुख्य नियंत्रक

कृते मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 15th March, 1984

S.O. 1043.—M/s. Orient Steel & Industries Ltd, 2, Brabourne Road, Calcutta 700001 was granted import licence No. P/CG/2082393/C.XX/79/H/81 dated 16th April, 1981 under Free Foreign Exchange for Rs. 6,78,470 (£ 35830). They have applied for issued of duplicate licence (Customs purpose only) of the said licence on the grounds that the original import licence (Customs purpose copy) have been lost/misplaced after having been registered with Customs Authorities, Bombay. Duplicate licence is required for the full amount Rs. 6,78,470 (£ 35830). This is fully utilised by the party. The applicant agrees and undertakes to return the original custom copy of the above licence if traced later to this office for record.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn in before oath commissioner Ballabgarh Faridabad. I am accordingly satisfied that the original import licence has been lost/misplaced. Therefore, in exercise of the power conferred under sub-clause (9cc) of the Import (Control) Order 1955 dated 7th December, 1955 as amended the said import licence (Customs purpose only) No. P/CG/2082393 dated 16th April, 1981 issued to M/s. Orient Steel & Industries Ltd., Calcutta is hereby cancelled.

3. A duplicate licence (Customs purpose copy) of the said licence is being issued separately to the licensee.

[File No. 189/81/24/CG IV/847]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller

for Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1984

का० आ० 1044.—कर्नल एस० के० शर्मा, सुपुत्र एस० आर० शर्मा, 494 आर, मॉडल टाउन, जालन्धर शहर (पंजाब) के निवासी को एक नं० कार 1984 इसूजू जेमिनी-4 डोर, सडिम 4-सिलेंडर 1817-सीसी डीजल माडल पी एफ डी 60-आर के आयात के लिए 39,000-रु० का एक सीमाशुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/3071462 दिनांक 4-2-84 प्रदान किया गया था । आवेदक ने उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट अस्थानस्थ हो गया है । आगे यह बताया गया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट को किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और इस प्रकार सीमा-शुल्क निकासी परमिट के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है ।

2. अपने तर्क के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने यथोचित न्यायिक प्राधिकारी के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट आवेदक से अस्थानस्थ हो गया है । समय-समय पर यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के उप खंड 9 (गग) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कर्नल एस० के० शर्मा के लिए जारी किए गए उक्त मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/307-1462 दिनांक 4-2-84 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है ।

3. कर्नल एस० के० शर्मा को सीमाशुल्क निकासी परमिट की एक अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[सं० जीए-165/83-84/बीएलएस/4029]

वी० के० मेहता, संयुक्त मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 16th March, 1984

S.O. 1044.—Col. S. K. Sharma, S/o S. R. Sharma resident of 494/R. Model Town, Jullundur City (Punjab) was granted a Customs Clearance Permit No P/J/3071462 dated 4-2-84-Rs. 39,000 for the import of One No. Car 1984 Isuzu Gemini 4-Door, Seden 4-Cylinder 1817-CC Diesel Model

PFD-60-RK. The applicant has applied for issue of Duplicate copy of the above mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Customs Authority and such the value of the CCP has not been utilised at all.

2. In support of his contention, the licensee has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/3071462 dated 4-2-84 has been misplaced by the applicant. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/3071462 dated 4-2-84 issued to Col. S. K. Sharma is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to Col. S. K. Sharma separately.

[No. GA-165/83-84/BLS/4029]

V. K. MEHTA, Jt. Chief Controller

निरस्त आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1984

का० आ० 1045.—सर्वश्री हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, 412-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, नई दिल्ली को वैसल्स 17014 के मैरीन पम्पस की बदल (रिप्लेसमेंट) आयात हेतु एक आयात लाइसेंस स. आई/ए/2235205 दिनांक 30-11-82 वास्ते रु० 3200 प्रदान किया गया था।

आवेदक फर्म ने इस कथन के समर्थन में अब एक शपथ-पत्र आयात-निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1983-84 के पैरा 357 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अप्रैल मार्च- 83 की अवधि के लिये प्रदान किया गया लाइसेंस सं. आई/ए/2235205 दिनांक 30-11-82 वास्ते रु० 3200 की एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी बिना किसी सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किये एवं बिना उपयोग किये ही खो गई हैं/अस्थानस्थ हो गई है।

मैं संतुष्ट हूं कि उक्त आयात लाइसेंस की मूल एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी खो गई है।

अतः आयात-व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दि० 7-12-55 (यथा-संशोधित) की धारा 9(सी सी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस सं० आई/ए/2235205 दि० 30-11-82 की मूल एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूं।

आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्यविधि-पुस्तिका 1983-84 के पैरा 357 के अनुसार उक्त लाइसेंस सं० आई/ए/2235205 दि० 30-11-82 वास्ते रु० 3200- की एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जायेगा।

[फाइल सं० जी/आर/168/एएम-83/एयू II/सीएलए]

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 18th January, 1984

S.O. 1045.—M/s. Hindustan Shipyard Ltd., 412-A Transport Bhavan, New Delhi were granted import licence No. I/A/2235205 dt 30-11-82 for Rs. 3200 for import replacement for marine pumps of vessels 171014.

The application has filed a affidavit as required under para 357 of Hand Book of Import Export Procedure 1983-84 wherein they have stated that exchange Control copy of the licence No. I/A/2235205 dated 30-11-82 for Rs. 3200 issued for the period AM. 83 has been lost/misplaced without having been registered with any custom authority and unutilised at all.

I am satisfied that the Exchange Control copy of the licence has been misplaced.

In exercise of the power conferred on me under subject clause 9(cc) in the import Trade Control Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended upto date, the said original exchange control copy of licence No. I/A/2235205 dated 30-11-82 for value of Rs. 3,200 is hereby cancelled.

The applicant is now being issued duplicate of Exchange Control copy of I/Licence I/A/2235205 dated 30-11-82 for Rs. 3,200 in accordance with the provision in Para 357 of Import Export Procedure 1983-84.

[File No. GR/168/AM.83/AU. II/CLA]

निरस्त आदेश

का०आ० 1046.—सर्वश्री अरिहन्त स्पिनिंग मिल्स (प्रोपराइटर महावीर स्पिनिंगमिल्स लिमिटेड) इन्डस्ट्रियल एरिया, मलेर कोटला, जिला संगरूर पंजाब को एक डिजिटल फाइबोग्राफ मॉडल 530 और एक इन्स्टेन्ट/वेइ मॉडल 485 के आयात के लिये 2,68,337/-रु० का एक आयात लाइसेंस सं० पी०/सीजी/2080148 दिनांक 28-7-82 को प्रदान किया गया था।

आवेदक फर्म ने इस कथन के समर्थन में अब एक शपथ-पत्र आयात निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1983-84 के पैरा 353 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उक्त लाइसेंस सं. पी/सीजी/2080148 दिनांक 28-7-82 अप्रैल-मार्च-82 की अवधि के लिये 2,68,337/-रु० की दोनों प्रतियां एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी एवं कस्टम हेतु कापी बिना किसी सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किये एवं बिना उपयोग किये ही खो गई हैं/अस्थानस्थ हो गई हैं।

कस्टम कापी एवं एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) शेष राशि रु० 2,68,337- को पूरा करने के लिये अपेक्षित है।

मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल एक्सचेंज कन्ट्रोल एवं कस्टम हेतु कापी खो गई हैं / अस्थानस्थ हो गई हैं।

अतः आयात-व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9 (सीसी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस सं० पी/सीजी/2080148 दिनांक 28-7-82 वास्ते रु० 2,68,337-की मूल कस्टम हेतु कापी/एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूं।

आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1983-84 के पैरा 352-355 के अनुसार उक्त लाइसेंस स. पी/सीजी/2080148 दिनांक 28-7-82 रु० 2,68,337- की कस्टम हेतु कापी/एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जा रहा है।

एन. डी. अग्निहोत्री, उपमुख्य नियंत्रक
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

[फाइल सं० सी जी/नॉन-जी ओ डी/नॉन-एस एसआई/21/ए० एम-82/एयू II/सीएलए]

CANCELLATION ORDER

S.O. 1046.—M/s. Arihant Spinning Mills, Prop. Mahavir Spinning Mills Ltd., Industrial Area Malerkotla Distt. Sangrur (Punjab) were granted Import licence No. P/CG/2080148 dated 28-7-82 for Rs. 2,68,337 for import of One Digital fibregraph Model 530 and one Instant/weig model 485.

The applicant has filed an affidavit as required under para 353 of Hand Book of Import-Export Procedure 1983-84 wherein they have stated that Custom Purpose and Exchange Control copy both copies of the licence No. P/CG/2080148 dated 28-7-82 for Rs. 2,68,337 issued for the period AM.82 has been lost/misplaced without having been registered with any custom authority and utilised at all.

The duplicate Customs Purpose/Exchange Control copy both Customs Purpose and Exchange Control copy is required to cover the balance value of Rs. 2,68,337.

I am satisfied that the Customs Purpose copy/Exchange Control copy/both Customs purpose copy and Exchange Control Copy of the licence has been misplaced.

In exercise of the powers conferred on me under subject clause 9(cc) in the Import Trade Control Order, 1955 dated 7-12-55 as amended upto date, the said original Customs Purpose Copy/Exchange Control copy/both Customs Purpose copy and Exchange Control copy of licence No. P/CG/2080148 dated 28-7-82 for the value of Rs. 2,68,337 is hereby cancelled.

The applicant is now being issued duplicate Customs Purpose copy and Exchange Control copy, both Customs Purpose copy and Exchange Control copy of Import licence No. P/CG/2080148 dated 28-7-82 for Rs. 2,68,337 in accordance with the provision of paras 352-355 of Hand Book of Import Export procedure 1983-84.

[File No. CG/NON-DGTD/NON-SSI/21/AM.82/AU. II/CLA]

N.D. AGNIHOTRI, Dy. Chief Controller

For Jt. Chief Controller

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1984

का०आ० 1047.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी को जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
श्री प्रदीप मेहरा, महाप्रबन्धक दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, के नई दिल्ली के स्वामित्वाधीन उसके द्वारा अर्जित या किराये पर लिए गए सरकारी स्थान

[फा०सं० एस० आई (पी)-15(31)/83]

आर०बी० अजवानी, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 15th March, 1984

S.O 1047.— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officers mentioned in Column 1 of the Table below, being gazetted officer of Government, to be Estate Officer for the purpose of the said Act, who shall exercise powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of Public premises specified in the corresponding entry in Column (2) of the said Table :—

TABLE

Designation of Officer	Category of Public premisses and local limits of jurisdiction.
1	2
Shri Pradeep Mehra, General Manager, Delhi State Industrial Development Corporation Limited, New Delhi	Public premises owned/ acquired or hired by the Delhi State Industrial Development Corporation Limited, N. Delhi

[F. No. SSI(P)-15(31)/83]

R.B. AJWANI, Under Secy

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1984

का० आ० 1048.—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में रविशंकर विश्वविद्यालय के न्यायालय के सदस्यों ने डा० के० पी० मेहरा को 9 फरवरी, 1984 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का० आ० 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिनियम में "धारा-3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अंतर्गत क्रम

संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाए, अर्थात् :—

"34. डा० के० पी० मेहरा, डीन
पंडित जवाहर लाल नेहरु मेमोरियल मेडिकल कालेज,
रायपुर, मध्य प्रदेश"

[सं० वी० 11013/3/84-एम० ई० (पी०)]

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 13th March, 1984

S.O. 1048.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act 1956 (102 of 1956) Dr. K. P. Mehra, has been elected by the members of the Court of Ravishankar University to be a member of the Medical Council of India with effect from the 9th February 1984.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Ministry of Health No. S.O. 138 dated the 9th January 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3" for serial number 34 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"34. Dr. K. P. Mehra,
Dean, Pandit Jawahar Lal Nehru Memorial Medical College, Raipur, Madhya Pradesh."

[No. V. 11013/3/84-M.E. (P)]

आदेश

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1984

का० आ० 1049.—यतः भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 2 फरवरी, 1961 की अधिसूचना संख्या-80345 के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने यह निर्देश दिया है कि "एम०डी० (कालेज आफ मेडिकल एवंजिलिस्ट्स, लॉस इंजिल्स, केलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमरीका" की चिकित्सा अर्हता भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी,

और यतः डा० (श्रीमती) कप्टन साइलियन कार्पेंटर हुड जो उक्त अर्हता रखती हैं, शिक्षण तथा धर्मार्थ कार्य के लिए फिलहाल साल्वेशन आर्मी कथरीन बूथ अस्पताल नगरकोइल, तलिमनाडु से संबंध हैं ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के खंड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि :—

(1) दो वर्ष की अवधि, अथवा

(2) वह अवधि जब तक डा० (श्रीमती) कैप्टन साइलियन कार्पेंटर हुड साल्वेशन आर्मी केथरीन बूथ अस्पताल नागरकोइल, तमिलनाडु से सम्बद्ध रहती हैं, जो भी कम हो, उक्त चिकित्सक की मेडिकल प्रैक्टिस के लिए सीमित अवधि होगी ।

[सं० वी० 11016/14/83-एम० ई० (पी०)]

ORDER

New Delhi, the 16th March, 1984

S.O. 1049.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. 80345 dated the 2nd February, 1961, the Central Government has directed that medical qualification, "M.D. (College of Medical Evangelists, Los Angeles, California, U.S.A.)" shall be recognised medical qualification for the purpose of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. (Mrs.) Captain Syllyann Carpenter Hood, who possesses the said qualification is for the time being attached to the Salvation Army Catherine Booth Hospital, Nagercoil, Tamil Nadu for the purpose of teaching and charitable work.

Now therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a period of two years, or

(ii) the period during which Dr. (Mrs) Captain Syllyann Carpenter Hood, is attached to the said Salvation Army Catherine Booth Hospital, Nagercoil, Tamil Nadu, whichever is shorter as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/14/83-ME(P)]

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1984

का० आ० 1050.—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारती दसन विश्वविद्यालय के न्यायालय ने चिकित्सा संकाय ने डा० एस० गनानदेसिकन को 5 जनवरी, 1984 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का० आ० 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम में "धारा-3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—

"62. डा गनानदेसिकन,
सिंडीकेट का सदस्य,
भारतीदेसन विश्वविद्यालय
टी० नगर, मद्रास"

[सं० पी० 11013/4/84-एम० ई० पी०]

New Delhi, the 19th March, 1984

S.O. 1050.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. S. Gnanadesikan of the medical faculty, has been elected by the Court of Bharathidasan University to be a member of the Medical Council of India with effect from the 5th January, 1984.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the late Ministry of Health No. S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of Section 3", after serial number 61 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"62. Dr. S. Gnanadesikan,
Member of the Syndicate,
Bharathidasan University,
T. Nagar, Madras.

Bharathidasan
University."

[No. V. 11013/4/84-ME(P)]

का० आ० 1051.—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102वां) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में चिकित्सा संकाय के एक सदस्य डा० जी० बक्थावथसलाम, को भारथियार विश्वविद्यालय के सीनेट ने 13 जनवरी, 1984 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का० आ० 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम में "धारा-3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 60 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"61. डा० जी० बक्थावथसलाम
सर्जन और निदेशक
के० जी० अस्पताल,
कोयम्बतूर-641018

भारथियार विश्वविद्यालय"

[सं० वी० 11013/5/84-एम ई० (पी०)]

S.O. 1051.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. G. Bakthavathsalam, a member of the medical faculty, has been elected by the Senate of Bharathiar University to be a member of the Medical Council of India with effect from the 13th January, 1984.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (i) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the late Ministry of Health No. S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3" for serial number 60 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"61. Dr. G. Bakthavathsalam,
Surgeon and Director,
K. G. Hospital,
Coimbatore-641018.

Bharathiar University."

[No. V. 11013/5/84-M.E.(P)]

का० आ० 1052.—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में कलकत्ता विश्वविद्यालय की सीनेट ने डा० भास्करानन्द रायचौधरी को डा० एम० एम० मुखर्जी के स्थान पर 22 मार्च, 1983 से आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या 5-13/50-एम-1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम में "धारा-3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—

"5. डा० भास्करानन्द रायचौधरी
डीन आव् फैकल्टी,
स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद्,
कलकत्ता विश्वविद्यालय"

[सं० वी० 11013/6/84-एम० ई० (पी)]

S.O. 1052.—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. Bhaskarananda Raychaudhury, has been elected by the Senate of the Calcutta University to be a member of the Medical Council of India with effect from the 22nd March 1983, vice Dr. M. M. Mukherjee;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the late Ministry of Health No. 5-13/50-MI, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3" for serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"5. Dr. Bhaskarananda Raychaudhury,
Dean of the Faculty Council for,
Postgraduate studies,
Calcutta University."

[No. V. 11013/6/84-M.E. (P)]

का० आ० 1053.—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में गुरू नानक

देव विश्वविद्यालय के सैनेट ने चिकित्सा संकाय के सदस्य डा० एस० पी० लाम्बा को 30 नवम्बर, 1983 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का० आ० 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात् :—

उक्त अधिनियम में "धारा-4 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"45 डा० एस० पी० लूम्बा,
प्रिंसिपल, चिकित्सा कालेज,
गुरू नानक देव विश्वविद्यालय,
अमृतसर ।"

[सं० वी० 11013/8/84-एम० ई० (पी०)]

पी० सी० जैन, अवर सचिव

S.O. 1053.—Whereas in pursuance of the provision of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. S. P. Lumba, a member of the Medical faculty, has been elected by the Senate of Guru Nanak Dev University to be a member of the Medical Council of India with effect from the 30th November 1983;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the late Ministry of Health No. S. O. 138 dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of Section 3" for serial number 45 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"45. Dr. S. P. Lumba,
Principal Medical College,
Guru Nanak Dev University,
Amritsar."

[No. V. 11013/8/84-ME(P)]

P. C. JAIN, Under Secy.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1984-03-09

का०आ० 1054.—भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1975-02-22 में प्रकाशित तत्काल उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय (भारतीय मानक संस्था) अधिसूचना संख्या एस० ओ० 534 दिनांक 1975-02-03 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दूध के लिए एल्युमिनियम, बायलर, की मानक डिजाइन का संशोधन किया गया है। मानक चिन्ह की संशोधित डिजाइन उसके शाब्दिक विवरण तथा तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दी गई है।

यह मानक चिन्ह भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त 1982-08-01 से लागू होगी

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मानक चिन्ह की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
1	2	3	4	5
1.		बायलर, दूध एल्युमिनियम	IS : 7185–1981 दूध के लिए एल्युमिनियम के बायलरों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या और वर्ष अंकित किया गया है।

[सं० सी एम डी 13 : 9]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, 1984-03-09

S.O. 1054.—In supersession of the then Ministry of Industry and Civil Supplies (Indian Standard Institution) notification number S.O. 534 dated 1975-02-03, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 75-02-22, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the design of the standard markfor boiler, milk, aluminium has been revised. The revised design

of the standard mark, together with the title of the relevant Indian Standard and verbal description of the design is given in the following Schedule.

This standard mark, for the purposes of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1982-08-01:

THE SCHEDULE

S.No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal Description of the Design of the Standard Mark
		Boiler, milk, aluminium	IS : 7185-1981 Specification for boiler, milk, aluminium (first revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col (2); the number of the Indian Standard, alongwith its year, being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

का०आ० 1055.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं रद्द कर दिए गए हैं और वापस ले लिए गए हैं:

अनुसूची

क्रम सं०	रद्द किए गए भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	गजट अधिसूचना की एस० ओ० संख्या और तारीख जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की अधिसूचना प्रकाशित की गई थी	कैफियत
1.	IS : 272-1950 कच्चे पटसन की ग्रेडिंग की विशिष्टि (पक्की छंटाई)	भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, दिनांक 1955-03-26 में एस०आर०ओ० 658 दिनांक 1955-03-26 के अधीन प्रकाशित	क्योंकि इस मानक में दी गई पटसन की किस्में अब विद्यमान नहीं है और व्यापार में इस किस्म की पटसन की गांठों के अनुसार बंधाई नहीं की जा रही है अतः इसे वापस ले लिया जाये।
2.	IS : 3183-1965 लिकर-इन-सिलेंडर के लिए आरी के दांतों वाले तार की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1966-04-09 में एस०ओ० 1081 दिनांक 1966-03-25 के अधीन प्रकाशित	क्योंकि इस मानक में दी गई अपेक्षाएं अब IS : 9568 (भाग 3)-1982 में शामिल कर ली गई है।

[सं० सी एम डी/13 : 7]

S. O. 1055 – In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standard(s), particulars of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have been cancelled and stands withdrawn:

THE SCHEDULE

S.No.	No. and Title of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified	Remarks
1.	IS: 272-1950 Specification for grading of raw jute (Pucca Assortment)	S.R.O. 658 dated 1955-03-26 published in the Gazette of India, Part II, Section-3, dated 1955-03-26	Since the varieties of jute specified in this standard no longer existed and that parking of jute bales in accordance with these varieties was not being practised in the trade. Hence withdrawn.
2.	IS : 3183-1965 Specification for saw-toothed wire for licker-in cylinder	S.O. 1081 dated 1966-03-25 published in the Gazette of India Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) dated 1966-04-09	As the requirements of this Indian Standard has been covered in IS : 9568 (Part III)-1982.

[No. CMD/18 : 7]

का०आ० 1056.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं रद्द कर दिए गए हैं और वापस ले लिए गए हैं :

अनुसूची

क्रम संख्या	रद्द किए गए भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	गजट अधिसूचना की एस० ओ० संख्या और तारीख जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की अधिसूचना प्रकाशित की गई थी	कैफियत
1.	IS : 3870–1966 चिकित्सा में उपयोग के लिए गैस सिलेन्डरों और सम्बद्ध उपकरणों के धरने उठाने की रीति संहिता	भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, दिनांक 1967-04-15 में एस० ओ० 1325 दिनांक 1967-03-30 के अधीन प्रकाशित	क्योंकि इस मानक में दी गई अपेक्षाएं अब IS : 8198 (भाग 12)–1982 में शामिल कर ली गई हैं ।

[सं० सी एम डी/13 : 7]

S. O. 1056 — In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is hereby notified that the Indian Standard, particulars of which is mentioned in the Schedule given hereafter, has been cancelled and stands withdrawn:

THE SCHEDULE

S.No.	No & Title of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. and Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was notified	Remarks
1.	IS : 3870-1966 Code of practice for handling gas cylinders and related equipment intended for medical use	S.O. 1325 dated 1967-03-30 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1967-04-15	As the requirements of this Indian Standard has been covered in IS : 8198 (Part-XII)-1982

[No. CMD/13 : 7]

नई दिल्ली, 1984-03-09

का०आ० 1057.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन मुहर) विनियम 1955 के विनियम 4 के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 3 के उपविनियम (1) के अनुसार प्राप्त अधिकारों के अधीन यहां अनुसूची में दिए भारतीय मानकों के संशोधन जारी किए गए हैं :

अनुसूची

क्रम सं०	संशोधित भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	जिस राजपत्र में भारतीय मानक के तैयार होने की सूचना छपी थी उसकी संख्या एवं तिथि	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन की संक्षिप्त विवरण	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 26–1979 टीन के पिंडों की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 अक्तूबर 1980	सारणी 1 संशोधित की गई है	1980-10-31
2.	IS : 276–1978 आस्टेनाइटी मेंगनीज इस्पात की ढली वस्तुओं की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 अक्तूबर 1980	खंड 10.1 संशोधित किया गया है	1980-10-31
3.	IS : 415–1978 शटलकाक की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 अक्तूबर 1980	1. पृष्ठ 4, खंड 4.2 द्वितीय वाक्य हटाया गया है। 2. चित्र 1 के बाद एक नयी टिप्पणी जोड़ी गई है।	1980-10-31

1	2	3	4	5	6
4.	IS : 549–1974 चिरवा पिनों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस०ओ० 988 दिनांक 1976-03-06	संख्या 2 अक्तूबर 1980	खंड 10 के स्थान पर नया खंड रखा गया है	1980-10-31
5.	IS : 893–1964 नारियल की जटा के रेशे की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	एस०ओ० 1152 दिनांक 1965-04-10	संख्या 1 अक्तूबर 1980	आवरण पृष्ठ, पृष्ठ 1 और 3 पर दिए गए शीर्षक के स्थान पर नया शीर्षक रखा गया है।	1980-10-31
6.	IS : 1063–1963, 14 मिमी चिंगारी प्लगों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	एस०ओ० 2370 दिनांक 1963-08-24	संख्या 3 अक्तूबर 1980	चित्र 2 संशोधित किया गया है।	1980-10-31
7.	IS : 1081–1960 धातु (इस्पात और एल्यु-मिनियम) के दरवाजे, खिड़कियां और रोशन-दान लगाने और चमकाने की रीति संहिता	एस०ओ० 2960 दिनांक 1960-12-19	संख्या 1 अक्तूबर 1980	(1) खंड 3.1 और 10.5 के स्थान पर नए खंड रखे गये हैं। (2) रिप्रिन्ट के पृष्ठ 5 पर पाद टिप्पणी हटाई गई है। (3) खंड 6.12 संशोधित किया गया है। (4) खंड 10.6 हटाया गया है और तदनुसार बाद के खंडों की संख्यायें फिर से डाली गई हैं।	1980-10-31
8.	IS : 1786–1979 कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी बनी उच्च शक्ति इस्पात के विकृत सरियों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 अक्तूबर 1980	(1) पृष्ठ 4 पर खंड 0.4.1 हटाया गया है। (2) खंड 3.4, 3.4.1 चित्र 1 और खंड 6.1 की अनौपचारिक सारणी संशोधित की गयी है। (3) खंड 3.4.2, 7.2.1 और परिशिष्ट ए बदले गये हैं। (4) खंड 3.1, 3.2 और 3.4.12 के बाद नयी टिप्पणियां जोड़ी गयी हैं। (5) खंड 3.4 के बाद खंड 3.4.0 जोड़ा गया है।	1980-10-31
9.	IS : 1932–1978 मालाथियोन, तकनीकी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	संख्या 2 अक्तूबर 1980	खंड ए-1.3.1 और खंड ए-1.6.2 के सूत्र के स्थान पर नया खंड और सूत्र रखा गया है।	1980-10-31
10.	IS : 2577–1974 मोटरगाड़ियों के लिए कारतूस फ्यूज की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस०ओ० 2858 दिनांक 1976-08-07	संख्या 1 अक्तूबर 1980	सारणी 1 संशोधित की गई है	1980-10-31
11.	IS : 2574–1964 प्रकाश उपकरणों की सामान्य अपेक्षाएं	एस०ओ० 4120 दिनांक 1964-12-05	संख्या 1 अक्तूबर 1980	खंड 4.2.6 संशोधित किया गया है।	1980-10-31
12.	IS : 2974 (भाग 1)–1969 मशीन नींवों के डिजाइन और निर्माण की रीति संहिता भाग 1 आगे पीछे चलने वाली मशीनों की नींव (पहला पुनरीक्षण)	एस०ओ० 3740 दिनांक 1971-10-09	संख्या 1 अक्तूबर 1980	(1) खंड 4.2 (बी) और 6.1.2 (एफ) संशोधित किये गये हैं। (2) खंड 5.7, 5.7.1, 5.7.1.1, 5.7.2 5.7.2.1 और 7.1 के स्थान पर नये खंड रखे गये हैं। (3) पृष्ठ 6 पर "*" और "†" पृष्ठ 8 पर "*", पृष्ठ 10 पर "*", "†" और "‡" तथा पृष्ठ 11 पर "*" चिह्न वाली पाद टिप्पणियों के स्थान पर नयी पाद टिप्पणियां रखी गई हैं। (4) खंड 2.10 के बाद खंड 2.11 जोड़ा गया है।	1980-10-31

*भारतीय मानक संस्था प्रमाणन मुहर योजना के प्रयोजनों के लिए यह संशोधन 1980-11-30 से लागू होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	IS : 3444–1978 सामान्य प्रयोग के लिए संक्षारणरोधी मिश्रधातु इस्पात और निकेल से बनी ढली वस्तुओं की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 अक्तूबर 1980	सारणी 3 संशोधित की गयी है	1980-10-31
14.	IS : 3716–1978 बिजली रोधन कोआर्डिनेशन के प्रयोग की मार्गदर्शिका (पहला पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 अक्तूबर 1980	(1) खंड 3.5.3, 4.3 और सी-1 संशोधित किये गये हैं। 2. आकृति 2 के शीर्षक के स्थान पर नया शीर्षक दिया गया है।	1980-10-31
15.	IS : 4060–1978 मोटरगाड़ियों के लिए दिशासूचक लैम्पों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 अक्तूबर 1980	खंड 5.3 संशोधित किया गया है।	1980-10-31
16.	IS : 4648–1968 रिहायशी इमारतों में बिजली लगाने के लिए मार्गदर्शिका	एस०ओ० 3608 दिनांक 1968-10-12	संख्या 1 अक्तूबर 1980	पृष्ठ 11, खंड 7.2, अन्तिम वाक्य हटा दिया गया है।	1980-10-31
17.	IS : 5153–1969 समानुपाती परकारों 150, 200 और 300 मिमी की विशिष्टि	एस०ओ० 4114 दिनांक 1969-10-11	संख्या 1 अक्तूबर 1980	खंड 4.3.5 संशोधित किया गया है।	1980-10-31
18.	IS : 5648–1970 ओ एनिसिडीन की विशिष्टि	एस०ओ० 5276 दिनांक 1971-12-04	संख्या 1 अक्तूबर 1980	सारणी 1 संशोधित की गयी है	1980-10-31
19.	IS : 6793–1972 फ्यूमेरिक अम्ल, खाद्य ग्रेड की विशिष्टि	एस०ओ० 2015 दिनांक 1975-05-28	संख्या 1 अक्तूबर 1980	(1) खंड 2.2.1 और 2.2.2 के स्थान पर नये खंड रखे गये है। (2) खंड 2.3.1 हटाया गया है।	1980- 10-31
20.	IS : 6821–1973 चूड़ी रहित बंधनों के नमूने लेने की पद्धतियाँ	एस०ओ० 2557 दिनांक 1985-08-09	संख्या 1 अक्तूबर 1980	(1) खंड 1 संशोधित किया गया है। (2) पृष्ठ 6 पर परिशिष्ट "ए" में अनौपचारिक सारणी, "रिवेट" के नीचे क्रम संख्या 1 से 9 हटायी गयी है और अनुवर्ती मदों की संख्या तदनुसार बदल दी गई है।	1980-10-31
21.	IS : 7002–1972 प्रचलित ऐंठ प्रकार की इस्पात की षटकोणी लाक-नट की विशिष्टि	एस०ओ० 776 दिनांक 1976-02-21	संख्या 1 अक्तूबर 1980	खंड 4 के स्थान पर नया खंड दिया गया है।	1980-10-31
22.	IS : 8019–1976 दाँतों के लिए कृत्रिम पत्थर की विशिष्टि	एस०ओ० 1597 दिनांक 1979-05-19	संख्या 1 अक्तूबर 1980	(1) खंड ए-5.1 के स्थान पर नया खंड रखा गया है। (2) पृष्ठ 7 और 9 पर, खंड ए-5.1.1, ए-5.1.2, ए-5.2 और ए-5.2.1 हटाये गये हैं।	1980-10-31
23.	IS : 8187–1976 डी-टाइप फ्यूजों की विशिष्टि	एस०ओ० 98 दिनांक 1980-01-12	संख्या 1 अक्तूबर 1980	(1) पृष्ठ 3, खंड 0.3, पंक्ति 3 "सारणी 1" के स्थान पर "सारणी 31" किया गया है। (2) सारणी 9 और 10 के नीचे चिह्नों के स्थान पर नये चिह्न दिए गए हैं। (3) सारणी 11 और 27 संशोधित की गई है।	1980-10-31
24.	IS : 8309–1976 बिजली रोधन केबिलों के एलुमिनियम चालकों के लिए संपीडन प्रकार के नलिकाकार अन्तिम सिरों की विशिष्टि	एस०ओ० 419 दिनांक 1980-02-23	संख्या 1 अक्तूबर 1980	(1) खंड 1.5 और 6 संशोधित किये गये हैं। (2) खंड 3 के स्थान पर नया खंड रखा गया है। (3) पृष्ठ 1 पर खंड 4.1 हटाया गया है। तथा तदनुसार बाद के खंडों की संख्यायें फिर से डाली गयी है। (4) पृष्ठ 3 पर सारणी 2 हटायी गयी है।	1980-10-31
25.	IS : 9243 (भाग 1)–1979 कलाई घड़ियों की परीक्षण पद्धतियाँ भाग 1 प्रति चुम्बकीय	—	संख्या 1 अक्तूबर 1980	पृष्ठ 2, व्याख्यात्मक टिप्पणी, पंक्ति 6–"नार्मेज स्टैंडर्डाइजिंग फार बंड" के स्थान पर "1" एसोसिएशन स्विस डी नार्मलाइजेशन रखा गया है।	1980-10-31

इन संशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 तथा अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, पटना और त्रिवेन्द्रम स्थित इसके शाखा कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

[सं० सी एम डी/13 : 5]

New Delhi, 1984-03-09

S.O. 1057. -In pursuance of regulation 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the Schedule hereto annexed have been issued under the power conferred by the sub-regulation (1) of Regulation 3 of the said Regulations:

SCHEDULE

S.No.	No. and title of the Indian Standard amended	No. and Date of Gazette Notification in which the establishment of the Indian Standard was notified	No. and Date of the Amendment	Brief particulars of the Amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 26-1979 Specification for tin ingot (third revision)	—	No. 1 Oct 1980	Table 1 has been amended	1980-10-31
2.	IS : 276-1978 Specification for austenitic manganese steel castings (third revision)	—	No. 1 Oct 1980	Clause 10 1 has been amended	1980-10-31
3.	IS : 415-1979 Specification for shuttlecocks (second revision)	—	No. 1 Oct 1980	(i) Page 4, clause 4.2, second sentence— Deleted (ii) A new note has been added after Fig. 1	1980-10-31
4.	IS : 549-1974 Specification for split pins (second revision)	S.D. 988 dated 1976-03-06	No. 2 Ot 1980	Clause 10 has been substituted by a new one	1980-10-31
5.	IS : 898-1964 Specification for coir fibre (revised)	S.O. 1152 dated 1965-04-10	No. 1 Oct 1980	(i) Title at first cover page, pages 1 and 3 has been substituted by a new one (ii) Clause 1.1 has been substituted by a new one	1980-10-31
6.	IS : 1063-1963 Specification for 14-mm sparking plugs (revised)	S.O. 2370 dated 1963-08-24	No. 3 Oct 1980	Fig. 2 has been amended	1980-10-31
7.	IS : 1081-1960 Code of practice for fixing and glazing of metal (steel and aluminium) doors, windows and ventilators	S.O. 2960 dated 1960-12-10	No. 1 Oct 1980	(i) Clauses 3.1 and 10.5 have been substituted by new ones (ii) (Page 5 of reprints, foot-note)–Deleted (iii) Clause 6.12 has been amended (iv) Clause 10.6 has been deleted and the subsequent clauses renumbered accordingly	1980-10-31
8.	IS : 1786-1979 Specification for cold-worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement (second revision)	—	*No. 1 Oct 1980	(i) Page 4, clause 0.4.1 - Deleted (ii) Clauses 3.4, 3.4.1, Fig. 1 and informal table of calause 6.1 have been amended (iii) Clauses 3.4.2, 7.2.1 and Appendix A have been substituted by new ones (iv) New notes have been added after clauses 1.1, 3.2 and 3.4.12 (v) Clause 3.4.0 has been added after clause 3.4	1980-10-31
9.	IS : 1832-1978 Specification for malathion, technical (first revision)	—	No. 2 Oct 1980	Clause A-1.3.1 and formula of clause A-1.6.2 have been substituted by new ones	1980-10-31
10.	IS : 2577-1974 Specification for cartriage fuse-links for automobiles (first revision)	S.O. 2858 dated 1976-08-07	No. 1 Oct 1980	Table 1 has been amended	1980-10-31
11.	IS : 2954-1964 General requirements for optical instruments	S.O. 4120 dated 1964-12-05	No. 1 Oct 1980	Clause 4.2.6 has been amended	1980-10-31

*For purposes of ISI Certification Marks Scheme; this amendment shall come into force with effect from 1980-11-30.

1	2	3	4	5	6
12.	IS : 2974–(Part I)–1969 code of practice for design and construction of machin foundations : Part I Foundaions for reciprocating type machines (first revision)	S. 3740 dated 1971-10-09	No. 1 Oct 1980	(i) Clauses 4.2(b) and 6.1.2 (f) have been amended (ii) Clauses 5.7, 5.7.1, 5.7.1 1, 5.7.2, 5,7,2,1 and 7.1 have been substitute l by new ones. (iii) Foot-notes with '*' and '†' marks (page 6), with '*' mark (page 8), with '*', '†' and '‡' marks (page 10) and with '*' mark (page 11) have been substituted by new ones. (iv) Clause 2.11 has been added after clause 2.10	1980-10-31
13.	IS : 3444–1978 Specificotion for corrosion resistant alloy steel and nickel based castings for general applications (first revision)	—	No. 1 Oct 1980	Table 3 has been amended	1980-10-31
14.	IS : 3716-1978 Application guide for insulation co-ordination (first revision)	—	No. 1 Oct 1980	(i) Clauses 3.5.3, 4.3 and C-1 have been amended (ii) Caption of Fig: 2 has been substituted by a new one	1980-10-31
15.	IS : 4060-1978 Specification for flashers for direction indicators for automobiles (first revision)	—	No. 1 Oct 1980	Clause 5.3 has been amended	1980-10-31
16.	IS : 4648-1968 Guide for electrical layout in residential buildings	S.O. 3608 dated 1968-10-12	No. 1 Oct 1980	Page 11, clause 7.2, last sentence-Delete	1980-10-31
17.	IS : 5153-1969 Specification for proportional compasses-150, 200 and 300 mm	S.O. 4114 dated 1969-10-11	No. 1 Oct 1980	Clause 4.3.5 has been amended	1980-10-31
18.	IS : 5648-1970 Specification for o-anisidine	S.O. 5276 dated 1971-12-04	No. 1 Oct 1980	Table 1 has been amended	1980-10-31
19.	IS : 6793-1972 Specification for fumaric acid, food grade	S.O. 2015 dated 1975-06-28	No. 1 Oct 1980	(i) Clauses 2.2.1 and 2.2.2 have been substituted by new ones (ii) Clause 2 3.1 has been deleted	1980-10-31
20.	IS : 6821-1973 Methods for sampling non-threaded fasteners	S.O. 2557 dated 1975-08-09	No. 1 Oct 1980	(i) Clause 1 has been amended (ii) Page 6, Appendix A, informal table, Sl No. 1 to 9, under 'Rivets'-Delete and renumber the subsequent items accordingly	1980-10-31
21.	IS.: 7002-1972 Specification for prevailing torque type steel hexagon locknuts	S.O. 776 dated 1976-02-21	No. 1 Oct 1980	Clause 4 has been substituted by a new one	1980-10-31
22.	IS : 8019-1976 Specification for dental artificial stone	S.O. 1597 dated 1979-05-19	No. 1 Oct 1980	(i) Clause A-5.1 has been substituted by a new one (ii) Pages 7 and 9, clauses A-5.1.1, A-5.1.2, A-5.2 and A-5.2.1-Delete	1980-10-31
23.	IS : 8187-1976 Specification for D-type fuses	S.O. 98 dated 1980-01-12	No. 1 Oct 1980	(i) Page 3, clause 0.3, line 3-Substitute 'Table 31' for 'Table 1' (ii) Figures under table 9 any 10 have been substituted yb new ones (iii) Tables 11 and 27 have been amended	1980-10-31
24.	IS : 8309-1976 Specification for compression type tubular terminal ends for aluminium conductors of insulated cables	S.O. 419 dated 1980-02-23	No. 1 Oct 1980	(i) Clauses 1, 5, 6 have been amended (ii) Clause 3 has been substituted by a new one (iii) Page 1, clause 4.1-Delete and renumber the subsequent clauses accordingly (iv) Page 3, Table 2-Delete	1980-10-31

1	2	3	4	5	6
25.	IS : 9243 (Part I)-1979 Methods of test for wrist watches : Part I Antimagnetic	—	No. 1 Oct 1980	Page 2, Explanatory Note, line 6-Substitute "1 'Association Francaise De Normalisation" for "Norges Standardiserings for bund"	1980-10-31

Copies of these amendments are available with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also from its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras Patna and Trivandrum.

[No. CMD 13 : 5]

का०आ० 1058.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन मुहर) विनियम 1955 के विनियम के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियम (3) के उपविनियम (1) के अनुसार प्राप्त अधिकारों के अधीन यहां अनसूची में दिए गए भारतीय मानकों के संशोधन जारी किए गए हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानक की पद संख्या एवं शीर्षक	जिस राजपत्र में भारतीय मानक के निर्धारित होने की सूचना छपी थी उस की संख्या तिथि एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन का संक्षिप्त विवरण	संशोधन लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	IS : 10 (भाग III)-1974 प्लाईवुड की चाय की पेटियों की विशिष्टि भाग III तख्ते (चौथा पुनरीक्षण)	एस ओ 1597 दिनांक 1976-05-08	संख्या 2 जुलाई 1980	खंड 7.1 और 7.2 का संशोधन किया गया है	1980-07-31
2.	IS : 226-1975 संरचना इस्पात (सामान्य किस्म) की विशिष्टि (पांचवा पुनरीक्षण)	एस ओ 3239 दिनांक 1976-09-11	संख्या 4 जून 1980	सारणी 1 के अन्तर्गत टिप्पणी 3 के बाद एक नई टिप्पणी 1 जोड़ी गई है।	1980-06-30
3.	IS : 393-1975 मुहर लगाने के पैड की स्याही की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस ओ 3530 दिनांक 1977-11-19	संख्या 1 जुलाई 1980	खंड 5.1 के अन्तर्गत नई सामग्री जोड़ी गई है।	1980-07-31
4.	IS : 617-1975 सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए एलुमिनियम और एलुमिनियम मिश्र-धातु के इंगट और ढलाइयां (दूसरा पुनरीक्षण)	"	संख्या 2 जून 1980	सारणी 1 को संशोधित किया गया है	1980-06-30
5.	IS : 710-1976 जहाजी प्लाईवुड की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ 97 दिनांक 1980-01-12	संख्या 2 जुलाई 1980	सारणी 1 का संशोधन किया गया है	1980-07-31
6.	IS : 722 (भाग 7)-1969 ए सी बिजली के मीटरों की विशिष्टि भाग 7 पूर्ण विद्युत फैक्टर रेंज के लिए वोल्ट अपियर घंटा मापी	एस ओ 4114 दिनांक 1969-10-11	संख्या 1 जून 1980	1 खंड 2.0, 6.1, 6.2.1 और 8.1 का संशोधन किया गया है। 2. पाद टिप्पणियां चिन्ह वाली पृष्ठ 3, चिन्ह वाली पृष्ठ 5 एवं 6 के स्थान पर नई पाद टिप्पणियां दी गई है।	1980-06-30
7.	IS : 739-1977 सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए पिटवा एलुमिनियम और एलुमिनियम मिश्रधातु के तार की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस ओ 618 दिनांक 1980-03-15	संख्या 1 जुलाई 1980	सारणी 2 का संशोधन किया गया है।	1980-07-31
8	IS : 909-1975 भूमिगत दमकल नल (कलम वाल्व वाले) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस ओ 3530 दिनांक 1977-11-19	संख्या 4 जुलाई 1980	1. खंड 3.1 और 8.1 का संशोधन किया गया है। 2. पृष्ठ 8 की * चिह्न वाली पाद टिप्पणी के स्थान पर नई पाद टिप्पणी दी गई है।	1980-07-31
9.	IS : 933-1976 सुवाह्य रासायनिक अग्नि शामक झागदार की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	—	संख्या 9 4 जून 1980	1. खंड 4.1 की टिप्पणी के स्थान पर नई टिप्पणी दी गई है। 2. खंड 4.5.1 और 8.1 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं। 3 खंड 4.7 और 7.3 का संशोधन किया गया है।	1980-06-30

1	2	3	4	5	6
				4. पृष्ठ 4, खंड 4.9 (संशोधन संख्या 1 को भी देखें)—हटा दो 5. पृष्ठ, पाद टिप्पणियां '††', '§§' और 'III' चिह्नों वाली (संशोधन संख्या 1 को भी देखें)—हटा दें। 6. पृष्ठ II खंड 15.1 (जो) हटा दें और अनुवर्ती मदों को फिर से तदनुसार संख्या दें। 7. खंड 10.1 के बाद एक नई टिप्पणी जोड़ी गई है।	
10. IS : 1384—1977 तेल दाब वाली लालटेनों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	—	संख्या 2 जून 1980	खंड 7.2.1 को संशोधित किया गया है।		1980-06-30
11. IS : 1404-1970 जहाजों के पेटा और ढांचे पर लाल, चाकलेट अथवा काले व वांछित रंगों में ब्रुश से लगाने के जंग रोधी रंगरोगन की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एम ओ 3544 दिनांक 1971-09-25	संख्या 1 दिनांक	खंड बी-3.1.1 को संशोधित किया गया है।		1980-06-30
12. IS : 1554 (भाग 1)—1976 पी वी सी रोधित (भारी कार्य के) बिजली के केबलों की विशिष्टि भाग 1 1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए (दूसरा पुनरीक्षण)	एम ओ 415. दिनांक 1980-02-23	संख्या 2 जून 1980	1. खंड 1.3, 4.1, 7.1 और 16.2.1 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं। 2. खंड 8.2, 14.3, 1, 15 और 16 को संशोधित किया गया है। 3. पृष्ठ 9, खंड 15.1 (एच) —हटा दें और अनुवर्ती मदों को तदनुसार फिर संख्या दें। 4. खंड 16.1 और 16.2 के अन्तर्गत शीर्षकों के स्थान पर नए शीर्षक दिए गए हैं 5. सारणी 7 को संशोधित किया गया है। 6. खंड 0.5 को खंड 0.4 के बाद जोड़ा गया है और अनुवर्ती खंडों को तदनुसार फिर से संख्या दी गई है। 7. खंड 17.3 के बाद एक नई टिप्पणी जोड़ी गई है।	1980-06-30
13. IS : 1608—1972 इस्पात उत्पादों की तन्यता परीक्षण पद्धति (पहला पुनरीक्षण)	एम ओ 115 दिनांक 1975-01-11	संख्या 1 जून 1980	खंड 14.3.1 के बाद खंड 144 जोड़ा गया है।		1980-06-30
14. IS : 1678—1978 शिरोपरि विद्युत कर्षण एवं दूरसंचार लाईनों के लिए पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के खंभों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 जून 1980	खंड 7.9 को संशोधित किया गया है।		1980-06-30
15. IS : 1835—1976 रस्सों के लिए गोल इस्पात के तार की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एम ओ 3823 दिनांक 1979-11-24	संख्या 1 जून 1980	1. खण्ड 1.1 और ए-1 (सी) को संशोधित किया गया है 2. सारणी 1 को संशोधित किया गया है। 3 खण्ड 1.1 के बाद खण्ड 4 1.2 जोड़ा गया है		1980-06-30
16. IS : 1873—1961 वायुयानों के लिए विरलक, शीतरोधी के सैलुलोज नाईट्रेट से बने रोगन, लेप और लैकर की विशिष्टि	एम ओ 416 दिनांक 1962-02-11	संख्या 1 जून 1980	सारणी 1 और डी 3.1 को संशोधित किया गया है।		1980-06-30
17. IS : 1993—1974 शीत तनुकृत टिन प्लेट और शीत तनुकृत ब्लैक की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एम ओ 987 दिनांक 1976-03-06	संख्या 4 जून 1980	1. खंड 5.3.2 के बाद खंड 5.3.3 जोड़ा गया है और खंड 5.3.3 की संख्या बदले कर 5.3.4 दी गई है। 2. खंड ए 4.3 के बाद खंड ए 4.4 जोड़ा गया है।		1980-06-30
18. IS : 2163—1976 कारबाईड टिपवाले एक नोक वाले खराद उपकरणों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एम ओ 3822 दिनांक 1979-11-24	संख्या 1 जून 1980	सारणी 4 को संशोधित किया गया है।		1980-07-31

1	2	3	4	5	6
19.	IS : 2200—1973 क्षेतिज नकुवे और समायोज्य ऊंचाई की मेज वाली मिलिंग मशीन के लिए परीक्षण चार्ट	एस ओ 776 दिनांक 1976-02-21	संख्या 1 जुलाई 1980	क्रम संख्या 14 ज्यामितीय परीक्षणों के बाद नया परीक्षण जोड़ा गया है।	1980-07-31
20.	IS : 2379-1963—पाइपलाइनों की पहचान के लिए रंग संहिता	एस ओ 4120 दिनांक 1964-12-05	संख्या 2 जून 1980	खंड 1.1 के स्थान पर नया खंड दिया गया है।	1980-06-30
21.	IS : 2654—1977 तांबा एवं ताम्र मिश्रित धातु की नम्यता परीक्षण पद्धति (पहला पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 जून 1980	सारणी 1 को संशोधित किया गया है	1980-06-30
22.	IS : 2881—1978 तेल के कुएं की खुदाई और रसायनिक उद्योग के लिए बेराइटीज की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 जून 1980	खंड 0.4 (ए) को संशोधित किया गया है।	1980-07-31
23.	IS : 2911 (भाग 1)—1964 पाइलवार नींव के निर्माण एवं डिजाइन की रीति संहिता भाग 1 भारवाही कंक्रीट के पाइल	एस ओ 2673 दिनांक 1965-08-28	संख्या 3 जुलाई 1980	खंड ई-1..4.2 को संशोधित किया गया है।	1980-07-31
24.	IS : 3066—1965 गरम एस्फाल्ट मिश्रण संयंत्र की विशिष्टि	एस ओ 3059 दिनांक 1965-10-02	संख्या 1 जुलाई 1980	1. खंड 14.2.2 के बाद खंड 14.2.3 जोड़ा गया है, 2. पृष्ठ 9, पाद टिप्पणी—निम्नलिखित नयी पाद टिप्पणी अन्त में जोड़ ले, * भ्रमसूचक और अर्धस्व सूचक काउंटर वाली तेल मशीनों की विशिष्टि।	1980-07-31
25.	IS : 3118—1978 कोयला खानों में भूमिगत आयोग के लिए अग्नि सह कन्वेयर पट्टी की विशिष्टि (पुनरीक्षण पहला)	— —	संख्या 1 जुलाई 1980	खंड एफ4·2.1 को संशोधित किया गया है।	1980-07-31
26.	IS : 3365—1965 फर्श पालिश करने की मशीनों की विशिष्ट	एस ओ 1081 दिनांक 1966-04-09	संख्या 1 जुलाई 1980	खंड 5.5.1 की अनौपचारिक सारणी को संशोधित किया गया है।	1980-07-31
27.	IS : 3657—1978 एक्सरे बिम्ब गुणता सूचकों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 जून 1980	1. पृष्ठ 12 की आकृति 2 के स्थान पर नई आकृति दी गई है। 2. पृष्ठ 14 की आकृति 3 बी को संशोधित किया किया गया है।	1980-07-31
28.	IS : 3766—1977 धातु परीक्षण के लिए लोलक संघात परीक्षण मशीनों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ 3416 दिनांक 1980-12-13	संख्या 1 जून 1980	1. खंड 3.3.4 को संशोधित किया गया है। किया गया है। 2. खंड 3.4.2.2 के स्थान पर नया खंड दिया गया है।	1980-06-30
29.	IS : 3930—1979 ज्वाला एवं प्रेरण कठोरीकरण इस्पातों की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 जुलाई 1980	सारणी 2 के स्थान पर नई सारणी दी गई हैं। गई हैं।	1980-07-31
30.	IS : 4184—1967 इस्पात के पहियेदार ठेलों (दो पहियों वाले) की विशिष्ट	एस ओ 683 दिनांक 1968-02-24	संख्या 1 फरवरी 1980	1. खंड 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 3.4, 8.2 और और 10.1 को संशोधित किया गया है 2. पृष्ठ 5 पर विद्यमान पाद टिप्पणी के स्थान पर नई पाद टिप्पणी दी गई है। 3. पृष्ठ 8 पर '*' एवं '‡' चिन्हों वाली पाद टिप्पणियों के स्थान पर नई पाद टिप्पणियां दी गई है।	1980-02-29
31.	IS : 4236—1977 श्रृंगार प्रसाधन उद्योग के लिए ग्लिसरील मोनोस्टेट की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ 1606 दिनांक 1980-06-14	संख्या 1 जुलाई 1980	1. सारणी 1 को संशोधित किया गया है। 2. पृष्ठ 5 खंड 3.2 पंक्ति 2—जोड़े 'धारक के निवल भार के बाद सामग्री का साबुनीकरण मान	1980-07-31

1	2	3	4	5	6
32	IS : 4351—1978 इस्पात के दरवाजे चौखटों की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	एमओ 97 दिनांक 1980-01-12	संख्या 1 जुलाई 1980	खंड 7.2(ए) को संशोधित किया गया है।	1980-07-31
33.	IS : 4377—1967 ध्वनि भरने और पुनः बजाने के लिए चुम्बकीय टेप की सामान्य अपेक्षाएं	एमओ 1719 दिनांक 1960-5-18	संख्या 2 जून 1980	खंड 9.1 के स्थान पर नया खंड दिया गया।	1980-06-30
34.	IS : 4570—1968 स्फटिक होल्डरों की विशिष्टि	एमओ 3453 दिनांक 1968-09-28	संख्या 3 जुलाई 1980	(i) खंड 2.0 को संशोधित किया गया है। (ii) पृष्ठ 2 पर ‡ चिह्न वाली पाद टिप्पणी के स्थान पर नई पाद टिप्पनी दी गई है।	1980-07-31
35.	IS : 4989—1974 आग बुझाने के लिए मशीनी झाग पैदा करने के लिए झाग मिश्र की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एमओ 987 दिनांक 1976-03-06	संख्या 5 अप्रैल 1980	(i) खंड आर-1.1.3 को संशोधित किया गया है। (ii) खंड जी-1.1 के बाद एक नई टिप्पणी जोड़ी गई है।	1980-04-30
36.	IS : 5411 (भाग II)—1972 प्लास्टिक इमशलन रंग रोगन की विशिष्टि : भाग 2 बहिरंग उपयोग के लिए	एमओ 3069 दिनांक 1975-09-13	संख्या 1 जुलाई 1980	(i) खंड डी 3.1.1 और एफ-1.1 को संशोधित किया गया है। (ii) खंड एफ-1.1 और पृष्ठ 12 पर* चिह्न वाली पाद टिप्पणी के स्थान पर नई टिप्पणी दी गई है।	1980-07-31
37.	IS : 5517—1978 मृदुकरण एवं कठोरीकरण के लिए इस्पात की विशिष्टि	—	संख्या 1 जुलाई 1980	खंड 4 को संशोधित किया गया है	1980-07-31
38.	IS : 5518—1979 पात गढ़ाई में प्रयुक्त डाईब्लॉकों के इस्पात की विशिष्टि	—	संख्या 1 जून 1980	सारणी 2 को संशोधित किया गया है	1980-06-30
39.	IS : 5681—1970 सामान्य मौसम विज्ञान संबंधी तरल भरे शीशे की तापमयी विशिष्ट	एमओ 5032 दिनांक 1971-11-06	संख्या 2 जुलाई 1980	(i) खंड 4.5.2 के स्थान पर नया खंड दिया गया है (ii) सारणी 1 को संशोधित किया गया है (iii) आकृति 4, 5, 6 और 7 को संशोधित किया गया है।	1980-07-31
40.	IS : 5750—1970 सिगुमाइडदर्शी की विशिष्टि	एमओ 1555 दिनांक 1972-06-24	संख्या 1 जनवरी 1980	पृष्ठ 8, खंड 6.3, पंक्ति 2-इन शब्दों को हटा दें 'पंपिंग किया'	1980-01-31
41	IS : 5790—1970 घरेलू बिजली के खाना पकाने के ओवन	एमओ 1635 दिनांक 1972-20-08	संख्या 3 मार्च 1980	खंड 5.6.3 और 9.3.6 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं।	1980-03-31
42.	IS : 5823—1970 खाना बनाने के मेजों की विशिष्टि	एमओ 1277 दिनांक 1972-05-27	संख्या 3 जुलाई 1980	(1) खंड 5.1.5.2, और 5.4 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं। (2) खंड 6.6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 को खंड 5.8 के बाद जोड़ा गया है और अनुवर्ती खंडों को तदनुसार फिर से संख्या दी गई है।	1980-07-31
43.	IS : 5890—1970 हल्के कार्य के चलते फिरते गरम ऐस्फाल्ट मिश्र गरमाने के संयंत्र की विशिष्टि	एमओ 3318 दिनांक 1972-10-21	संख्या 1 जुलाई 1980	(1) खंड 8.1.2 को खंड 8.1.1 के बाद जोड़ा गया है। (2) *चिह्न वाली पाद टिप्पणी को पृष्ठ 6 पर जोड़ा गया है।	1980-07-31
44.	IS : 6112—1971 दो सिरों वाले योनि स्पेकुलम (सिम के नमूने के) की विशिष्टि	एमओ 3056 दिनांक 1973-10-27	संख्या 1 जुलाई 1980	खंड 6.3 के स्थान पर नया खंड दिया गया है।	1980-07-31
45.	IS : 6512 : 1972 ठोस घनत्व बांध की डिजाइन संबंधी कसौटियां	—	संख्या 1 जून 1980	खंड 5, 12.2(बी) को संशोधित किया गया है।	1980-06-31
46.	IS : 6589—1972 बोजेमन नमूने की गर्भाशय की मरहम पट्टी करने की फोर्सेप्स की विशिष्टि	एमओ 115 दिनांक 1975-01-11	संख्या 1 जुलाई 1980	खंड 6.2 के स्थान पर नया खंड दिया गया है।	1980-07-31

1	2	3	4	5	6
47.	IS : 6959—1973 चपटी और मे वक्र भ्रूण अपनयन की कैंचियों की विशिष्टि	एसओ 2557 दिनांक 1975-08-09	संख्या 1 जुलाई 1980	खंड 6, 3 के स्थान पर नया खंड दिया गया है।	1980-07-31
48.	IS : 6960—1973 स्त्रियों की धातु की मूत्र नलिका की विशिष्टि	एसओ 2557 दिनांक 1975-08-09	संख्या 1 जुलाई 1970	खंड 5, 1 के स्थान पर नया खंड दिया गया है।	1980-07-31
49	IS : 6986—1973 कपालीय एवं शीर्ष संबंधी संयुक्त फॉर्सेप्स की विशिष्टि	एसओ 2081 दिनांक 1975-07-05	संख्या 1 जुलाई 1980	खंड 6, 1 के स्थान पर नया खंड दिया गया है	1980-07-31
50.	IS : 7076—1973 धातु की पुम्न टेक की विशिष्टि	एसओ 2669 दिनांक 1975-08-16	संख्या 3 जुलाई 1980	(1) खंड 5, 1, 5, 2 और 5, 3 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं। (2) और चिह्नों वाली पाद टिप्पणियों के स्थान पर नई पाद टिप्पणियां दी गई हैं। (3) खंड 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 को खंड 5.4 के बाद जोड़ा गया है तथा अनुवर्ती खंडों को तदनुसार फिर से संख्या दी गई है। (4) **चिह्न वाली पाद टिप्पणी को π चिह्न वाली पाद टिप्पणी के बाद जोड़ा गया है।	1980-07-31
51.	IS : 7081—1973 हस्पताल के प्रयोग के लिए घूमने वाले स्टूल की विशिष्टि	—	संख्या 2 जुलाई 1980	खंड 4, 3 को संशोधित किया गया है।	1980-07-31
52.	IS : 7181—1974 पानी गैस और मलजल के लिए के लिए क्षैतिज ढलवां लोहे के दोहरी कोरदार पाइपों की विशिष्टि	एसओ 988 दिनांक 1976-03-06	संख्या 2 जुलाई 1980	(1) सारणी 4 के अंतर्गत एक नई टिप्पणी जोड़ी गई है। (2) खंड 8.4 के बाद खंड 8.5 और 8.6 खंड जोड़े गए हैं।	1980 07-31
53.	IS : 7432 —1974 भौनी नमूने की मांसपेशी संबंधी शिकंजे की विशिष्टि	एसओ 1232 दिनांक 1976-04-03	संख्या 1 जुलाई 1980	खंड 6.2 के स्थान पर नया खंड दिया गया है।	1980-07-31
54.	IS : 7793—1975 अंतर्दाही इंजन के पिस्टनों के लिए एलुमिनियम मिश्रधातु की विशिष्टि	एसओ 2240 दिनांक 1978-08-05	संख्या 1 जुलाई 1980	(1) खंड 3.1, 6.2 और 7.2 के स्थान पर नए खंड दिए गए है। (2) सारणी 1 को संशोधित किया गया है।	1980 07-31
55.	IS : 7821—1975 3 से 24 मिमी तक सांकेतिक व्यास की लम्बी नली वाली मशीन टोटियों की विशिष्टि	एसओ 1596 दिनांक 1979-05-19	संख्या 3 जून 1980	खंड 3.1 और 3.2 के अन्तर्गत अनौपचारिक सारणी को संशोधित किया गया है।	1980-06-30
56.	IS : 8122 (भाग 1)—1976 संयुक्त फसल काटने व गहाने की संयुक्त कम्बाइन परीक्षण संहिता भाग I परिभाषाएं	एसओ 3822 1979-11-24	संख्या 1 जुलाई 1980	खंड 4.2.1.1 और 4.2.7.5 (सी) को संशोधित किया गया है।	1980-07-31
57.	IS : 8149—1976 युग्म कार्बन डाइआक्साइड अग्नि शामक (ट्राली पर रखे) की कार्यात्मक अपेक्षाएं	एसओ 3822 दिनांक 1979-11-24	संख्या 1 जुलाई 1980	(1) खंड 2.2 और 5.2 को संशोधित किया गया है। (2) पृष्ठ 4 पर* चिह्न वाली और पृष्ठ 8 पर एवं '†' एवं '‡' चिह्नों वाली पाद टिप्पणियों के स्थान पर नई पाद टिप्पणियां दी गई हैं।	1980-07-31
58.	IS : 8306—1976 मोर्स गावदुम नने वाली कारबाइड टिप वाली ट्विस्ट ड्रिल की विशिष्टि	एसओ 417 दिनांक 1980-02-23	संख्या 1 जुलाई 1980	सारणी 1 की वर्तमान आकृति के स्थान पर नई आकृति की गई है।	1980-07-31
59.	IS : 8617—1977 मोर्स गावदुम और चाभी वाले छोटे खंडों की मिलिंग वाले आर्बर की विशिष्टि	एसओ 3170 दिनांक 1980-12-15	संख्या 1 जून 1980	सारणी 1 ए को संशोधित किया गया है।	1980-06-30
60.	IS : 8769—1978 राख एवं सल्फेटेड राख के निर्धारण की पद्धतियां	एसओ 3416 दिनांक 1980-12-13	संख्या 1 जुलाई 1980	खंड 5.2 को संशोधित किया गया है।	1980-07-31
61.	IS : 8920—1978 पकी मिट्टी की टाइलों की नमूने लेने की पद्धतियां	—	संख्या 1 जुलाई 1980	सारणी 1 और खंड 5.2.1 को संशोधित किया गया है।	1980-07-31

1	2	3		5	6
62.	IS : 9019-1979 शक्ति चालित थ्रेशरों के संस्थापन, प्रचालन और सेहतियाती रखरखाव की रीति संहिता	—	संख्या 1 जून 1980	खंड 0.3 एवं 9.1 को संशोधित किया गया है।	1980-06-30
63.	IS : 9020—1979 शक्ति चालित थ्रेशरों से संबंधित सामान्य एवं सुरक्षा अपेक्षाएं	—	संख्या 1 जुलाई 1980	खंड 0.3, 6.1 एवं 7.2 को संशोधित किया गया है	1980-07-31
64.	IS. 9129—1979 शक्ति चालित थ्रेशरों की सुरक्षित भरण प्रणाली की तकनीकी अपेक्षाएं	—	संख्या 1 जून 1980	सारणी 1 के स्थान पर नई सारणी दी गई है	1980-06-30

उन संशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली एवं इसके शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, कानपुर, पटना एवं त्रिवेंद्रम से भी प्राप्त की जा सकती है।

[सं० सीएमडी/13:5]

S.O. 1058.—In pursuance of regulation 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Instiution, hereby, notifies that amendment(s) to the Indian Standard (s) given in the schedule hereto annexed have been issued under the powers conferred by the sub-regulation (1) of Regulation 3 of the said Regulations.

SCHEDULE

S.No.	No. and title of the Indian Standard amended	No. and Date of Gazette Notification in which the establishment of the Indian Standard was notified	No. and Date of the Amendment	Brief particulars of the Amendment	Date from which the amendment shall have effect
1	2	3	4	5	6
1.	IS : 10 (Part III)–1974 Specification for plywood tea-chest : Part III Battens (fourth revision)	S.O. 1597 dated 1976–05–08	No. 2 Jul 1980	Clauses 7.1 and 7.2 have been amended	1980–07–31
2.	IS : 226–1975 Specification for structural steel (standard quality) (fifth revision)	S.O. 3279 dated 1976–09–11	No. 4 Jun 1980	A new note 4 has been added under table 1 after note 3	1980–06–30
3.	IS : 393–1975 Specification for ink, stamp-pad (second revision)	S.O. 3530 dated 1977–11–19	No. 1 Jul 1980	New matter has been added under clause 5.1	1980–07–31
4.	IS : 617–1975 Specification for aluminium and aluminium alloy ingots and castings for general engineering purposes (second revision)	-do-	No. 2 Jun 1980	Table 1 has been amended	1980–06–30
5.	IS : 710–1976 Specification for marine plywood (first revision)	S.O. 97 dated 1980–01–12	No. 2 Jul 1980	Table 1 has been amended	1980–07–31
6.	IS : 722 (Part VII)–1969 Specification for AC electricity meters : Part VII Volt-ampere-hour meters for full power factor range	S.O. 4114 dated 1969–10–11	No. 1 Jun 1980	(i) Clauses 2.0, 6.1, 6.2.1 and 8.1 have been amended (ii) Foot notes with '§' mark at page 3, with '†' marks at pages 5 and 6 have been substituted by new ones	1980–06–30
7.	IS : 739–1977 Specification for wrought aluminium and aluminium alloy wire for general engineering purpose (second revision)	S.O. 618 dated 1980–03–15	No. 1 Jul 1980	Table 2 has been amended	1980–07– 31

1	2	3	4	5	6
8.	IS : 909–1975 Specification for underground fire hydrant, sluice-valve type (second revision)	S.O. 3530 dated 1977–11–19	No. 4 Jul 1980	(i) Clauses 3.1 and 8.1 have been amended (ii) Foot-note with '*' mark at page 8 has been substituted by a new one	1980–07–31
9.	IS : 933–1976 Specification for portable chemical fire extinguisher, foam type (second revision)	—	No. 4 Jun 1980	(i) Note under clause 4.1 has been substituted by a new one (ii) Clauses 4.5.1 and 8.1 have been substituted by new ones (iii) Clauses 4.7 and 7.3 have been amended (iv) Page 4, clause 4.9 (see also amendment No. 1)—Delete (v) Page 4, foot-notes with '‡‡' '§§' and '‖‖' marks (see also Amendment No. 1)—Delete (vi) Page 11, clause 15.1(g)—Delete and renumber the subsequent items accordingly (vii) A new note has been added after clause 10.1	1980–06–30
10.	IS : 1384–1977 Specification for oil pressure lanterns (second revision)	—	No. 2 Jun 1980	Clause 7.2.1 has been amended	1980–06–30
11.	IS : 1404–1970 Specification for anti-corrosive paint, brushing, for ships' bottoms and hulls, red, chocolate or black, as required (first revision)	S.O. 3544 dated 1971–09–25	No. 1 Jun 1980	Clause B-3.1.1 has been amended	1980–06–30
12.	IS : 1554 (Part I)–1976 Specification for PVC insulated (heavy duty) electric cables: Part I For working voltages up to and including 1100 V (Second revision)	S.O. 415 dated 1980–02–23	No. 2 Jun 1980	(i) Clauses 1.3, 4.1, 7.1 and 16.2.1 have been substituted by new ones (ii) Clauses 8.2, 14.3.1 15, and 16 have been amended (iii) Page 9, clause 15.1(h)–Delete and renumber the subsequent items accordingly (iv) Headings under clauses 16.1 and 16.2 have been substituted by new ones (v) Table 7 has been amended (vi) Clause 0.5 has been added after clause 0.4 and the subsequent clauses renumbered accordingly (vii) A new note has been added after Clause 17.3	1980–06–30
13.	IS : 1608–1972 Method for tensile testing of steel products (first revision)	S.O. 115 dated 1975–01–11	No. 1 Jun 1980	Clause 14.4 has been added after clause 14.3.1	1980–06–30
14.	IS : 1678–1978 Specification for prestressed concrete poles for overhead power, traction and telecommunication lines (first revision)	—	No. 1 Jun 1980	Clause 7.9(a) has been amended	1980–06–30
15.	IS : 1835–1976 Specification for round round steel wire for ropes (third revision)	S.O. 3823 dated 1979–11–24	No. 1 Jun 1980	(i) Clauses 1.1 and A-1(c) have been amended (ii) Table 1 has been amended (iii) Clause 1.2 has been added after clause 1.1	1980–06–30

1	2	3	4	5	6
16.	IS : 1873–1961 Specification for thinner, amichill for cellulose nitrate based paints, dopes and lacquers for aircrafts	S.O. 416 dated 1962-02-11	No. 1 Jun 1980	Table 1 and D-3.1 have been amended	1980-06-30
17.	IS : 1993–1974 Specification for cold-reduced tinplate and cold-reduced blackplate (first revision)	S.O. 987 dated 1976-03-06	No. 4 Jun 1980	(i) New clause 5.3.3 has been added after clause 5.3 2 and the subsequent clause 5.3.3 renumbered as clause 5.3.4 (ii) Clause A-4.4 has been added after clause A-4.3	1980-06-30
18	IS : 2163 -1976 Specification for carbide tipped single point turning tools (first revision)	S.O. 3822 dated 1979–11–24	No. 2 Jul 1980	Table 4 has been amended	1980–07–31
19.	IS : 2700–1973 Test chart for milling machines with table of variable height, with horizontal spindle (first revision)	S.O. 776 dated 1976–02–21	No. 2 Jul 1980	New test has been added after geomatrical tests Sl. No. 14	1980–07–31
20.	IS : 2379 1963 Colour code for the Identification of pipelines	S.O. 4120 dated 1964–12–05	No. 2 Jun 1980	Clause 1.1 has been substituted by a new one	1980–06–30
21.	IS : 2654–1977 Method for tensile testing of copper and copper alloys (first revision)	—	No. 1 Jun 1980	Table 1 has been amended	1980–06–30
22.	IS : 2881–1978 Specification for barytes for chemical industry and oil-well drilling (first revision)	—	No. 1 Jul 1980	Clause 0.4(a) has been amended	1980–07–31
23.	IS : 2911 (Part I)–1964 Code of practice for design and construction of pile foundation: Part I Load-bearing concrete piles	S.O. 2673 dated 1965-08-28	No. 3 Jul 1980	Clause E-1.4.2 has been amended	1980–07–31
24.	IS : 3066–1965 Specification for hot asphalt mixing plants	S.O. 3059 dated 1965–10–02	No. 1 Jul 1980	(i) Clause 14.2.3 has been added after clause 14.2.2 (ii) page 9, foot-note-Add the following new footnote at the end: '*Specification for self indicating and semiself indicating counter type weighing machines'	1980–07–31
25.	IS : 3181–1978 Specification for fire resistant conveyor belting for underground use in coal mines (first revision)	—	No. 1 Jul 1980	Clause F-4.4.1 has been amended	1980–07–31
26.	IS : 3365–1965 Specification for flood polishing machines	S.O. 1081 dated 1966–04–09	No. 1 Jul 1980	Informal table of clause 5.5.1 has been amended	1980–07–31
27.	IS : 3657–1978 Specification for radiographic image quality indicators (first revision)	—	No. 1 Jun 1980	(i) Fig. 2 at page 12 has been substituted by a new one (ii) Fig. 3 B at page 14 has been amended	1980–07–31
28.	IS : 3766–1977 Method for calibration of pendulum impact testing machines for testing metals (first revision,	S.O. 3416 dated 1980–12–13	No. 1 Jun 1980	(i) Clause 3.3.4 has been amended (ii) Clause 3.4.2.2 has been substituted by a new one	1980–06–30
29.	IS : 3930–1979 Specification for flame & induction hardening steels (first revision)	--	No. 1 Jul 1980	Table 2 has been substituted by a new one	1980–07–31
30.	IS : 4184-1967 Specification for steel wheelbarrows (with two wheels)	S.O. 683 dated 1968–02–24	No. 1 Feb 1980	(i) Clauses 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 3.4, 8.2 and 10.1 have been amended (ii) Existing foot-notes at page 4 have been substituted by new ones (iii) Foot notes with '*' and '‡' marks at page 8 have been substituted by new ones	1980–20–29

1	2	3	4	5	
31.	IS : 4236–1977 Specificetion for glyceryl monostearate for cosmetic industry (first revision)	S.O. 1606 dated 1966–06–14	No. 1 Jul 1980	(i) Table 1 has been amended (ii) Page 5, clause 3.2, line 2, add 'saponification value of the material; after 'the net mass in the container;'	1980–07–31
32.	I : 4351–1976 Specification for steel door frames (first revision)	S.O. 97 dated 1980–01–12	No. 1 Jul 1980	Clause 7.2(a) has been amended	1980–07–31
33.	IS : 4377–1967 General requirements for magnetic tapes for sound recording and reproduction	S.O. 1719 dated 1968–05–18	No. 2 Jun 1980	Clause 9.1 has been substituted by a new one	1980–06–30
34.	IS : 4570–1968 Specification for crystal holders	S.O. 3453 dated 1968–09–28	No. 3 Jul 1980	(i) Clause 2.0 has been amended (ii) Foot-noto with '‡' at page 2 has been substituted by a new one	1980–07–31
35.	IS : 4989–1974 Specification for foam compound for producing mechanical foam for fire fighting (first revision)	S.O. 987 dated 1976–03–06	N . 5 Apr 1980	(i) Clause R-1.1.3 has been amende l (ii) A new note has been added after clause G-1.1	1980–04–31
36.	IS : 5411 (Part II)—1972 Specification for plastic emulsion paint: Part II For exterior use	S.O. 3069 dated 1975–09–13	No. 1 Jul 1980	(i) Clauses D-3.1 & F-1.1 have been amended (ii) Clause F-1.1 and footnoto with '*' mark at page 12 have been substituted by new ones	1980–07–31
37.	IS : 5517–1978 Specification for steels for hardening and tempering (first revision)	—	No. 1 Jul 1980	Table 4 has been amended	1980–07–31
38.	IS : 5518–1979 Specification for steels for die blocks for drop forging (first revision)	—	No. 1 Jun 1980	Table 2 has been amended	1980–06–30
39.	IS : 5681–1970 Specification for general meteorological thermometers, liquid-in-glass	S.O. 5032 dated 1971–11–06	No. 2 Jul 1980	(i) Clause 4.5.2 has been substituted by a new one (ii) Table 1 hat been amended (iii) Fig 4, 5, 6 and 7 have been amended	1980–07–31
40.	IS : 5750–1970 Specification for sigmoidoscope	S.O. 1555 dated 1972–06–24	No. 1 Jan 1980	Page 8, clause 6.3, line -Delete the words 'pumping action'.	1980–01–31
41.	IS : 5790–1970 Specification for domestic electric cooking ovens	S.O. 1635 dated 1972–07–08	No. 3 Mar 1980	Clauses 5.6.3 and 9.3.6 have been substituted by new ones	1980–03–31
42.	IS : 5823–1970 Specification for dinning tables	S.O. 1277 dated 1972–05–27	No. 3 Jul 1980	(i) Clauses 5.1, 5.2 and 5.4 have been substituted by new ones (ii) Clauses 6.6.1, 6.2, 6.3, 6.4 and 6.5 have been added after clause 5.8 and the subsequent clauses renumbered accordingly	1980–07–31
43.	IS : 5890–1970 Specification for mobile hot mix asphalt plant, light duty	S.O. 3318 dated 1972–10–21	No. 1 Jul 1980	(i) Clause 8.1.2 has been added after clause 8.1.1 (ii) Foot-note with '*' mark has been added at page 6	1980–07–31
44.	IS : 6112–1971 Specification for speculum vaginal, double ended (SIM's Pattern)	S.O. 3056 dated 1973–10–27	No. 1 Jul 1980	Clause 6.3 has been substituted by a new one	1980–07–31
45.	I : 6512–1972 Criteria for design of solid gravity dams	—	No. 1 Jul 1980	Clause 5.12.2.2(b) has been amended	1980–06–30
46.	IS : 6589–1972 Specification for forceps, uterine, dressing, Bozemann's pattern	S.O. 115 dated 1975–01–11	No. 1 Jul 1980	Clause 6.2 has been substituted by a new one	1980–07–31
47.	IS : 6959–1973 Specification for scissors, embryotomy, curved on flat	S.O. 2557 dated 1975–08–09	No. 1 Jul 1980	Clause 6.3 has been substituted by a new one	1980–07–31
48.	IS : 6960–1973 Specification for catheters, metal, female	S.O. 2557 dated 1975–08–09	No. 1 Jul 1980	Clause 5.1 has been substituted by a new	1980–07–31

1	2	3	4	5	0
49.	IS : 6986–1973 Specification for forceps, cranioclast and cephalotribe combined	S.O. 2081 dated 1975–07–05	No. 1 Jul 1980	Clause 6.1 has been substituted by a new one	1980–07–31
50.	IS : 7076–1973 Specification for metal book ends	S.O. 2269 dated 1975–08–16	No. 3 Jul 1980	(i) Clauses 5.1, 5.2 and 5.3 have been substituted by new ones (ii) Foot-notes with '§' and '‖' marks have been substituted by new ones (iii) Clauses 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 and 6.5 have been added after clause 5.4 and the subsequent clauses renumbered accordingly (iv) Foot-note with '**' mark has been added after foot-not with 'π' mark	1980–07–31
51.	IS : 7081–1973 Specification for stool, revolving for hospital use	—	No. 2 Jul 1980	Clause 4.3 has been amended	1980–07–31
52.	IS : 7181–1974 Specification for horizontally cast iron double flanged pipes for water, gas and sewage	S.O. 988 dated 1976–03–06	No. 2 Jul 1980	(i) A new note has been added under table 4 (ii) Clauses 8.5 and 8.6 have been added after clause 8.4	1980–07–31
53.	IS : 7432–1974 Specification for clamp, myomectomy, Bonney's pattern	S.O. 1232 dated 1976–04–03	No. 1 Jul 1980	Clause 6.2 has eeeen substituted by a new one	1980–07–31
54.	IS : 7793–1975 Specification for aluminium alloys for I.C. engine pistons	S.O. 2240 dated 1978–08–05	No. 1 Jul 1980	(i) Clauses 3.1, 6.2 and 7.2 have been substituted by new ones (ii) Table 1 has been amended	1980–00–31
55.	IS : 7821–1975 Specification for long shank machine taps with nominal diameter from 3 to 24 mm	S.O. 1596 dated 1979–05–19	No. 3 Jun 1980	Informal table under clauses 3.1 and 3.2 have been amended	1980–06–30
56.	IS : 8122 (Part I) 1976 Test code for combine harvester-thresher: Part I Terminology	S.O. 3822 dated 1979–11–24	No. 1 Jul 1980	Clauses 4.2.1.1 and 4.2.7.5 (c) have been amended	1980–07–31
57.	IS : 8149–1976 Functional requirements for twin CO_2 fire extinguisher (trolley mounted)	S.O. 3822 dated 1979–11–24	No. 1 Jul 1980	(i) Clauses 2.2 and 5.2 have been amended (ii) Foot-notes with '*' mark at page 4, with '†' and '‡' marks at page 8 have been substituted by new ones	1980–07–31
58.	IS : 8306-1976 Specification for carbide tipped twist drills, morse taper shank	S.O. 417 dated 1980–02 23	No. 1 Jul 1980	Existing figure of Table 1 has been substituted by a new one	1980-07-31
59.	IS : 8617–1977 Specification for stub milling arbours with morse tapper and with key	S.O. 3170 dated 1980-11–15	No. 1 Jun 1980	Table 1A has been amended	1980–06–30
60.	IS : 8769–1978 Methods of determination of ash and sulphated ash	S.O. 3416 dated 1980–12–13	No. 1 Jul 1980	Clause 5.2 has been amended	1980–07–31
61.	IS : 8920–1978 Methods for sampling of burnt clay tiles		No. 1 Jul 1980	Table 1 and clause 5.2.1 a have been amended	1980–07–31
62.	IS : 9019–1979 Code of practice for installation, operation and preventive maintenance of power threshers		No. 1 Jun 1980	Clause 0.3 and 9.1 have been amended	1980–06–31
63.	I : 9020–1979 General and safety requirements for power threshers		No. 1 Jul 1980	Clauses 0.3, 6.1 and 7.2 have been amended	1980–07–31
64.	I : 9129–1979 Technical requirements for safe feeding systems for power threshers		No. 1 Jun 1980	Tabel 1 has been substituted by a new one	1980-06–30

Copies of these amendments are available with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also from its branch offices at Ahmedabad, Bangalore Bhopal, Bhubaneshwar, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13 : 51

का० आ० 1059.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के नियम 3 के उपनियम 2 तथा विनियम 3 के उपविनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 1980-11-30 को निर्धारित किए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं०	निर्धारित भारतीय मानक की पद संख्या एवं शीर्षक	नए भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक या मानकों, यदि कोई है, की पद संख्या एवं शीर्षक	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	*IS : 320-1980 उच्च तनन की पीतल की छड़ें एवं सैक्शन (गढ़ाई भण्डार के अतिरिक्त) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 320-1962 उच्च तनन की पीतल की छड़े एवं सैक्शन की विशिष्ट (पुनरीक्षित)	*भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना हेतु IS : 320-1980 -1981-03-01 से लागू होगा।
2.	IS : 444-1980 रबड़ के पानी के नल की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	IS : 444-1968 बुने कपड़े से प्रबलित रबड़ के पानी के नल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	—
3.	IS : 1072-1980 पत्ती चेन कलविस और गरारी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1072-1967 पत्ती चेन की विशिष्टि	—
4.	IS : 1145-1980 मोटर-साइकिल, आटोरिक्शा और सामान वाहनों की सीसा अम्ल संग्राही बैटरियों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1145-1962 मोटर-साइकिल, आटो-रिक्शा और सामान वाहनों के लिये सीसा अम्ल संग्राही बैटरियों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	—
5.	IS : 1367 (भाग II)-1979 इस्पात की चूड़ीदार बंधों की तकनीकी पूर्ति शर्तें : भाग-II उत्पाद ग्रेड एवं छूटें (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1367-1967 चूड़ीदार बंधों की तकनीकी पूर्ति शर्तें (पहला पुनरीक्षण)	—
6.	IS : 1367 (भाग 3)-1979 इस्पात की चूड़ीदार बंधों तकनीकी पूर्ति शर्तें भाग-3 पूरे भार सहित चटखनियां, पेंच एवं गुल्मेखों के यान्त्रिक गुणधर्म और परीक्षण पद्धतियां (दूसरा पुनरीक्षण)	—वही—	—
	IS : 1380-1980 निशान अंगूठा लगाने की स्याही की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1380-1959 निशान अंगूठा लगाने की काली स्याही की विशिष्टि	—
8.	IS : 1440 (भाग 96)-1980 पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की परीक्षण पद्धतियां भाग 96 पानी की उपस्थिति में माप टरबाइन तेल की जंग रोधी विशेषताएं	—	—
9.	IS : 1574-1980 कांच की लोहने की बोतलों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1574-1960 कांच की लोहने की बोतलें	—
10.	IS : 1823-1980 दरवाजे के लिए फर्श में लगे अवरोधकों की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	IS : 1823-1974 दरवाजे के लिए फर्श में लगे अवरोधकों की विशिष्टि	—

(1)	(2)	(3)	(4)
11	IS 1985 (भाग 1)–1980 विद्युत लेपन के लिए लोहे एवं इस्पात को तैयार करने की अनुशंसित रीति भाग-I उच्च कार्बन इस्पात (पहला पुनरीक्षण)	IS 1985–1962 विद्युत लेपन के लिए पूर्व संसाधित इस्पात, ताम्र एवं ताम्र आधारित मिश्र धातु, जस्ता एवं जस्ता आधारित मिश्र धातु की रीति संहिता	—
12	IS : 1985 (भाग 2)–1980 विद्युत लेपन के लिए लोहे एवं इस्पात तैयार करने की सिफारिशी रीति भाग-2 निम्न कार्बन इस्पात (दूसरा पुनरीक्षण)	—वही—	—
13.	IS : 1985 (भाग 3)–1980 विद्युत लेपन के लिए लोहे एवं इस्पात तैयार करने की सिफारिशी रीति भाग-3 लोहे की ढलाई (पहला पुनरीक्षण)	—वही—	—
14	IS : 2516 (भाग 3)अनुभाग 2 1980 परिपथ विच्छेदकों की विशिष्टि : भाग-3 नमूना एवं बनावट अनुभाग-2 1000 वीएसी की वोल्टता से अधिक के लिए	(1) IS : (2516 भाग 1/अनुभाग 3)–1972 प्रत्यावर्ती धारा परिपथ विच्छेदकों की विशिष्ट भाग I अपेक्षाएं : अनुभाग 3 II किलो से अधिक उच्च वोल्टता के लिए (2) IS : 2516 (भाग-2/अनुभाग 2)-1965 प्रत्यावर्ती धारा परिपथ विच्छेदकों की विशिष्टि भाग 2 परीक्षण अनुभाग 2 1000 से अधिक और 11000 वोल्ट तक की वोल्टता के लिए	—
15	IS : 2596–1980 खनिकों की टोपी की बत्तियों के लिए बल्बों (बत्तियों) की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2596–1965 खनिकों की केप-बत्तियों के लिए बल्बों (बत्तियों) की विशिष्टि	*भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह योजन हेतु IS : 2596–1980 -1981-05-15 से लागू होगा।
16.	IS : 2683–1980 इमारती लकड़ी के संसेचन संयंत्र लगाने की संदर्शिका (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 2683–1966 इमारती लकड़ी के संसेचन संयंत्र लगाने की संदर्शिका (पहला पुनरीक्षण)	—
17.	IS : 2884–1979 शुष्क एवं परतदार मोटे सूती बम्बई डक की विशिष्टि	IS : 2884–1964 शुष्क एवं परतदार मोटे सूती बम्बई डक की विशिष्टि	—
18.	IS : 3194–1980 बिजली लेपन से पूर्व धातु साफ करने की सिफारिशी रीति (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3194–1965 बिजली लेपन से पूर्व धातु साफ करने की सिफारिशी रीति संहिता	—
19.	IS : 3257–1980 स्टेनलेस इस्पात की खानेदार ट्रे की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3257–1965 स्टेनलेस इस्पात की खानेदार ट्रे की विशिष्टि	—
20.	IS : 3300–1980 माउन्ट किये पहियों एवं केन्द्रों के परिमाप (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3300–1980 माउन्ट किये हुए पहियों एवं केन्द्रों के परिमाप (पहला पुनरीक्षण)	—
21.	IS : 3415–1980 चुम्बकीय कण त्रुटि अन्वेषण में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3415–1966 चुम्बकीय कण त्रुटि अन्वेषण में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली	
22.	IS : 3560–1980 लघु अन्तराल संचारण परिशुद्धता कृषि चेन और चेन पहियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3560–1966 लघु अन्तराल संचारण परिशुद्धता कृषि चेन और चेन पहियों की विशिष्टि	—
23.	IS : 3672–1980 डाइऑक्टाइल थैलेट सुघट्कारी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3672–1980 डाइऑक्टाइल थैलेट सुघट्कारी की विशिष्टि	—

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	IS : 3924–1980 बेंजाइल अल्कोहल की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3924–1966 बेंजाइल अल्कोहल की विशिष्टि	—
25	IS : 4453–1980 गड्ढों, खाइयों, प्रवाहों और शाफ्ट द्वारा अवतलन सतह के पर्यवेक्षण की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4453–1967 गड्ढों, खाइयों, प्रवाहों और शाफ्ट द्वारा अवतलन-सतह के पर्यवेक्षण की रीति संहिता	—
26.	IS : 4493 (भाग 1)–1979 खोखली धात्विक तरंग संदर्शिका की विशिष्टि भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं एवं परीक्षण (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4493 (भाग 1)–1968 खोखली धात्विक तरंग संदर्शिका की विशिष्टि भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं एवं परीक्षण	—
27.	IS : 4651 (भाग 5)–1980 पत्तन और बन्दरगाह की योजना और बनावट की रीति संहिता भाग 5 रूपरेखा और कार्यात्मक अपेक्षाएं	—	—
28.	IS : 5448–1980 वस्त्र उद्योग के लिए डेक्सट्रिन (ब्रिटिश गोंद शुक्ल) की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 5448–1969 वस्त्र उद्योग के लिए प्रयुक्त डेक्सट्रिन की विशिष्टि	—
29.	IS : 6246–1980 सादा प्लग मापकों के मापन अंगों की विशिष्टि, "गो" और "नागो" अंग (साइज वर्ग 120 से 250 मिमी (पहला पुनरीक्षण)	1 IS : 6246–1980 सादा प्लग मापकों के मापन अंगों की विशिष्टि, "गो" अंग (साइज वर्ग 100 से 250 मिमी) और 2. IS : 6247–1971 सादा प्लग मापकों के मापन अंगों की विशिष्टि "नो गो" अंग (साइज वर्ग 100 से 250 मिमी)	
30.	IS : 6304–1980 धनात्मक प्लेट लगी सीसा अम्ल प्रकार की स्थिर बैटरियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 6304–1971 धनात्मक प्लेट लगी सीसा अम्ल प्रकार के स्थिर सैल और बैटरियों की विशिष्टि	
31.	IS 7524 (भाग 1)–1980 नेत्र रक्षकों की परीक्षण पद्धतियां भाग 1 यंत्रकाशकीय परीक्षण (पहला पुनरीक्षण)	IS : 7524 (भाग 1)–1975 नेत्र रक्षकों की परीक्षण पद्धतियां भाग 1 नेमी परीक्षण	
32.	IS :8872 (भाग II खण्ड 4)–1979 परिवर्ती प्रतिरोधकों की विशिष्टि भाग 2 सामान्य कार्य : अनुभाग 4 टाइप वीआर-जी 4पी	—	
33	IS : 9001 (भाग 6)–1980 पर्यावरणीय परीक्षण के लिए मार्गदर्शन भाग 6 सम्पर्क एवं सम्बन्ध के लिए हाईड्रोजन सल्फाइड के परीक्षण	—	
34.	IS: 9239-1979 खानों में लपेटने की ढलवां घिरनी की विशिष्टि		
35.	IS: 9304-1979 आम संग्रह करने की संदर्शिका	—	
36.	IS: 9313-1979 संसोधित आहार से भरे हुए शीशे के मर्तबानों और बोतलों की निर्यात पैकेजबंदी के लिए पनारीदार रेशे के तख्तों के बक्सों की विशिष्टि		
37.	IS: 9355–1980 ब्यूटाक्लोर तकनीकी की विशिष्टि		
38.	IS: 9373–1979 बेकरी उद्योग में संबंधित पारिभाषिक शब्दावली	—	

(1)	(2)	(3)	(4)
39.	IS: 9376—1979 रोड़ी तोड़न मान और 10 प्रतिशत चूरा (डस्ट) मान मापन उपकरण की विशिष्टि	—	—
40.	IS: 9385 (भाग II)—1980 उच्च वोल्टता के फ्यूजों की विशिष्टि भाग II निष्कासन और समरूप फ्यूज	IS : 5792—1979 उच्च वोल्टता के निष्कासन फ्यूजों एवं समतुल्य फ्यूजों की विशिष्टि	—
41.	IS: 9399—1979 कंक्रीट के नमन परीक्षण के उपकरण की विशिष्टि	—	—
42.	IS: 9409—1980 बिजली के झटके से बचाव संबंधी बिजली और इलेक्ट्रानी उपकरण का वर्गीकरण	—	—
43.	IS: 9418—अनु-सिलेंडरों वाले संपीड़न प्रज्वलन इंजन के इंधन अन्तःक्षेपण पम्पों पर माउन्ट किये कोर के परिमाप	—	—
44.	IS: 9418—1980 300 किवों तक एवं सहित और 1000 वो से अधिक की सांकेतिक वोल्टता के लिए जैव पदार्थ के भीतरी धम्मा रोधकों की विशिष्टि	—	—
45.	IS: 9439—1980 जल-कूप की खुदाई प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली	—	—
46.	IS: 9488 (भाग I)—1980 समुद्री जहाजी सुरक्षा जंगलों और सीखचों की विशिष्टि : भाग 1 जहाजों के लिए सुरक्षा जंगले।	—	—
47.	IS: 9448 (भाग II)—1980 समुद्री जहाजी सुरक्षा जंगलों और सीकचों की विशिष्टि भाग II जहाजों के लिए दरवाजे और सुवाह्य सुरक्षा जंगले सेक्शन	—	—
48.	IS: 9457—1980 सुरक्षा रंगों और सुरक्षा संकेतों की रीति संहिता	—	—
49.	IS: 9489—1980 ऊष्मा प्रवाह मापी द्वारा ऊष्मा संवाहकता के ऊष्मा रोधन पदार्थों के परीक्षण की पद्धतियां	—	—
50.	IS: 9491—1980 हवा भरे गद्दों की विशिष्टि	—	—
51.	IS: 9509—1980 विस्कोस रेयन उद्योग के निःस्रावों के उपचार एवं निपटान की संदर्शिका	—	—
52.	IS: 9510—1980 अम्लसह ग्रेड के बिटूमन मास्टिक की विशिष्टि	—	—
53.	IS: 9616—1980 ऊष्मा प्रतिरोधी दस्ताने की विशिष्टि	—	—
54.	IS: 9522—1980 विलोडक उपकरण की रीति संहिता	—	—
55.	IS: 9528 (भाग II)—1980 पीएलसी व्यवस्था (एसएसबी) की योजना की नियमावली भाग II पीएलसी व्यवस्था योजना	—	—
56.	IS: 9530—1980 विद्युत लेपनों की सूक्ष्म कठोरता की परीक्षण पद्धति	—	—
57.	IS: 9531—1980 बिजली लेपन के लिए ताम्बा और ताम्बे से बनी मिश्रधातु तैयार करने की सिफारिश रीति	—	—
58.	IS: 9549—1980 काबलों के लिए चिरवा पिन के छिद्रों, तार के छिद्रों और ऊपरी खांचों के परिमाप	—	—
59.	IS: 9550—1980 चमकीली सलाखों की विशिष्टि	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)
60.	IS: 9556—1980 छायाफ्राम दीवारों के बनाने और नमूने की विशिष्टि	—	—
61.	IS. 9561—1980 वृक्षों को काट कर गिराने और लट्ठों में बदलने की सिफारिशें	—	—
62.	IS: 9562—1980 पुलिस दल के लिए आधात्मिक हेलमेट की विशिष्टि	—	—
63.	IS: 9565—1980 इस्पात की ढलाई के परोश्रव्य निरीक्षण के लिए स्वीकृत मानकों की विशिष्टि	—	—
64.	IS: 9567—1980 बंग अथवा बंग सीसा आवरित तांबे के तार की विशिष्टि	—	—
65.	IS: 9573—1980 द्रवित पैट्रोलियम गैस के लिए रबड़ के नल की विशिष्टि	—	—
66.	IS: 9581—1980 पाद-नियंत्रित सिलिंडर (फिरकी) वाली बिजली की घास काटने की मशीन की सुरक्षा एवं चालनों की अपेक्षाएं	—	—
67.	IS: 9585—1980 वृत्तमापी की विशिष्टि	—	—
68.	IS: 9600—1980 पुस्तिकाओं के आकार की सुरक्षा दियासलाइयों की विशिष्टि	—	—
69.	IS: 9602—1980 विलोडकों के लिए पूर्तिकर्ता का आंकड़ा पत्र	—	—

इन भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, पटना और तिरुवेंद्रम स्थित शाखा कार्यालयों में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

[संख्या सीएमजी/13:2]

ए० एस० चीमा, अपर महानिदेशक

S.O. 1059—In pursuance of sub-rule(2) of Rule 3 and Sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard(s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on 1980-11-20:

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standards Established	No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard	Remarks, If any
1	2	3	4
1.	*IS : 320-1980 Specification for high tensile brass rods and sections (other than forging stock) (second revision)	IS : 320-1962 Specification for high tensile brass rods and sections (revised)	*For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 320-1980 shall come into force with effect from 1981-03-01
2.	IS : 444-1980 Specification for rubber water hose (third revision)	IS : 444-1968 Specification for water hose of rubber with woven textile reinforcement (second revision)	—
3.	IS : 1072-1980 Specification for leaf Chains, clevises and sheaves (first revision)	IS : 1072-1967 Specification for leaf chains	—
4.	IS : 1144-1980 Specification for lead-acid storage batteries for motor cycles, autorickshaws and smimilar vehicles (second revision)	IS : 1145-1962 Specification for lead-acid storage batteries for motor cycle, autorickshaws and similar vehicles (revised)	—

1	2	3	4
5.	IS : 1367 (Part II) 1979 Technical supply conditions for threaded steel fasteners: Part II Product grades and tolerances (second revision)	IS : 1367-1967 Technical supply conditions for threaded fasteners (first revision)	—
6.	IS : 1367(Part III)—1979 Technical supply conditions for threaded steel fasteners: Part III Mechanical properties and test methods for bolts, screws and studs with full loadability (second revision)	-do-	—
7.	IS : 1380-1980 Specification for ink, finger, printing, (first revision)	IS : 1380-1959 Specification for ink, finger printing, black)	—
8.	IS : 1448(P:96)-1980 Methods of test for petroleum and its products : P: 96 Rust-preventing characteristics of steam-turbine oil in the presence of water	—	—
9.	IS : 1574—1980 Specification for glass weighing bottles (first revision)	IS : 1574-1960 Specification for glass weighing bottles	—
10.	IS : 1823-1980 Specification for floor door stoppers (third revision)	IS : 1823-1974 Specification for floor door stoppers (second revision)	—
11.	IS : 1985 (Part I)-1980 Recommended practice for preparation of iron and steel for electroplating Part I High Carbon steel (first revision)	IS : 1985-1962 Code of practice for pre-treatment of steel, copper and copper base alloys, zinc and zinc base alloys for electroplating	—
12.	IS : 1985 (Part II)—1980 Recommended practice for preparation of iron and steel for electroplating: Part II Low carbon steel (first revision)	-do-	
13.	IS : 1985 (Part III) -1980 Recommended practice for preparation of iron and steel for electroplating : Part III Iron castings (first revision)	-do-	
14.	IS : 2516 (Part III/Sec 2)-1980 Specification for circuit-breakers : Part III Design and construction: Section 2 for voltages above 1000 V ac (first revision)	(i) IS : 2516 (Part I/Sec 3)—1972 Specification for alternating current circuit-breakers: Part I Requirements: Section 3 Voltages above 11 KV (ii) IS : 2516 (Part II/Sec 2)—1965 Specification for alternating current circuit breakers: Part II Tests: Section 2 Voltage above 1000 up to and including 11000 volts	
15.	For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 2596—1980 shall come into force with [effect from 1981-05-15[IS : 2596—1980 Specification for bulbs (lamps) for miners' cap-lamps (first revision)	IS : 2596-1964 Specification for bulbs (lamps) for miners' cap lamps	
16.	IS : 2683-1980 Guide for Installation of impregnation plants for timber (second revision)	IS : 2683-1966 Guide for installation of pressure impregnation plants for timber (first revision)	—

1	2	3	4
17.	IS : 2884—1979 Specification for dried and laminated Bombay duck (first revision)	IS : 2884-1964 Specification for dried and laminated Bombay duck	—
18.	IS : 3194-1980 Recommended practice for cleaning metals prior to electroplating (first revision)	IS : 3194—1965 Code of recommended practice for cleaning of metals prior to electroplating	—
19.	IS : 3257-1980 Specification for stainless steel compartmental trays (first revision)	IS : 3257-1965 Specification for stainless steel compartmental trays	—
20.	IS : 3300-1980 Dimensions for mounted wheels and points (first revision)	IS : 3300-1965 Dimensions for mounted points	—
21.	IS : 3415-1980 Glossary of terms used in magnetic particle flaw detection (first revision)	IS : 3415-1966 Glossary of terms used in magnetic particle flaw detection	—
22.	IS : 3560-1980 Specification for short pitch transmission precision bush chains and chain wheels (first revision)	IS : 3560-1966 Specification for short pitch transmission precision bush chains and chain wheels	—
23.	IS : 3672-1980 Specification for dioctyl phthalate pasticizers (first revision)	IS : 3672-1966 Specification for octyl phthalate plasticizers	—
24.	IS : 3924-1980 Specification for benzyl alcohol (first revision)	IS : 3924-1966 Specification for benzyl alcohol	—
25.	IS : 4453-1980 Code of practice for sub-surface exploration by pits, trenches, drifts and shafts (first revision)	IS : 4453-1967 Code of practice for exploration by pits, trenches, drifts and shafts	—
26.	IS : 4493 (Part I) -1979 Specification for hollow metallic waveguides : Part I General requirements and tests (first revision)	IS : 4493 (Part I)—1968 Specification for hollow metallic waveguides : Part I General requirements and tests	—
27.	IS : 4651 (Part V)—1980 Code of practice for planning and design of ports and harbours Part V Layout and functional requirements		—
28.	IS : 5448-1990 Specification for dextrins for textile industry (including British gum) (first revision)	IS : 5448-1969 Specification for dextrin for use in textile industry	
29.	IS : 6246-1980 Specification for gauging members for plain plug gauges go and no go members (size range above 120 up to 250 mm) (first revision)	(i) IS : 6246-1971 Specification for gauging members for plain plug gauges 'Go' member (size range 100 to 250 mm) and (ii) IS : 6247-1971 Specification for gauging members for plain plug gauges 'No Go' member (size range 100 to 250 mm)	
30.	IS : 6304-1980 Specification for stationary batteries lead-acid type with pasted positive plates (first revision)	IS : 6304-1971 Specification for stationary cells and batteries, lead acid type with pasted plates	—
31.	IS : 7524 (Part I)—1980 Method of test for eye-protectors Part I Non-optical tests (first revision)	IS : 7524 (Part I)—1975 Methods of test for eye protectors: Part I Routine tests	—

1	2	3	4
32.	IS : 8872 (Part II/Sec. 4)—1979 Specification for variable resistors: Part II General purpose: Section 4 Type VRG4P	IS : 7524 (Part I) 1975 methods of test for eye protectors : Part I Routine tests	—
33.	IS : 9001 (Part VI)-1980 Guidance for environmental testing: Part VI Hydrogen sulphide test for contacts and connections	—	—
34.	IS : 9239–1979 Specification for cast sheaves for winding in mines	—	—
35.	IS : 9304—1979 Guide for storage of mangoes	—	—
36.	IS : 9313–1979 Specification for corrugated fibreboard boxes for the export packaging of glass jars and bottles filled with processed foods	—	—
37.	IS : 9355–1980 Specification for butachlor, technical	—	—
38.	IS : 9373–1979 Glossary of terms relating to bakery industry	—	—
39.	IS : 9376–1979 Specification for apparatus for measuring aggregate crushing value and ten per cent fines value	—	—
40.	IS : 9385 (Part II)—1980 Specification for high voltage fuses: Part II Expulstion and similar fuses	IS : 5792–1970—Specification for high voltage expulsion fuses and similar fuses	—
41.	IS : 9399–1979 Specification for apparatus for flexural testing of concrete	—	—
42.	IS : 9409–1980 Classification of electrical and electronic equipment with regard to protection against electric shock	—	—
43.	IS : 9418–1980 Dimensions for mounting flanges for in-line fuel injection pumps for multi-cylinder compression ignition engines	—	—
44.	IS : 9431–1979 Specification for indoor post insulators of organic material for systems with nominal voltages greater than 1000 V up to and including 300 KV	—	—
45.	IS : 9439–1980 Glossary of terms used in water-well drilling technology	—	—
46.	IS : 9448 (Part I)-1980 Specification for marine guardrails and stanchions: Part I Guardrails for ships	—	—
47.	IS : 9448 (Part II)—1980 Specification for marine guardrails and stanchions Part II Gates and portable guardrail sections for ships	—	—
48.	IS : 9457–1980 Code of practice for safety colours and safety signs	—	—
49.	IS : 9489–1980 Methods of test for thermal conductivity of thermal insulation materials by means of heat flow meter	—	—
50.	IS : 9491–1980 Specification for mattress, air	—	—

1	2	3	4
51.	IS : 9509–1980 Guide for treatment and disposal of effluents of viscose rayon industry	IS : 5792–1970—specification for high voltage expulsion fuses and similar fuses	—
52.	IS : 9510–1980 Specification for bitumen mastic, acid-resisting grade	—	—
53.	IS : 9516–1980 Specification for heat resisting steels	—	—
54.	IS : 9522–1980 Code of practice for agitator equipment	—	—
55.	IS : 9528 (Part II)—1980 Manual for planning of (SSB) PLC systems: Part II PLC systems planning	—	—
56.	IS : 9530–1980 Method of testing microhardness of electroplated coatings	—	—
57.	IS : 9531–1980 Recommended practice for preparation of copper and copper-base alloys for electroplating		—
58.	IS : 9549–1980 Dimensions for split pin holes, wire holes and head slots for bolts	—	—
59.	IS : 9550–1980 Specification for bright bars	—	—
60.	IS : 9556–1980 Code of practice for design and construction of diaphragm walls	—	—
61.	IS : 9561–1980 Recommendations for felling and conversion of trees into logs	—	—
62.	IS : 9562–1980 Specification for non-metal helmet for police force	—	—
63.	IS : 9565–1980 Specification for acceptance standards for ultrasonic inspection of steel castings	—	—
64.	IS : 9567–1980 Specification for tin or tin-lead coated copper wire	—	—
65.	IS : 9573–1980 Specification for rubber hose for liquefied petroleum gas (LPG)	—	—
66.	IS : 9581–1980 Safety and operational requirements for pedestrian-controlled cylinder (reel) power lawn mowers	—	—
67.	IS : 9585–1980 Specification for lactometers	—	—
68.	IS : 9600–1980 Specification for safety matches in booklets	—	—
69.	IS : 9602–1980 Supplier's data sheet for agitators	—	—

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also from its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Bombay, Calcutta Chandigarh, Hyderabad, Jaipur Kanpur, Madras, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13 : 2]

A. S. CHEEMA, Addl. Director General

ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1984

का० आ० 1060.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 3375 तारीख 6-8-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कलोल—111 से के-7 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला और ताल्लुका : गांधीनगर

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
शरेथा	1001/2	0	02	62
	1000	0	11	20

[सं० O--12016/100/83-प्रोड]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 14th March, 1984

S.O. 1060.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3375 dated 6-8-1983 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Kalol-111 To K-7

State Gujarat District & Taluka : Gandhinagar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
SERTHA	1001/26	0	02	62
	1000	0	11	20

[No. O-12016/100/83-PROD]

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1984

का० आ० 1061.—यतः पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय, पट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 4148 तारीख 24-10-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : ओलपाड

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीआर
सरोली	171	0	13	80
	169	0	31	50
	168	0	05	06
	195	0	37	35
	196	0	16	35
	197	0	31	20
	198	0	27	60
	68	0	25	80
	69	0	17	25
	70	0	01	85
	71	0	36	20
	72	0	01	68
	74	0	79	80
	75	0	01	20
	76	0	27	75
	110	0	13	74
	45	0	10	28
	46	0	07	98
	47	0	21	60
	27	0	27	00
	कार्ट ट्रेक	0	02	00
	26	0	01	52
	22	0	71	66
	कार्ट ट्रेक	0	00	90
	14	0	27	60
	15	0	54	50
	16	0	05	74
	8	0	05	20

[सं० O-12016/123/83-प्रो०]

S.O. 1061.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4148 dated 24-10-83 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appened to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall ifnstead of vesing in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from embrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira to Barcilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Surat Taluka : OLPAD

Village	Block No.	Hec-age	Are	Cent-are
SAROLI	171	0	13	80
	169	0	31	50
	168	0	05	06
	195	0	37	35
	196	0	16	35
	197	0	31	20
	198	0	27	60
	68	0	25	80
	69	0	17	25
	70	0	01	85
	71	0	36	20
	72	0	01	68
	74	0	79	80
	75	0	01	20
	76	0	27	75
	110	0	13	74
	45	0	10	28
	46	0	07	98
	47	0	21	60
	27	0	27	00
	Cart Track	0	02	00
	26	0	01	52
	22	0	71	66
	Cart Track	0	00	90
	14	0	27	60
	15	0	54	50
	16	0	05	74
	8	0	05	20

[No. O-12016/123/83-Prod]

नई दिल्ली, 14 मार्च 1984

का० आ० 1062.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 3374 तारीख 6-8-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस पाइपलाइन में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कलोल-9 से कलोल-169 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : गांधीनगर

गांव	ब्लॉक, नं०	हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
अडालज	407	0	18	75
	कार्ट ट्रैक	0	05	10
	410	0	09	10

[सं० O-12016/99/83-प्रोड]

New Delhi, the 14th March, 1984

S.O. 1062.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3374 dated 6-8-1983 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Kalol-9 to Kalol-169

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
ADALAJ	407	0	18	75
	Cart Track	0	05	10
	410	0	09	10

[No. O-12016/99/83-PROD]

का० आ० 1063.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आ० सं० 4143 तारीख 24-10-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका चोर्यासी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
वरीयाव	510	0	04	30
	511	0	39	00
	513	0	28	05
	517	0	41	20
	518	0	04	10
	522	0	08	90
	521	0	24	00
	524	0	09	00
	525	0	00	35
	526	0	14	50
	527	0	14	35
	528	0	10	85
	535	0	02	30
	536	0	30	00
	537	0	02	10
	560	0	30	50
	561	0	04	90
	559	0	30	50
	563	0	63	00

[सं० ओ-12016/125/83-प्रौड]

S.O. 1063.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4143 dated 24-10-1983 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira to Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Surat Taluka : Choriyasi

Vilage	Survey No.	Hec-are	Are	Centi are
VARIAV	510	0	04	30
	511	0	39	00
	513	0	28	05
	517	0	41	20
	518	0	04	10
	522	0	08	90
	521	0	24	00
	524	0	09	00
	525	0	00	35
	526	0	14	50
	527	0	14	35
	528	0	10	85
	535	0	02	30
	536	0	30	00
	537	0	02	10
	560	0	30	50
	561	0	04	90
	559	0	30	50
	563	0	63	00

[No. O12016/25/83-PROD]

का०आ० 1064.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आ०सं० 4145 तारीख 24-10-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है

कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : ओलपाड

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
कठोदरा	314	0	39	46
	315	0	33	39
	316	0	23	27
	328	0	29	34
	340	0	72	84
	343	0	36	41
	347	0	34	40
	342	0	03	04

[सं० ओ०-12016/124/83-प्रौड]

S.O. 1064.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4145 dated 24-10-1983 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira To Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Surat Taluka Olpad

Village	Block No.	Hect-are	Are	Centi-are
KATHODRA	314	0	39	46
	315	0	33	39
	316	0	23	27
	328	0	29	34
	340	0	72	84
	343	0	36	41
	347	0	34	40
	342	0	03	04

[No. O-12016/124/83-Prod.]

का०आ० 1065.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 3652 तारीख 16-8-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूपनं० केआरडी–8 से जीजी०एस०–IV तक पाइप लाइन बिछाने लिए

राज्य—गुजरात जिला – मेहसाना तालुका–कलोल

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
धमासणा	992	0	05	85
	991	0	04	50
	996	0	10	30
	1000	0	00	75
	999	0	01	90
	998	0	02	60
	864	0	07	00
	866	0	06	90
	841	0	02	50
	873	0	20	70
	कार्ट ट्रैक	0	00	50
	875	0	07	80
	876	0	08	70
	876	0	08	50
	881	0	10	00

[सं० ओ०–12016/106/83–प्रोड]

S.O. 1065.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3562 dated 16-8-1983 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in the lands specified in the Schedule appended Government declared its intention to acquire rights of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquires for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead, of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Well No. Kod-8 to GGS IV

Sate : Gujarat Dirstrict Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No. W	Hec-are	Are	Centi-are
DHAMASANA	992	0	05	85
	991	0	04	50
	996	0	10	30
	1000	0	00	75
	999	0	01	90
	998	0	02	60
	863	00	07	00
	866	0	06	90
	841	0	02	50
	873	0	20	70
	Cart Track	0	00	50
	875	0	07	80
	876	0	08	70
	877	0	08	50
	881	0	10	00

[No. O-12016|06|83-PROD]

का० आ० 1066.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आ० सं० 1516 तारीख 9-11-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर लिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० एम०पी०ए० से एम० एम० डी०-10 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—मेहसाना तालुका—कलोल

गाँव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए आर ई सेंटीयर	
जेठलज	516	0	05	70
	513/1	0	10	35
	513/2	0	07	20
	512	0	01	07

[सं० ओ०-12016/139/83-प्रोड]

S.O. 1066.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4516 dated 9-11-1983 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Well No. SPA to SND. 30.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
JETHALAJ	516	0	05	70
	513/1	0	10	35
	513/2	0	07	20
	512	0	01	07

[No. O-12016|39|83-PROD]

का०आ० 1067—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 4151 तारीख 25-10-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—सूरत तालुका—ओल पाड

गाँव	ब्लॉक	हेक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
जोथान	198	0	06	52
	199	0	10	92
	200	0	04	90

[सं० O-12016/132/83-प्रोड०]

S.O. 1067.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4151 dated 25-10-1983 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira to Barcily to Jagdishpur

State : Gujarat District : Surat Taluka : Olpad

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centi-are
JOTHAN	198	0	06	52
	199	0	10	92
	00	0	04	90

[No. O-12016|132|83-PROD]

का० आ० 1068—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 3563 तारीख 1-9-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची

में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप—केओडी-19 से जी०जी०एस० VIII तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—मेहसाना तालुका—कलोल

गाँव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
कलोल	1113/1	0	09	75
	1115	0	02	85
	1114	0	04	65
	1119/1	0	27	15

[सं० ओ-12016/105/33-प्रोड.]

S.O. 1068.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum, S.O. 3563 dated 1-9-1983 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Well No. KOD-19 to GGS VIII

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centi-are
Kalol	1113/1	0	09	75
	1115	0	02	85
	1114	0	04	65
	1119/1	0	27	15

[No. O-12016|105|83-PROD]

1564 GI/83—7

का० आ० 1069.—अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 3553 तारीख 30-8-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

सी० टी० एफ० कलोल से फ्लेयर पाइंट तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला-मेहसाना ताल्लुका-कलोल

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
सइज	996/1	0	03	00
	994/4/10	0	06	00

[सं० O-12016/103/83-प्रोड०]

S.O. 1069.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum, S.O. 3553 dated 30-8-1983 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right

of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from C.T.F. Kalol to Flair Point

State : Gujarat Distt. : Mehsana : Taluka : Kalol

Vill.	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
SAIJ	996/1	0	03	00
	994/4/10	0	06	00

[No. O-12016/103/83-PRQD]

का० आ० 1070.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 4376 तारीख 18-11-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

झालोरा-22 से जी० जी० एस० I तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—मेहसाना ताल्लुका—कड़ी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर	सेंटीमीटर
मनीपुर	172	0	02	00
	176	0	09	75
	177	0	08	70
	178	0	18	00
	179	0	10	05
	180	0	24	00
	182	0	24	45

[सं० O-12016/140/83-प्रोड०]

पी० के० राजगोपालन, डेस्क अधिकारी

S.O. 1070.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4376 dated 18-11-1983 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Jhalora 22 to GGS I

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Manipur	172	0	02	00
	176	0	09	75
	177	0	08	70
	178	0	18	00
	179	0	10	05
	180	0	24	00
	182	0	24	45

[No. O-12016/140/83-PROD]

P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1984

का० आ० 1071.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजपत्र में तारीख 31-7-82 को प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 2761 तारीख 7

जुलाई, 1972 को अधिक्रांत करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों की बाबत अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1 राजस्व का प्रधान	सेन्ट्रल कोलफील्डस लि०, रांची के या उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन के सब स्थान और महाप्रबन्धक राजरप्पा, कुजू और हजारी बाग क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० के सभी अन्य स्थान ।
2 राजस्व का सर्वोच्च प्रधान संपदा प्रबन्धक, सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० दरभंगा हाउस, रांची ।	बिहार राज्य के भीतर रांची, पलामू, हजारीबाग और गिरीडीह जिलों, उड़ीसा राज्य के भीतर ढेंकनाल, उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर मिर्जापुर और मध्य प्रदेश राज्य के भीतर सिन्धी में सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० रांची के और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन के कोयला खान क्षेत्र और सभी अन्य स्थान ।
3. राजस्व का उप प्रधान, सेन्ट्रल कोल फील्डस लि०	अरगदा, उत्तरी कर्णपुरा, तालचर और सिंगरौली क्षेत्रों के महाप्रबन्धकों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० के कोयलाखान क्षेत्र और सभी राज्य स्थान ।
4. राजस्व का सहायक प्रधान, सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० दरभंगा हाउस, रांची	बोकारो, और करगली, बारकाकाना (जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डार और केन्द्रीय कर्मशाला परिसर भी है) कथरा और डोरी क्षेत्र के महाप्रबंधक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सेन्ट्रल कोलफील्डस के कोयला खान क्षेत्र और सभी अन्य स्थान ।

[सं० 29/2/83-सी०एल०]

समय सिंह, अवर सचिव

(Department of Coal)

New Delhi, the 15th March, 1984

S.O. 1071. –In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Energy Department of Coal S.O. No. 2761 dated the 7th July, 1982 published in the Gazette of India on 31-7-82, the Central Government hereby appoints the Officers mentioned in Column(1) of the Table below, being officers equivalent to the rank of Gazetted officers of Government, to be estate officers for the purposes of the said Act, and the said officers shall expercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officer by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdictions in respect of categories of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the officer	Categories of the public premises and local limits of jurisdiction
1	2
1. Chief of Revenue, Central Coalfields Ltd., Darbhanga House, Ranchi.	All the premises belonging to or under the administrative control of the Central Coalfields Ltd., Ranchi and Coalfields area and all other premises belonging to the Central Coalfields Ltd., under the administrative control of the General Managers, Rajrappa, Kuju & Hazaribagh areas.
2. Chief of Revenue/ Estate Manager, Central Coalfields Ltd. Dharbhanga House, Ranchi.	Coalfields areas and all other premises belonging to and under the administrative control of the Central Coalfields Ltd. Ranchi, in the districts of Ranchi, Palamau, Hazaribagh and Giridih within the State of Bihar, Dhenkanal within the State of Orissa, Mirzapur within the State of Uttar Pradesh and Sidhi within the State of Madhya Pradesh.
3. Dy. Chief of Revenue Central Coal fields Ltd., Darbhanga House, Ranchi.	Coalfields Area and all other premises belonging to the Central Coalfields Ltd. under the administrative control of General Managers, Argada, North Karanpura, Talcher and Singrauli Areas.

1	2	1	2
4. Asstt. Chief of Revenue, Central Coalfields Ltd. Dharbhanga House, Ranchi.	Coal fields area and all other premises belonging to the Central Coalfields Ltd., under the administrative control of the General Managers of Bokaro & Kargali,		Barkakana, (including Central Stores & Central Workshop premises), Kathara and Dhori Areas.

[No. 29/2/83-CL]
SAMAY SINGH, Under Secy

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1984

शुद्धि पत्र

का० आ० 1072.—भारत के राजपत्र भाग-2 खंड-3, उपखंड (ii) दिनांक 10 अप्रैल, 1982 के का० आ० 1451, पृष्ठ संख्या 1632 से 1634 पर प्रकाशित सौंफ (साबुत और पिसी हुई) मेथी (साबुत और पिसी हुई) और सेलेरी सीड (साबुत) श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1982 के हिन्दी रूपांतर में निम्नलिखित सुधार आवश्यक है :—

क्रम सं०	संदर्भ	अशुद्ध	शुद्ध	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	पृष्ठ 1632 पर,			
	(क) मंत्रालय का नाम	ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	
	(ख) परिच्छेद 4, पंक्ति 2	सेलेरी सीड (साबुत) नियम, 1967	सेलेरी सीड (साबुत) श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1967	
	(ग) परिच्छेद 4, पंक्ति 2	बनाती है, अर्थात् :—	बनाती है।	
	(घ) परिच्छेद 4 के पश्चात् एवं नियम (1) से पूर्व			"नियम" शीर्षक रूप में पढ़ें।
	(ङ) नियम 1(1)	सौंफ नियम (साबुत और पिसी हुई)	सौंफ (साबुत और पिसी हुई),	
	(च) नियम 1(1)	सीड़	सीड	
	(छ) अनुसूची III में :—			
	(अ) स्तम्भ 1	अभिधान श्रेणी	श्रेणी अभिधान	
	(ब) स्तम्भ 2	नमी भारम द्वारा प्रतिशत	नमी, भार द्वारा प्रतिशत	
	(स) स्तम्भ 3	कुल भस्म भार द्वारा प्रतिशत	कुल भस्म भार, द्वारा प्रतिशत	
	(द) स्तम्भ 4	अम्ल अविलेय भस्म भार द्वारा प्रतिशत	अम्ल अविलेय भस्म, भार द्वारा प्रतिशत	
	(य) स्तम्भ 5	वाष्पशील तेल प्रतिशत न्यूनतम (वी०/डब्ल्यू)	वाष्पशील तेल वी०/डब्ल्यू० द्वारा प्रतिशत (न्यूनतम)	
	(र) स्तम्भ 6, पंक्ति 2	अच्छे साबुत सौंफ फलोंको	अच्छे साबुत सौंफ (फोनिकुलम वलगेयर मिल)) फलों को	
	(ल) स्तम्भ 6, पंक्ति 4,	वह अधिमिश्रण से मुक्त, फफूंदी, कीटाग्रसन या	वह अधिमिश्रण, फफूंदी, कीटाग्रसन या	
	(व) स्तम्भ 6, पंक्ति 8	पिसा हुआ । होगा कि	पिसा हुआ होगा कि	
2.	पृष्ठ 1633 पर			
	(1) अनुसूची V में :—			
	(अ) स्तम्भ 2	नमी भारद्वारा प्रतिशत (अधिकतम)	नमी, भारद्वारा प्रतिशत (अधिकतम)	

1	2	3	4	5
	(ब) स्तम्भ 3	कुल भस्म भार द्वारा प्रतिशत (अधिकतम)	कुल भस्म, भार द्वारा प्रतिशत (अधिकतम)	
	(स) स्तम्भ 4	अम्ल अविलेय भस्म भार प्रतिशत (अधिकतम)	अम्ल अविलेय भस्म, भार द्वारा प्रतिशत (अधिकतम)	
	(ङ) स्तम्भ 6 पंक्ति 2	साबुत मेथी बीजों को	साबुत मेथी (ट्रमहगोनेला फोइनम ग्रीकम एल) बीजों को	
	(च) स्तम्भ 6,	वह अधिमिश्रण से मुक्त, फफूंदी	वह अधिमिश्रण, फफूंदी, कीटाग्रसन या फफूंदी।	
	पंक्ति 4,	कीटाग्रसन या फफूंदी गंध से मुक्त व स्थूल कणों से होगा और	गंध से मुक्त होगा। वह स्थूल कणों से मुक्त होगा और	

[10-2/80-एम आई]

बी० के० बजाज, अवर सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the14th March, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 1072—In the notification of Fennel (Whole and Ground), Fenugreek (Whole and Ground) and Celery Seed (whole) gr aing and Marking (Amendment) Rules 1982 dated the 27th March, 1982 published at S.O. No. 1451, on pages 1632 to 1634 in the Gazette of India, part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th April, 1982.

1. at page 1633

(a) in the paragraph 4 for "Marketing"	read "Marking"
(b) in rule 1, in sub-rule (1) for "Marketing"	read "Marking"
(c) after rule (1) Sub-rule(1)	read "1(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the official gazette",
(d) in Rule 2 for "Marketing"	read "Marking"
(e) in SCHEDULE-III in Column 6,—	
(i) in lines 3 & 4 for "Fennel fruits of Foeniculu vulgare MILL."	read "fruits of fennel (Foeniculum vulgare NILL."
(ii) in line 5 for "be free from admixture from mould"	read "be free from admixture, mould".

2. at page 1634:

(a) in line 1, for "Substitute"	read "Substituted"
(b) in SCHEDULE V, in column 6,—	
(i) in lines 3 & 4 for "Fenugreek Seeds of Tragonalla Foenum-graecum L".	read "Seeds of Fenugreek Trigonella foenumgraecum L".
(ii) in lines 5 &7, for "Shall be free from admixture, free from mould growth, inseet, infestation".	read "Shall be free from admixture, mould growth, insect infestation".

[10-2/80-MI]

B.K. BAJAJ, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1984

का० आ० 1073.—केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 9 (अ), तारीख 7 जनवरी, 1978* में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

(1) "सेंसर-व्यवस्था" शब्द के स्थान पर जहां-जहां वह आता है, "प्रमाणन" शब्द रखा जाएगा।

(2) "फिल्म सेंसर बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं "फिल्म प्रमाणन बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे।

*(i) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 17-2-79, में का० आ० 618 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं० 5/7/77-एफ(सी), तारीख 27-1-79 द्वारा संशोधित।

(ii) भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 7-5-83 में का० आ० 356(अ) के रूप में प्रकाशित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं० 805/2/82-एफ(सी), तारीख 7-5-83 द्वारा संशोधित।

[फाइल सं० 805/6/83-एफ (सी)]

आर० डी० जोशी, उप सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 9th March, 1984

S.O. 1073.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5B of the Cinematograph Act 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, No. S.O. 9F, dated the 7th January, 1978* namely :—

(i) for the word "censorship" wherever it occurs the word "certification" shall be substituted.

(ii) for the words "Board of Film Censors" wherever they occur the words "Board of Film Certification" shall be substituted.

*(1) Amended by (i) Notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 5/7/77-F(C) dated 27-1-1979 published as S.O. 618 in the Gazette of India, Part II Section 3 Sub-section (ii) dated 17-2-79.

(2) Notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 805/2/82-F(C) dated 7-5-83 published as S.O. 356(E) in the Gazette of India : Extraordinary Part II Section 3 Sub-section (ii) dated 7-5-83.

[File No. 805/6/83-F(C)]

R. D. JOSHI, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 13 मार्च 1984

का० आ० 1074.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने शहादा टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-4-1984 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-4/84 पी० एच० बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T BOARD)

New Delhi, the 13th March, 1984

S.O. 1074.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 1-4-1984 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Shahada, Telephone Exchange Maharashtra Circle.

[No 5-4/84-PHB]

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1984

का० आ० 1075.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने बिजनौर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-4-1984 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है :

[संख्या 5-5/84-पी० एच० बी०]

New Delhi, the 19th March, 1984

S.O. 1075.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 1-4-1984 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Bijnore Telephone Exchange U.P. Circle.

[No. 5-5/84-PHB]

का० आ० 1076.—स्थायी आदेश संख्या 627 दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने वृन्दावन टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-4-1984 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-5/84-पी० एच० बी०]

S.O. 1076.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 1-4-1984 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Vrindaban Telephone Exchange U.P. Circle.

[No. 5-5/84-PHB]

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1984

का० आ० 1077.—अस्थायी आदेश संख्या 627 दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने शिवपुरी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-4-1984 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-10/84-पी० एच० बी०]

New Delhi, the 21st March, 1984

S.O. 1077.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 1-4-1984 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Shivpuri Telephone Exchange M.P. Circle.

[No. 5-10/84-PHB]

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1984

का० आ० 1078.—अस्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने सोमानूर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-4-1984 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-4/84-पी० एच० बी०]

New Delhi, the 22nd March, 1984

S.O. 1078.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 1-4-1984 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Somanur Telephone Exchange Tamil Nadu Circle.

[No. 5-4/84-PHB]

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1984

का० आ० 1079.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक के पेरून्दुराय/शंकरीद्रुग टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-4-1984 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-4/84-पी० एच० बी०]

त्रिलोकी नाथ, सहायक महानिदेशक, (पी० एच० बी०)

New Delhi, the 23rd March, 1984

S.O. 1079.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 1-4-1984 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Perundurai/Sankaridrug Telephone Exchanges in T. N. Circle.

[No. 5-4/84-PHB]

TRILOKI NATH, Asstt. Director General (PHB)

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1983

का०आ० 1080.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रबन्धतंत्र से संबंधित एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है :

और, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है :

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण होंगे, जिसका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी श्री जोगिन्द्र सिंह भाटी की सेवाएं समाप्त करना न्यायोचित है यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।"

[सं० एल-15012/2/82-डी० 2(बी)]

हरी सिंह, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

ORDER

New Delhi, the 16th September, 1983

S.O. 1080.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Employees State Insurance Corporation and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the termination of services of Shri Joginder Singh Bhati, Class IV employee of ESIC Jaipur is justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

[No. L-15012(2)/82-D. II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली 16 मार्च, 1984

का० आ० 1081.—केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम 1949 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० संख्या 649 (अ) तारीख 13 अगस्त 1981 जिसमें का० आ० संख्या 342 (अ) तारीख 20 मई 1982 और का० आ० संख्या 776 (अ) तारीख 26 अक्तूबर 1983 द्वारा संशोधन किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में नियोजकों के प्रतिनिधियो से संबंधित मद (2) में क्रमांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

श्री राजेश छ.बड़,
निदेशक (निर्माण),
निर्माण और आवास मंत्रालय
नई दिल्ली।

[संख्या एस०-32023/16/83-डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू०)]

New Delhi, the 16th March, 1984

S.O. 1081.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), read with Section 9 of the said Act and rule 3 of the Minimum Wages (Central Advisory Board) Rules, 1949, the Central Govt. hereby makes the following amendment in the notification of the Govt. of India in the Ministry of Labour No. S.O. 649(E), dated the 13th August, 1981 and modified

vide S.O. No. 342(E) dated the 20th May, 1983 and S.O. No. 776(E) dated the 26th October, 1983 namely :—

In the said notification in item (II) relating to the Employers' representatives for serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely :—

Shri Rajesh Chhabra,
Director (Works),
Ministry of Works and Housing,
New Delhi.

[No. S-32023/16/83-W.C.(M.W.)]

का०आ० 1082.—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० संख्या 393 (अ) तारीख 28 मई, 1981 जिसमें का०आ० संख्या 124(अ), तारीख 5 मार्च, 1982 और का०आ० संख्या 776 (अ) तारीख 25 अक्तूबर, 1983 द्वारा संशोधन किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "नियोजकों के प्रतिनिधियों" से संबंधित मद 2 में प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :—

श्री राजेश छाबड़ा,
निदेशक (निर्माण),
निर्माण और आवास मंत्रालय
नई दिल्ली ।

[संख्या एस-32023/16/83-डब्ल्यू०सी० (एम०डब्ल्यू)]

बिशम्भर नाथ, अवर सचिव

S.O. 1082.—In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 393(E) dated the 28th May, 1981 and modified vide S.O. No. 124(E) dated the 5th March, 1982, S.O. No. 325(E) dated the 17th May, 1982 and S.O. No. 776(E) dated the 25th October, 1983 namely:—

In the said notification in item II relating to "Representatives of employers" for entry 2, the following shall be substituted namely :—

Shri Rajesh Chhabra
Director (Works)
Ministry of Works and Housing,
New Delhi.

[No. S-32023/16/83-W.C. (M.W.)]

BISHAMBHAR NATH, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 फरवरी 1984

का० आ० 1083—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक औद्योगिक विवाद जो श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या एल०-29012/3/77-डी०-3(बी०) तारीख 5 फरवरी 1977 द्वारा भेजा गया था, डा० बी० एन० मिश्रा, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर के समक्ष लंबित पड़ा है और डा० बी० एम० मिश्रा की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही हैं ;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 33-ख की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जे० एम० मोहपात्रा होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त श्री बी० एन० मिश्रा पीठासीन अधिकारी औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर के समक्ष लंबित उक्त विवाद से संबद्ध कार्यवाही औद्योगिक अधिकरण भुवनेश्वर को इस निदेश के साथ स्थानांतरित करती है कि उक्त अधिकरण आगे कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगा, जिस पर वह उसे स्थानांतरित की जाए तथा विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा।

अनुसूची

"क्या उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम की दुन्नारी चूना पत्थर खान के रेंजिंग ठेकेदार श्री पी० के० जेना की निम्नलिखित कर्मकारों की वर्ष 1973 में विभिन्न तारीखों को सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

क्रम संख्या	नाम
1.	सर्वश्री बेनीडिक टेटे
2.	" जोहिनी टाटे
3.	" कुलाबती
4.	" क्लेमेंट डंग
5.	" होल्यानी कुलु
6.	" टुरलेन बार्दक
7.	" लोनिओ बिलोंग
8.	" मिरिआम बिलोंग

[सं० एल०-29012/3/77-डी०-3 (बी०)]

नन्द लाल अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th February, 1984

S.O. 1083.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before Dr. B. N. Misra, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneswar, having been referred to him vide Ministry of Labour Order No. L-29012/3/77-D.III(B) dated the 5th February, 1977;

And whereas, the services of Dr. B. N. Misra, are no longer available;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A read with sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an industrial Tribunal, the Presiding Officer of which shall be Shri J. M. Mohapatra, with headquarters at Bhubaneswar and withdraws, the proceedings relation to the said dispute pending before Dr. B. N. Misra, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneswar and transfers the same to Shri J. M. Mohapatra, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneswar with the directions that the said tribunal shall proceed with the proceedings from the

stage at which they are transferred to it and dispute of the same according to law.

SCHEDULE

"Whether the action of Shri P. K. Jena, Raising Contractor of Dungari Limestone Mines of Messrs Industrial Development Corporation of Orissa Ltd., in dismissing his following workmen on different dates in 1973 was justified ? If not to what relief are the workmen concerned entitled ?"

S. No.	Name
1.	Shri Banedik Tete
2.	Shri Johani Tate
3.	Shri Kulabati
4.	Shri Kalement Dung Dung
5.	Shri Holyani Kulu
6.	Shri Turlain Dadaik
7.	Shri Lonence Belong
8.	Shri Miriam Belong.

[No. L-29012/3/77-D.III(B)]

New Delhi, the 20th March, 1984

S.O. 1084.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Pacific Minerals Pvt. Ltd. Balaghat (Madhya Pradesh) and their workmen which was received by the Central Government on the 12th March, 1984.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(6)/1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs Pacific Minerals Pvt. Ltd., Balaghat (Madhya Pradesh) and their workmen, Smt. Kalibai W/o Shri Shambhoolal, Miner, represented through the Khaniz Mazdoor Ekta Union, Post Office Waraseoni, District Balaghat (Madhya Pradesh).

APPEARANCES :

For the Management.—Shri A. K. Pandit.
For Workman.—Shri T. L. Mandalwar.

DISTRICT : Balaghat (M.P.) INDUSTRY : Minerals.

AWARD

By Notification No. L-27012(8)/82-D. III(B) dated 7th January, 1984, the Central Government in exercise of its powers under Sec. 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dispute to this Tribunal, for adjudication :—

"Whether the action of the management of Messrs Pacific Minerals Private Limited Balaghat in relation to their Netra Manganese Mine in stopping Smt. Kalibai W/o Shri Shambhoolal, Miner from work with effect from 13-6-1982 is justified ?"

2. During the pendency of the dispute the parties have settled the claim amicably. Parties have filed a duly signed settlement. This award is therefore made in terms of the settlement as under.

Smt. Kalibai shall be deemed to be in employment with effect from 15-1-1984. The management shall pay Rs. 500 (Rupees Five Hundred only) towards the back wages immediately. There is no dispute between the Management and the workman represented by the Secretary of the Union. There shall be no order as to costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer

[No. L-27012/8/82-D. III(B)]

S.O. 1085.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bharat Gold Mines Ltd., Ramgiri Gold Project and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th March, 1984.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 29 of 1983

BETWEEN

The Workmen of Bharat Gold Mines, Limited, Ramgiri Gold Project, Karnataka.

AND

The Management of Bharat Gold Mines, Limited, Ramgiri Gold Project, Karnataka.

Ref.—Ministry of Labour Letter No. L-29012(43)/83-D. III(B), dt. 6-12-1983.

APPEARANCES :

None present on behalf of the Workmen and the Management.

DOCKET SHEET ORDER

17-2-1984.

Management called absent one Sri Balasubramanyam was present representing the Management on the first date. He is also called absent. There is no representation on behalf of tht Management and the Management is absent for the last two adjournments also. Counter also not filed. In these circumstances management set ex parte. Workman also called absent. His claims statement was received by post but he is not present for any adjournment so far. The workmen also called absent. Set ex parte. As there is no one prosecuting this matter reference terminated holding that it is not established that the workman is entitled to any relief.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 17th day of February, 1984.

M. SRINIVASA RAO, Presiding Officer

[No. L-29012/43/83-D. III(B)]

S.O. 1086.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Andhra Pradesh Mining Corporation Management Barytes Mines, Management and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th March, 1984.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

INDUSTRIAL DISPUTES NO. 1 OF 1984

BETWEEN

The Workmen of Andhra Pradesh Mining Corporation, Management Baryes Mines, Management, Rajampet Taluk, Cuddapah District.

AND

The Management of Andhra Pradesh Mining Corporation, Management, Barytes Mines, Management, Rajampet Taluk, Cuddapah District.

Ref : Ministry of Labour Lr. No. L-29012/42/83-D.III. B, dt. 22nd December, 1983.

APPEARANCES :

None present—for the Workmen and the Management.

DOCKET SHEET ORDER

13-2-1984.

The Workmen's Union and their General Secretary called absent this day also. No claims statement filed on their behalf. As the workman remained absent, they are set ex parte. As there is no claims statement and as this case is not prosecuted, the reference is terminated holding that the workmen are not entitled to any relief.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 13th day of February, 1984.

M. SRINIVASA RAO, Presiding Officer

[No. L-29012/42/83-D.III(B)]

NAND LAL, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1984

का० आ० 1087.—इस उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री बी० एच० उपाध्याय, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के समक्ष लंबित पड़े हैं, और श्री बी० एच० उपाध्याय की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही हैं :

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33-ख की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० एन० लालगे होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त श्री बी० एच० उपाध्याय, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के समक्ष लंबित उक्त विवाद से संबंध कार्यवाही को वापस लेती है और उसे श्री बी० एन० लालगे, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर को इस निदेश के साथ स्थानांतरित करती है कि उक्त अधिकरण आगे कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगा जिस पर वह उसे स्थानांतरित की जाए तथा विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा।

अनुसूची

क्रमांक	औद्योगिक संख्या	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश की संख्या और तारीख	पक्षकारों के नाम
1	2	3	4
1.	4/73	एल-29011/40/73-एल०आर०-IV दिनांक 29-9-73	मैसर्स तुंगभद्रा मिनरल्स (प्रा०) लि०, डाकघर नारानगर के प्रबन्धक और कर्मकार
2.	4/75	एल-29012/9/74-एल आर-4 डी ओ 3(बी) दिनांक 26-2-1975	भारत गोल्ड माइन्स लि० के०जी०एफ०
3.	10/75	एल-12012/18/73-आर एल-III दिनांक सितम्बर, 1975	सिंडीकेट बैंक मणिपाल
4.	6/76 (केन्द्रीय)	एल-12012(85)/76-डी-II(ए) दिनांक 19-8-1976	विजय बैंक लिमिटेड, बंगलोर
5.	7/76	एल-4301206/76-डी-4(बी) दिनांक 4-9-1976	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, के०जी०एफ०
6.	3/77	एल-17012/3/75-डी-II(ए) दिनांक 7-5-1976	नेशनल इंसोरेंस कम्पनी लिमिटेड, बंगलोर
7.	7/78	एस-12011/94/78-डी-III (ए) दिनांक 21/27/9/1978	कारपोरेशन बैंक लिमिटेड, मंगलोर
8.	7/80	सं० एल-29011/59/79-डी-III (बी) दिनांक 24-9-1980	बागलकोट उद्योग लि० बागलकोट, जिला बीजापुर
9.	1/81	सं० एल-12011/9/80-डी-II(बी) दिनांक 29-1-1981	कारपोरेशन बैंक हुबली
10.	2/81	सं० एल-26012/9/80-डी-III(बी) दिनांक 29-1-1981	कुद्रेमुख आयरन ओरे कं० लिमिटेड, बंगलोर
11.		सं० एल 12012/37/80-डी-II(ए) दिनांक	स्टेट बैंक आफ मैसूर बंगलोर

1	2	3	4
12.	4/81	सं० एल-45012/1/80-डी-IV(ए) दिनांक 28-2-1981	न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर
13.	6/81	सं० एल-12012/74/80-डी-II(ए) दिनांक 2-4-1981	कैनरा बैंक
14.	6/75	सं० एल 27011/4/74-एल आर-4(बी) दिनांक 4-3-1975	संडूर मैंगनीज एण्ड आयरन वर्क्स (प्रा०) लिमिटेड, जिला बेलरी
15.	3/82	सं० एल-17015/(1)/81-डी-4(ए) दिनांक शून्य	लाइफ इंसोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, बंगलोर
16.	4/82	सं० एल-12011(28)/81-डी-4(ए) दिनांक 26-4-1982	कृष्णा ग्रामीण बैंक लि०, गुलबर्गा
17.	6/82	सं० एल-126012/9/81-डी-III(बी) दिनांक 3-8-1982	कुद्रमुख आयरन ओर कं० लि०,बंगलोर
18.	7/82	एल-45015/2/78-डी-4(ए) दिनांक शून्य	न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर
19.	8/82	एल-12011/75/81-डी-II(ए) दिनांक 17-8-1982	कर्नाटक बैंक लिमिटेड, मंगलोर
20.	9/82	सं० एल-12012(12)/82-डी-IV(ए) दिनांक शून्य	—यथोक्त—
21.	10/82	सं० एल-43012(3)/81-डी-III(बी) दिनांक शून्य	हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लिमिटेड, हट्टी, जिला रायचूर
22.	11/32	सं० एल-43012(3)/82-डी-III(बी) दिनांक शून्य	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के०जी०एफ०
23.	12/82	सं० एल-12012/14/82-डी-4(ए) दिनांक 30-10-1982	यथोक्त;
24.	1/83	सं० एल-12012/19/82-डी-4(ए) दिनांक 8-3-1983	कर्नाटक बैंक लिमिटेड, मंगलोर
25.	2/83	सं० एल-12512/34/82-डी-II(ए) दिनांक 4-4-1983	मलप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़
26.	3/83	सं० एल-12012/101/82-डी-II(ए) दिनांक 31-3-1983	कावेरी ग्रामीण बैंक लिमिटेड, मैसूर
27.	5/83	सं० एल-26011/8/82-डी-III(बी) दिनांक 15-7-1983	कुद्रमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलोर
28.	6/83	सं० एल-43011/9/82-डी-III(बी) दिनांक शून्य	भारत गोल्ड माइन्स लि०, के०जी०एफ०
29.	7/83	सं०एल-29011/43/82-डी-III (बी) दिनांक शून्य	बायरापुर, क्रोमाइट माइन्स डा० कम्बल जिला हसन
30.	11/80	सं० एल-12012/46/80-डी-II(ए) दिनांक 20-11-1980	स्टेट बैंक आफ मैसूर, बंगलोर
31.	—	सं० एल-43012/2/82-डी-III(बी) दिनांक 5-10-1983	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, के०जी०एफ०
32.	—	सं० एल-45011(4)/83-4(ए) दिनांक शून्य	दी न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट
33.	—	सं० एल-12012(51)/83-डी-II(ए) दिनांक नवम्बर, 1983	दी सिंडीकेट बैंक, मणिपाल
34.	—	सं० एस-12012/41/83-डी-4(ए) दिनांक 6-2-1984	दी कर्नाटक बैंक लि० मंगलोर
35.	—	सं० एल-12012/42/83-डी-4(ए) दिनांक 6-2-1984	दी कर्नाटक बैंक लि० हैड आफिस, मणिपाल
36.	—	सं० एल-12012/202/83-डी-II(ए) दिनांक 2-2-1984	बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र और कर्मकार

[सं० एस-11025/4/83-डी-4(बी)]

ORDER

New Delhi, 22nd February, 1984

S.O. 1087.—Whereas the industries disputes specified in the Schedule hereto annexed are pending before Shri V.H. Upadhyaya, the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bandalore;

And Whereas the services of Shri V.H.Upadhyaya are no longer available ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A read with sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal, the Presiding Officer of which shall be Shri B.N. Lalage with headquarters at Banglore and withdraws the proceeding in relation to the disputes pending before the said Shri V.H. Upadhyaya, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bangalore and transfers the same to Shri B.N. Lalage , Presiding Officer, Industrial Tribunal Bangalore with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sr. No.	I.D.No.	Number and date of the Order of the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Name of the Parties
1	2	3	4
1.	4/73	No. L-29011/40/73-LR-IV dt. 29-9-73	Workmen and the management of M/s. Tungbhadra Minerals (P) Ltd., Tranagar Post Office.
2.	4/75	No. L-26012/9/74-LR-IV D.O. 3(B) dated 26-2-75.	Bharat Gold Mines Ltd., K.G.F
3.	10/75	L-12012/18/73-RL. III dt. Sept., 1975	Syndicate Bank Manipal.
4.	6/76 (Central)	L-12012(85)/76-D. II(A) dt. 19-8-76	Vijaya Bank Ltd., Banglore.
5.	7/76	L-43912/676-D. IV(B) dt. 4-9-76	Bharat Gold Mines Ltd., K.G.F.
6.	3/77	L-17012/375-D. II(A) dated 7-5-76	National Insurance Co. Ltd., Bangalore.
7.	7/78	L-12011/94/78-D. II(A) dt. 21/27-9-78	Corporation Bank Ltd., Mangalore.
8.	7/80	L-29011/59/79-D. III(B) dt. 24-9-80	Bagalkot Udyog Ltd., Bagalkot, Bijapur Dist.
9.	1/81	No. L-12011/9/80-D. II(B) dt. 29-1-81	Corporation Bank, Hubli.
10.	2/81	L-26012/9/89-D. III(B) dt. 29-1-81	Kudremukh Iron Ore Co. Ltd., Bangalore.
11.	--	No. L-12012/37/80-D. II(A) dated Nil	State Bank of Mysore, Bangalore.
12.	4/81	No. L-45012/1/80-D. IV(A) dated 28-2-81	New Mangalore port Trust, Mangalore.
13.	6/81	No. L-12012/74/80-D. II(A) dt. 2-4-81	Canara Bank.
14.	6/75	No. L-27011/4/74-D. IV(B) dt. 4-3-75	Sandur Manganese & Iron Worker (P) Ltd., Bellary Distt.
15.	3/82	No. L-17015(1)/81-D. IV(A) dt. Nil	Life Insurance Corporation of India, Bangalore.
16.	4/82	No. L-12011(28)/81-D.IV(A) dt. 26-4-82	Krishna Grameena Bank Ltd., Gulbarga.
17.	6/82	No. L-126012/9/81-D. III(B) dt. 3-8-82	Kudremukh Iron Ore Co. Ltd.
18.	7/82	No. L-45015/2/78-D. IV (A) dt. Nil	New Mangalore Port Trust, Mangalore.
19.	8/82	No. L-12011/75/81-D. II(A) dt. 17-8-82	Karnataka Bank Ltd., Mangalore.
20.	9/82	No. L-12012/1282-D.IV(A) dt. Nil	Karnataka Bank Ltd., Mangalore.
21.	10/82	No. L-43012/5/81-D. III(B) dt. Nil	Hutti Gold Mines Co. Ltd., Hutti, Raichur Distt.
22.	11/82	No. L-43012(3)/82-D. III(B) dt. Nil	Bharat Gold Mines Ltd., K.G.F.
23.	12/82	No. L-12012/14/82-D. IV(A) dt. 30-12-82	Bharat Gold Mines Ltd., K.G.F.
24.	1/83	No. L-12012/19/82-D. IV(A) dt. 8-3-83	Karnataka Bank Ltd., Mangalore.
25.	2/83	No. L-12012/34/82-D. II(A) dt. 4-4-83	Malaprabha Grameena Bank, Dharwad.
26.	3/83	No. L-12012/101/82-D. II(A) dt. 31-3-83	Cauvery Grameena Bank Ltd., Mysore.
27.	5/83	No. L-26011/8/82-D. III(B) dt. Nil	Kudremukh Iron Ore Co. Ltd., Bangalore.
28.	6/83	No. L-43011/9/82-D. III(B) dt. Nil	Bharat Gold Mines Ltd., K.G.F.
29.	7/83	No. L-29011/43/82-D. III(B) dt. Nil	Byrapur Chremite Mines Kambal Post, Hassan Distt.
30.	11/80	No. L-12012/46/80-D. II(A) dt. 20-11-80	State Bank of Mysore, Bangalore.
31.	—	No. L-43012/2/82-D. III(B) dt. 5-10-83	Bharat Gold Mines Ltd., K.G.F.
32.	—	No.L-45011(4)/83-IV(A) dt. Nil	The New Mangalore, Port Turst.
33.	—	No. L-12012/51)/82-D.II(A) dt. Nov. 83	The Syndicate Bank, Manipal.
34.	—	No. L-12012/41/83-D. IV (A) dt. 6-2-84	The Karnataka Bank Ltd., Mangalore.
35.	—	No. L-12012/42/83-D. IV(A) dt. 6-2-84	The Karnataka Bank Ltd., Head Office, Manipal
36.	—	No. L-12012/202/83-D. II(A) dt. 2-2-84	Workman and the Management of Bank of India.

[No. S. 11025/4/83-D.IV(B)]

New Delhi, the 19th March, 1984

S.O. 1088.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ningha Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited, P.O. Kalipahari (Burdwan) and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th March, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 43/82

PARTIES :

Employers in relation to the management of Ningha Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Kalipahari, Dist. Burdwan.

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri B. N. Lala, Advocate.

For the Workman.—Sri D. K. Verma, Advocate.

INDUSTRY : Coal STATE : West Bengal.

Dated, the 28th February, 1984

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(15)/82-D.IV(B) dated the 3rd May, 1982.

SCHEDULE

"Whether the action of the Agent, Ningha Colliery, M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Kalipahari, Dist. Burdwan in stopping allowance of Rs. 125 besides normal wages from April, 1973 and not regularising Sri Rambhaju Prasad as Traffic in Clerical Grade-III from 1973 justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. After filing the written statement the union or the concerned workman were not taking any steps for hearing of the case and were absent. Shri D. K. Verma, Advocate was representing the union and he took time on certain dates for hearing of the case. On 27-2-84, however, he submitted that he had written several letters to the union to come ready for hearing but they were not responding and they have no interest in the case and therefore the case may be disposed of.

3. It appears that there is now no dispute between the parties and hence a 'no dispute' award is passed.

J. N. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19012(15)/82-D. IV (B)]

New Delhi, the 19th March, 1984

S.O. 1089.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3 Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Parbelia Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Neuteria (Purulia) and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th March, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 38/82

PARTIES :

Employers in relation to the management of Parbelia Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Neuteria (Purulia).

AND

Their workman

APPEARANCES :

For the Employers.—Sri B. N. Lala, Advocate.

For the Workman.—Sri P. N. Ojha.

INDUSTRY : Coal STATE : West Bengal.

Dated, the 1st March, 1984

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(10)/82-D. IV(B) dated the 24th April, 1982.

SCHEDULE

"Whether the management of Parbelia Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Neuteria (Purulia) was justified in not regularising S/Shri Somwa Hari, Lachman, Chandan, Krishna, Syama and Dasarath as Sweepers in Cat. II with effect from 3-9-1980 with payment of back wages ? If not, to what relief the workmen are entitled ?"

2. On 1-3-84 both the parties have filed a joint petition of compromise duly signed on their behalf and they pray that an award be passed in terms of the settlement.

3. I have gone through the settlement which is beneficial for the workmen.

4. In the circumstances the award is passed in terms of the settlement which shall form part of the award.

Sd/-

J. N. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19012/10/82-D. IV(B)]

Enc : Settlement.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NO. 3, DHANBAD

In the matter of Reference No. 38 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Parbelia Colliery of Eastern Coalfields Limited.

AND

Their Workmen.

Joint petition of Compromise.

The humble petition of both the parties herein concerned most respectfully sheweth :—

1. That the above matter is fixed for hearing on 23-2-84.

2. That both the parties, in the meantime negotiated the instant matter mutually and have settled the instant matter, without prejudice to the respective contentions made in their written statements submitted before the Hon'ble Tribunal, on the following terms :—

(i) That S/Shri Sonowa Hari, Lachman, Chand, Krishna, Shyama, and Dasarath as named in the order of reference will be regularised as Sweepers in Category I with effect from 10-1-84 and each of them will be placed at the Basic rate of Rs. 21.16 per day as per NCWA.—III.

(ii) That regular payment on the Wages Sheet of the Colliery as per the rate stated in paragraph (i) above will be made with effect from 1-3-1984 and for the period from 10-1-1984 to 29-2-1984 the concerned workmen will be paid the balance, if any, arrived at between the payment entitled to as per the rate stated in paragraph (i) above and the actual payments received by them, purely as consolidated amounts with no other payments or benefit arising thereon, and that these consolidated amounts will be paid within two months from the date this settlement takes effect.

(iii) That the concerned workmen shall have no claim for any back wages or any benefits for any period prior to 10-1-84 and any such past period will be deemed as 'Dies non' and for all intents and purposes the concerned workmen will be deemed to have joined the service as on 10-1-1984, the date when the competent authority of the employers accorded approval of their regularisation.

(iv) That by this settlement the instant matter is fully and finally settled and the workmen shall have no other claim whatsoever on any matter arising out of the instant settlement.

(v) That this settlement will be effective as from the date it is accepted by the Hon'ble Tribunal as fair and proper and an Award is passed in terms of this settlement.

3. That both the parties pray that the Hon'ble Tribunal, may please be to accept this settlement is fair and proper and pass an Award in terms of the settlement.

And for this act of kindness, both the parties as in duty bound, shall ever pray.

For and on behalf of
the workmen.

Dated this the day of February, 1984.

(Sd/-) Illigible

For and on behalf of
the employer.

(Sd/-) Illigible

J. N. SINGH, Presiding Officer

New Delhi, the 13th March, 1984

S.O. 1090.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Punjab Region, Chandigarh and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th March, 1984.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH.

Case No. I.D. 25/83 CDH; 114/83 (Delhi).

PARTIES :

Employers in relation to the management of Food Corporation of India—Punjab region Chandigarh.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the employers—S/Shri B. L. Laroiya and S. K. Bhowmik.

For the Workmen.—Shri P. K. Singla.

INDUSTRY : Food Corporation of India. STATE : Punjab

AWARD

Dated the 1st of March, 1984

The Central Govt., Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act, vide their Order No. L-42011/17/82/FCI. D. IV(A) dated the 4th of November, 1982 read with S.O. No. S-11025 (2)/83 dated the 8th of June, 1983 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Food Corporation of India, Punjab Region, Chandigarh in denying and curtailing facilities of supply of torches, cells, gum boots, PT shoes and overcoats/great coats to their Class IV employees working at District Sangrur, is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

2. To trace a short history of the matter, the petitioner/Workmen consisting of the Watchmen/Dusting Operators and other similarly placed Class IV employees, serving under the Respondent Corporation in Dist. Sangrur, complained that as a matter of job requirement they were obliged to use torches, boots, PT shoes, and overcoats/great coats as a part of their uniform, because every day they had to open the godowns, keep them neat and clean, guard them against vagaries of weather, risks of fire, theft, vandelism and other such eventualities. Moreover a considerable part of the under health area was snake infested and to keep it operational they required vigorous-precautious and hence the need for the extra equipment. It goes without saying that they had to perform a round the clock duty through out the year, irrespective of the vicissitudes of Nature. It was pleaded that despite the essential nature of the aforesaid items and their persistent entreaties the management failed to provide the same even though at one stage the Senior Regional Manager, FCI. (Punjab region) had conceeded the point. They, therefore, raised an Industrial dispute which could not be settled in the conciliation proceedings even on the intervention of the A.L.C.(C) and hence the Reference.

3. Resisting the claim on all counts, the management avered that sufficient number of torches had been provided to the night duty watchman according to the requirement and for the better safety of stock even though there was proper lighting arrangement in each depot of the District; that whenever any snake rouble was observed casual labour was hired from time to time to remove such nuisance from the depot to avoid any infestation, but all the same they were ready to supply gum boots provided the Watch and Ward staff, deputed in the concerned depot, was willing to take them in place of the ordinary boots. It was propounded that the Watchmen were being given summer as well as winter liveries alongwith woollen Blankets as per Instructions which did not permit the grant of overcoats/great coats. They pleaded that they were not obliged to supply PT shoes to the Dusting Operators who were otherwise eligible to special allowance. Projecting their bona fides an sympathetic attitude towards the petitioner-workmen the management contended that on

receipt of the representation from the Secretary of the Union regarding the non-supply of livery articles they issued instructions to the District Manager Sangrur to look into the grievance and arrange the supply of liveries, if due.

4. Since the respective pleadings of the parties were fully covered under the terms of reference, therefore, they were called upon to adduce evidence. In support of their case the petitioners examined their authorised representative Shri P. K. Singla whereas the management produced their Deputy General Manager Shri S. K. Bhowmik. Of course, both the parties also filed a few documents.

5. On a careful scrutiny of the entire material on records and hearing the parties I am inclined to sustain the petitioners' claim to a considerable extent because even in their written Statement the Respdt. management did not categorically deny their entitlement to the grant of functional Uniform including torches, cells and gum boots. They rather came out with a sort of evasive reply that inspite of sufficient arrangement of light in each depot, torches were being provided to the night-duty Watchman in accordance with the requirement and the rules. Strangely enough, they neither elaborated the requirement nor the rules. Similarly it was conceded that there was some sort of snake-infestation, or atleast a risk of it, and that was how that casual labour was being hired to remove such nuisance from time to time; but they were still willing to give gum boots to the Watch and Ward Staff provided the latter give up their claim to the ordinary boots. In the same sequence petitioners' entitlement, to summer and winter uniforms/liveries including the Blankets, was also admitted with the rider of Instructions which again remained unrevealed; and it goes without saying that the deposition of their Dy. General Manager Sh. S. K. Bhowmik was more or less on the lines of their pleadings.

6. On the other hand the petitioners had some positive evidence to clinch the issue. Letter Ex. W. 6 dated 26-12-1977 shows an admission of the then Dist. Manager to their Dy. Manager (Admn.) in their "inter se" official correspondence that least Samana, Khannauri and Ahmedgarh depots of Sangrur Dist. were snake infested. Circular Ex. R. 1 dated 25th of Feb., 1977 issued under the authority of the Dy. General Manager (Gen.) from the New Delhi H. O. should leaves no manner of doubt that in such type of areas the Workmen were entitled to gum boots in lieu of Chhapal/Shoes. And perhaps that was the reason that in his letter Ex. W. 2 dated 3-8-1980, the Asstt. Manager (Gen.), speaking for the Sr. Regional Manager, directed the Dist. Manager of Sangrur to arrange the supply of gum boots and PT shoes without any loss of time. In the same sequence he also directed for the immediate issue of torches and cells (twice in a month) to all the Workmen.

7. Shorn of explaining such admissions in the aforesaid documents, the Managament appears to have accepted the demands of the workmen even at the time of their Joint Meeting on 27-7-79 as should be evident from its minutes Ex. W. 4 and the consequent action in constituting a committee for the purchase of the relevant items vide office Order Ex. W.5.

8. The logical inference would, threfore, be that the management had no justification in frustrating the petitioners' in so far as it related to the demand of torches, Cells (twice in a month), gum boots in lieu of Chhapal, and PT shoes. However, regarding their claim to overcoat and great coat, I feel that it devoid of force for want of support from any positive or direct evidence. They primarly reply on the settlement Ex. W.7. between the Dist. Manager Hosiarpur Depot and the Concerned Union. In my considered opinion, it can not be pressed as a precedent on the Sangrur Depot for the simple reason that they were not a party to the said agreement. And in so far as the livery Rules of the Respdt./ Management are concerned they are quite categorical about the supply of Blankets in preference to the overcoats or great coats as a part of Winter Uniform. It is besides the point that in any future bipartite settlement or at the time of revision of rules, the management may be better advised to go in for a change to ensure greater efficiency in the job performance.

9. To suffer a little deviation, according to the management the Workmen's cause was not properly espoused, because the Union through whom they had raised the dispute did not command sufficient majority of the Workmen. An attempt was made to file an affidavit of one Sat Pal to support the objection. But the exercise did not impress me because the document was not attested by any oath commissioner or judicial functionary. Moreover, it was submitted during the course of arguments without affording any opportunity to the petitioners to test the credibility of the deponent on the touch stone of cross-examination; on the other hand the statement of petitioners' representative Shri P. K. Singla was more than indicative of their majority and legitimacy of the action in espousing the cause.

10. Thus to sum up my aforesaid discussion on the limited available data and the points raised before me. I hold that the management had no justification in denying or curtailing the facility of supply of torches; cells (twice ina month), gum boots in lieu of Chappal/Shoes, and PT shoes to their Class IV employees working in Sangrur Depot even though there was nothing wrong with their action in rejecting the demand for overcoats/greatcoats.

11. As such, I return my Award accordingly.

Chandigarh.
Dated the 1st of March, 1984.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-42011/17/82/FCI|D. IV(A)|D(V)]

C. D. BHARDWAJ, Desk Officer

New Delhi, the 15th March, 1984

S.O. 1091.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Pandaveswar Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th March, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 30/82

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Pandaveswar Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P. O. Pandaveswar, Dist. Burdwan.

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers.—None.

For the Workman.—Shri N. Laik, Advocate.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dated, the 29th February, 1984

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them u/s 10(1)(c) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(79)/81-D. IV(B) dated the 23-3-82.

SCHEDULE

"Whether the action of the Agent, Pandaveswar Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P. O. Pandaveswar, Dist. Burdwan, in stopping work of Sri Madan Mohan Karmakar, Blacksmith of Gangaramchak-Kankartala Unit with effect from Nov. '75 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The case of the workman as stated in the written statement filed on his behalf by the union is that the concerned workman Sri Madan Mohan Karmarkar was a permanent employee of Gangarmachak unit of Kankartalla Colliery which was taken over by the Govt. in the year 1974. The said workman continued to work as a Blacksmith in the said colliery even after take over upto October, 1975 but thereafter the management stopped him from work with effect from 1st November 75 without issuing any notice or assigning any reason. Several representations were made by the workman and the union but the management inspite of assurances did not reinstate him. An Industrial Dispute was then raised which ended in the present Reference. The workman was claimed his reinstatement with full back wages from 1-11-1975.

3. It may be stated that this case has been heard exparte and an exparte award is being passed under the circumstances mentioned below.

4. The Reference in question was registered on 8-4-82 and registered notices were issued to both the parties for submission of their [illegible] fixing 14-5-82. On 14-5 82 none of the [illegible] the case was adjourned to 21-6-82 for filing written statement. In the meantime the union filed their written statement on 10-5-82 but on the date fixed i.e. 21-6-82 no written statement was filed by the management and hence a fresh registered notice was issued to both the parties fixing 14-7-82. On 14-7-82 Sri R. N. Tewary, Dy. Personnel Manager of Pandeveswar Colliery whose Agent is a party to the Reference attended the Court and noted the next date fixed i.e. 11-8-82.

5. On 11-8-82 neither party was present and hence a last chance was given to the parties and a final notice was issued to them informing that if they do not pursue the case a no dispute award will be passed and accordingly fresh notices were issued fixing 15-9-82. On 15-9-82 Sri R. N. Tewary, Dy. Personnel Manager appeared for the management while Sri Faroque Hussian appeared for the union and both parties prayed for time. The management was directed to file written statement-cum-rejoinder by 12-10-82. On 12-10-82 the union was represented and Sri R. N. Tewary, Dy. Personnel Manager was also present for the management but he did not take any steps and the case was again adjourned to 19-11-82 and a fresh notice was issued to the management. On 19-11-82 Sri R. N. Tewary was present for the management and he submitted that a date may be given to him for submission of written statement and documents. The union was represented by Sri Faroque Hussain. Management was again given a chance to file their written statement and documents by 23-12-82.

6. On 23-12-82 though the union was present but none appeared for the management nor any step was taken though number of dates had been given to them. The case was fixed on 31-1-83 for hearing and the management was issued a registered notice to come ready for hearing on the date fixed. On 31-1-83 Sri N. Laik, Advocate appeared for the union and Sri R. N. Tewary for the management but he submitted that due to unavoidable reasons no written statement on behalf of the management could be filed and so a short date be given and as a last chance he was directed to file the written statement of the management as also the rejoinder on 15-2-83 with clear understanding that no further opportunity will be allowed. On 15-2-83 again Sri Tewary for the management was present but no written statement was filed by him and the case was adjourned to 30-3-83 for hearing. On 30-3-83 Sri N. Laik, Advocate filed his authority on behalf of the union Sri Tewary, Dy. Personnel Manager who was present for the management filed a petition with a prayer to add the General Manager Kankartala Area as a party to the reference as the Agent Pandeveswar Colliery was no longer an employer of the concerned workman in the dispute. According a notice was issued to the General Manager, Kankartala Area to show cause as to why he should not be made a party to the dispute, and the case was adjourned to 27-4-83. On 27-4-83 though the Advocate for the union was present and Shri Tewary was also present but no reply was received from the General Manager nor Sri Tewary filed any written statement. The union, however, called for certain documents from the management and the management was directed to file them before 8-6-83 the next date fixed for hearing. On 8-6-83 though the Advocate for the union was present but no step was taken on behalf of the management and the case was adjourned to 8-7-83 for hearing. On 8-7-83 the union's Advocate as also Sri Tewari were present but they were not ready and hence the reference was adjourned to 8-9-83 for hearing. On 8-9-83 again the management remained absent and a fresh notice was again issued to them fixing 7-10-83 for hearing. On 7-10-83 though Shri Tewary was present for the management and Sri N. Laik, Advocate for the workman, but they were not ready. They were, however, directed to come ready for hearing positively on 8-11-83. On 8-11-83 though the Advocate for the union was present but again the managemente reamained absent and the case was adjourned to 6-12-83 for hearing. On 6-12-83 the Advocate for the union was present and he filed certain documents but the management again did not appear and another notice was issued to them fixing 3-1-84 for hearing. On 3-1-84 Sri Abdul Sattar, P. A. to Sri R. N Tewary filed a petition for time on the ground of illness of Shri Tewary. The union pressed that the management had not even filed their written statement till date and were proceeding with the case reluctantly. Accordingly a fresh notice was issued to the General Manager, Kankartala also for taking proper steps in the case and the case was again fixed for hearing on 25-1-84. On 25-1-84 Sri Tewary again appeared and submitted that the case was likely to be settled and so a time be allowed. It was accordingly adjourned to 28-2-84 for filing settlement or for hearing of the case and the parties were directed to come ready for hearing.

7. Inspite of so many adjournments as mentioned above, on 28-2-84 again though the union was ready a time petition was filed duly signed by Sri R. N. Tewary, Dy. Personnel Manager praying for adjournment on the ground of his sickness. I fail to understand as to why inspite of so many adjournments the management did not even care to file their written statement far less from being ready to proceed with the case. If Sri Tewary was ill on certain dates the management should have taken steps to file their written statement as also documents though the Reference as pending since 8-4-82. This is one of the glaring instance which would indicate as to how the labourers are harassed by the management who wants to drag on the disposal of cases on some ground or other and though about two years have lapsed the management never cared even to file any written statement.

8. I do not think the Tribunal would have given any more chance to the management. In such circumstances the case was taken up for exparte hearing. The union examined the concerned workman as WW-1 who has stated that he was working as a Blacksmith in Kankartala Colliery since 1964 and he continued to work in this colliery even after take over and worked there till October '75. It is further stated by him that he was a permanent employee but he was stopped work with effect from 1-11-75 without assigning any reason and no chargesheet was ever issued against him. He therefore, raised the present dispute. The evidence of the workman is exparte and there is no reason to disbelieve him.

9. Considering his evidence and facts and circumstance of the case. It is held that the action of the management in stopping work of the concerned workman Sri Madan Mohan Karmakar Blacksmith with effect from November '75 is unjustified As he was stopped work without any reason, he is entitled to be reinstated with full back wages.

10. The award is given accordingly.

Sd/-

J. N. SINGH Presiding Officer

[No. L-19012(79)/81-D IV(B)]

C. D. BHARDWAJ, Desk Officer.

New Delhi, the 13th March, 1984

S.O. 1092.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Govt. Industrial Tribunal, No. II, Bombay the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Maharashtra, Pune and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th March, 1984.

TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/28 of 1983

Employers in relation to the Management of Bank of Maharashtra, Pune

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employer : Shri D. J. Bhanage, Advocate.

For the Workmen—Shri S. M. Dharap, Advocate.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 23rd February, 1984

AWARD

(Dictated in the Open Court)

By their order No. L-12012/17/83-DIII(A), dated 24-3-83 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the management of Bank of Maharashtra in relation to their Bajirao Road Branch Pune in depriving Smt. M. S. Tambe, Clerk from Special Allowance post is justified ? If not, to what relief is she entitled ?"

2. The facts giving rise to the present dispute shortly stated are that on 5th August, 1974 the Bank of Maharashtra issued a circular relating to allotment of special allowance post. Before that Smt. Tambe who is the workman concerned in the instant case was appointed in a clerical cadre of the Bank on 24-11-1969 and she would be governed by the Bipartite Settlement as laid in para 5.9. On 21-9-1982 and subsequently on 11-5-1982 the Manager of Bajirao Road Branch of Bank of Maharashtra, having experienced certain difficulties in day to day administration, issued the two circulars and the case of the Bank is that the employees would be governed thereby. There are some posts in the Bank which carry allowance may be a special allowance or not, Cashier is entitled to get Rs. 25 p.m. as cash allowance while the operators in machine section get a allowance of Rs. 134 p.m. as special allowance. On day to day basis special allowance comes to Rs. 4.35. In Bajirao Road Branch there are 13 machines and two operators are required to operate each machine. On 12-5-1982 which is the crucial date, Smt. Tambe was working in the machine section since some of the permanent incumbents were absent. Now after the issue of second circular dated 11-5-1982, the Manager by his order dated 12-5-82 asked Smt. Tambe to work in Cash Section as per his circular dated 29-1-1982 and 13-5-1982 till further instructions. To this Smt. Tambe replied by her letter of the even date asking for time to arrive at a decision. On receipt of this letter of request, the Manager by his letter dated 13-5-1982, treating the reply as a refusal to the office order, informed Smt. Tambe, accordingly to which she gave reply on 14-5-1982, and then on 25-5-1982 informed the Manager her willingness to accept the post but under protest. On 19-10-1982 the Manager issued a office order declaring the once a refusal amounts to always a refusal and therefore asked Smt. Tambe to revert back to her earlier section. Because of this declaration which is to amount to a permanent debarring, a dispute has been raised by the Union on behalf of Smt. Tambe. The Union who has espoused the cause state in their statement Ex. 2/W that this order of the Manager of the Bank is illegal and thereby Smt. Tambe has been deprived of the post of Machine operator to which she is otherwise entitled and on the strength of which she is entitled to get a special allowance.

3. The Bank has filed written statement at Ex. 14/M whereby it is contended that the reference itself is not tenable in law. They have also referred to the decision in Ref. CGIT-2/20 of 1983 dated 20-10-1983 and it is contended that during the pendency of the said dispute the Bank has issued a notice under Section 9A of the I.D. Act which is dated 22-2-1983 for effecting the change in condition of service and therefore now the present reference cannot survive. The correctness of the facts stated in para 11 to 15 of the statement of claim stands admitted. However it is urged that Smt. Tambe who was appointed in the Bank as Clerk was given the machine operator's post as and when required as per the seniority of the branch and that on 13-5-1982 a post of Cashier fell vacant, Smt. Tambe being seniormost was asked to take up the said post, since it was possible for the Manager to adjust the machine department work without the aid of Smt. Tambe. The Bank however stated that they are experiencing difficulties in day to day working of the branch because the employees are unwilling to take cash work which carries lesser allowance but additional responsibilities. Then they refer to the notice under Section 9A and it is stated that casual vacancies in the machine section are filled in accordance with seniority list as stated above and for the said purpose they maintain a pool of employees who can be allotted these posts.

4. On the strength of the following points arise for determination. My findings are :

ISSUES	FINDINGS
1. What is the effect of notice under Section 9A of the Industrial Disputes Act, 1947 dated 22-2-1983 on the rights of the parties ?	Nil
2. Whether the said notice has got retrospective effect so as to merge the Manager's circular in the said notice ?	No
3. If the notice has prospective force, will it be binding, legal and valid against the rights of Smt. Tambe and the Union, who is espousing the cause ?	Not in the present reference.
4. Whether the Union proves that Smt. Tambe was illegally deprived of the post carrying special allowance ?	Yes
5. If yes, is Smt. Tambe entitled to any relief ?	Yes
6. Was the action of the management justified ?	No
7. What award ?	As per order

REASONS

5. As the facts stand, the parties would be governed by the circular dated 5-8-1974 issued by the Bank Ex. 4/W which lays down the modalities as to how the allowance posts are to go. In the very opening para, viz. para. I, it is stated that all allowance posts go by seniority unless there is something adverse against or wrong with such person or he is unwilling to take the post. There are certain other guidelines also with which at this stage we are not much concerned. Now as the record shows, the Manager by his circular dated 29-1-1982 and then again by his circular dated 11-5-1982 Ex. 5/W and 6/W wanted to formulate a new policy and circulate the guidlines for the allotment of the allowance post wherein it was tried to be laid down that entry to the machine section will be only through cash section i.e. the staff member will not be eligible for machine operator's post unless he is working in the cash department and it was further tried to be laid down that declining to work in cash section will debar the staff member for any allowance post. The Manager did not stop but further stated that request for opting to go out of cash section or machine section will tantamount to one's right to abandoning allowance post except in the case of promotion. It is further stated in the event of a post carrying allowance falling vacant, the next eligible senior person in that cadre shall be asked to do the job and if all the eligible senior persons decline to work, the eligible seniormost person shall have to perform those duties. Now the legality and validity of the circulars issued by the Manager arose for consideration

in the earlier decided reference viz. Reference CGIT-2/20 of 1983, to which the Bank has made a reference in the written statement wherein two issues along with others were required to be considered viz. issue No. 1A—Whether there was a conflict between the circular of the Manager and the Head Office circular dated 5-8-1974 ? The finding on which was in the affirmative and there was another issue No. 2 which read—if yes whether the circular issued by the Manager is valid and legal ? and the finding was in the negative. It was held in the said Reference, the award in which is binding on the parties, that since the circular issued by the Manager was conflicting with the Head Office circular, it was bad and illegal since it was to introduce certain changes in the conditions of service as laid down by the Bank. Atleast uptill now nobody has gone in appeal or special civil application against the award and therefore it stands with all its legal effects.

6. Once we brush aside these two circulars issued by the Managers, they being not legal and valid and therefore not binding on employees, whatever might have been stated defining the term refusal, the same shall have to be ignored and effect shall have to be given to the Head Office circular dated 5-8-1974. Once this is done then the allowance post must go by seniority and unless there is evidence to show that Smt. Tambe was unwilling to take up the particular post, she could not have been deprived of the said post that too permanently as seems to have been done by the Manager in the instant case.

7. At the time of oral evidence as well as in the argument some different case is tried to be made out regarding the order dated 12-5-1982 Ex. 7/W. As the order reads it was a direction to Smt. Tambe to work in cash section but at the relevant time she was working in machine section and therefore eligible to have additional allowance. The second para of the letter says that refusal of the said order will debar her for any higher allowance post and she should submit the refusal in writing on the enclosed preforma. In the written argument what is tried to be contented as seen from page 4 is that Smt. Tambe would have been continued in machine section, if she had accepted to work, on cash on that date and some junior person would have been asked to work in cash and she would have been continued in machine section according to the seniority. This stand of the Bank means that they never intended to disturb Smt. Tambe, that they never intended to post her in cash section but only wanted an acceptance from her where upon she would have continued to work in machine section. The order of the Manager however as already stated reads something else and if the real intention behind the letter dated 12th was as presented in the argument, they could have very well stated in the letter itself which was not done and therefore it is a clear case of the intention being something different than what is appearing in the letter Ex. 7/W. The Bank should never have done accordingly and should have laid the cards on the table which they did not do and why is not clear. One fact therefore is certain that Smt. Tambe even according to the Bank was entitled to continue in the machine section. It is equally certain that her presence in the cash was not necessary and the Bank had alternate arrangement viz. to ask somebody who is junior to Smt. Tambe to go to cash section. If Smt. Tambe had a right by virtue of seniority to continue in machine section, if the Bank had suitable alternate arrangement, and if by going to cash section Smt. Tambe was to lose financially, I can not understand the reasoning behind the order to just solliting a consent without intending to enforce it.

8. The choice as the circular of 1974 says was to fall on senior person and the written argument indicates that Smt. Tambe had such right. The only question then remains is whether there was a refusal and further whether by virtue of such refusal, a permanent bar could have been created. So far as the circular of 1974 is concerned it does speak of unwillingness, but it does not speak of permanent bar which for the first time was introduced by the Manager in his circular which circular is struck down as bad and illegal. In reply to letter dated 12-5-82 Smt. Tambe who gave her letter of the even date Ex. 8/W mentioned the dispute then pending before the Dy. Commissioner of Labour and further requested to allow her some time to take a decision. The reaction of the Manager then was that he treated the letter as a refusal. Now if Sm. Tambe was not to be disturbed, if the Manager was thinking to appoint some junior person in the cash section, there was not that urgency as to foreclose the whole matter by treating the request for time as a total refusal and then to act accordingly. Shri Apte Bank's witness had stated that she had orally stated readiness to go to cash section. There is also a letter Ex. 11/W dated 25-5-1982 which speaks of acceptance but under protest. However bushing aside all these facts, by applying self created rule that once a refusal always a refusal the Manager sent Smt. Tambe back to her section, although there is an admission that normally Smt. Tambe would have continued to work in machine section, I have gone through the correspondence and I am not prepared to accept the contention of the Bank that Smt. Tambe had refused as to invoke the penalty tried to be imposed. The circular of the year 1974 speaks of the refusal of the allowance post. Smt. Tambe had never refused to work in cash section. The post of a Assistant Cashier which Smt. Tambe was to hold is not a allowance post under Bipartite Settlement and therefore having regard to all the circumstances above discussed, at no point of time Smt. Tambe could have been deprived of the machine special allowance which she was earning, where which she was willing to work and particularly when the management merely on paper for the reasons best known to them wanted a written consent to act as a Cashier. When she had accepted the service, she shall be deemed to have undertaken to carry out the service as may be entrusted to her. Therefore had she not been working in machine section then, it was incumbent on her to go to cash section but once her right to work in machine section is recognised by asking her to work there, by virtue of seniority in the branch, and once suitable arrangement was possible by sending some junior to her to cash section, the request for time or acceptance under protest could never have been used to forestall Smt. Tambe's right to continue in machine section.

9. I, therefore, hold that till the time there was vacancy in machine section in her own right Smt. Tambe should have been allowed to continue there and since the action of the management in depriving her of the said right is not justified, Smt. Tambe gets all the reliefs available to her.

10. There is subsequent issue of notice of change, but in the first place it cannot have a retrospective effect and secondly since a dispute has been raised under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, unless that dispute is resolved proposed change cannot be implemented. At least the Bank to avoid any complications further and similar monetary claims should wait till the conciliation proceeding which is pending before the Conciliation Officer ends.

11. In the light of the above discussions, therefore, Smt. Tambe is entitled to get the special allowance of the machine operator's post from 19-10-1982 till she is posted there or she forefeits her right for any reason, as and when there was a vacancy in the machine section during this period. It is not her fault that she did not work in machine section during this period. There is no bar in her path in appointing her in machine section as held by the management.

No order as to posts.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer.

[No. L-12012/17/83-D.II(A)]

Dated : 28-2-84.

S.O. 1093.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Patiala, Patiala and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th March, 1984.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGAH.

Case No. I.D. 170/83 (N. DELHI), 10 of 1983 CHD

PARTIES :

Employers in relation to the Management of State Bank of Patiala, Patiala.

AND

Their Workman—Mrs. Kamlesh Kumari.

APPEARANCES :

For the Employers.—Sh. B. K. Gupta.

For the Workman.—Sh. T. C. Sharma.

INDUSTRY : Banking. STATE : Punjab.

AWARD

Dated the 1st of March, 1984

The Central Govt. Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act, vide their Order No. L-12012|52|82|D.II(A) dated the 17th of March, 1983 read with S.O. No. S. 11025(2)/83 dated the 8th of June, 1983 referred the following Industrial dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the management of State Bank of Patiala in relation to their Sangrur Branch in terminating the services of Mrs. Kamlesh Kumari, Cashier-cum-Clerk with effect from 28-5-77 and in not allowing her opportunity of re-employment in the Bank, is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. According to the petitioner|Workman, on recruitment by the Respondent Bank she served them as a Clerk-cum-Typist at their Sangrur Branch w.e.f. 1-3-1977 to 28-5-1977, with a forced break from 1-5-1977 to 5-5-1977 and was paid her wages as per scales provided in the Desai Award read with the provisions of the Bi-partite Settlement binding upon the parties. It was avered that the petitioner was recruited for a work of permanent nature but the management gave her temporary employment and then illegally removed her from their rolls in a highly arbitrary and improper manner, even though some of her junior were retained in service; without assigning any reason, moreover no prior notice or compensation etc. was paid to her. It was projected that the petitioner's work and conduct during the aforesaid period of her employment under the Respt. was commendable.

3. Elaborating her grouse, the petitioner submitted that after the termination of her services the Respt. Management employed a large number of persons in the same cadre without affording her an opportunity of re-employment. Thus alleging violation of the provisions of Section 25-B; 25-F; 25-H; and 25-G she raised an Industrial dispute which could not be settled amicably despite the intervention of the A.L.C. (C) during the Conciliation proceedings and hence the reference.

4. Contesting the proceedings on all counts, the Respdt. Management contended that the petitioner was employed on purely temporary basis for a fixed duration to meet the momentary exegencies from 1-3-1977 to 28-5-1977, and since she had not put in 240 days continuous-service in the preceding 12 Calender months, therefore, she was not entitled for any prior notice or retrenchment benefits, including the preferential treatment in the matter of re-employment. For the obvious reasons they denied infringement of any provisions of the Act and questioned the propriety and validity of petitioner's claim.

5. Since the respective pleadings of the parties were found fully covered under the terms of reference, therefore, they were called upon to adduce evidence. In support of her case the petitioner examined herself whereas the mangement produced their Branch Manager Sh. Sant Singh had filed Exh. M-2 and Exh. M-3 of the Recruitment Rules.

6. I have carefully perused the entire material on records and heard the parties. On behalf of the petitioner it was vehemently argued that since her work and conduct were found satisfactory, and according to the common case of the parties she was fully qualified for the job, therefore, there was no justification in dispensing with her services in preference to the newly recruited raw hands. In the same sequence it was submitted that according to the Desai Award, broadly speaking, there could be only two categories of Workmen employed in the Banking Industry i.e. (A) Clerical and (b) Substaff consisting of the Class IV employees; meaning thereby that a person serving in the Clerical staff enjoyed the same category with his/her co-workers, irrespective of the status or degree of their permanent, probationary or temporary tenure, with the result that the management was obliged to adhere to the time honoured principle of "Last come first go" envisaged by Section 25-G. My attention was drawn towards the cases of Abdul Rahiman Vs. D'v. Sundt. S. Rly. 1981, Lab. I.C. 217, Union of India and Ors. Vs. Mahavir Parsad 1982 (1) Services Law Reporter 166 and Surinder Kumar Verma Vs. Central Govt., Industrial Tribunal 1981(1) Labour Law Journal 386 (S.C.).

7. In spite of seeming attraction, the effort of the Id. Representative of the workman failed to carry conviction with me; even though there is no dispute with the legal proposition projected by him. The pertinent point is that the judicial precedents cannot be invoked blindly despite their blinding nature as it is often observed that there is some slight difference in the facts of the two given cases, which, when apprised critically, may prove crucial to call for an entirely different adjudication.

8. In the matter of Abdul Rahiman, His Lordship was dealing with a situation where out of one common lot of Casual Labourers, Administration was found guilty of carving out a special class of "Out of turn appointees" for the purpose of regularisation of their services whereas the cases of Mahavir Parsad and Surinder Kumar Verma related to the implications of "Continuous Service" and the "retrenchment benefits" envisaged under Section 25-B and 25-F.

9. At the risk of repetition it may be pointed out that in our case, on her own showing, the total length of service put in by the petitioner did not exceed 84 days and, that too, with an in between break of 5 days. In her claim statement it was projected that the said break was a forced one but for the reasons better known to her, she did not reiterate the allegation either in her affidavit or the oral deposition.

10. In my considered opinion since her total length of service was far less than the statutory requirement of 240 days, therefore, she was not entitled for the retrenchment benefits elaborated in Section 25-F of the Act. Similarly her grouse of any infringment of Section 25-G by the Management is also devoid of force because barring her wild and vague allegation that some of her juniors were retained in service or that new and raw hands were recruited after her termination, there is not even an iota of evidence to support the charge. So much so that she could not disclose even a single instance of positive nature.

11. As a matter of fact, by necessary implication, Desai Award stands superceded by Shastri Award, which formulates different classifications of Employees. It categories and places a temporary employ at an inferior position than a permanent hand as well as a probationer. Similarly its Articles 522 and 524(1) provide sufficient justification for the action of the Management in disengaging the petitioner without any formal notice, or compensation in lieu, thereof. The question of her good conduct and the absence of any departmental proceedings was quite irrelevant since no insinuation was ever raised by the Management. To be precise the innocuous termination arose for want of work with the Management and was without any stigma.

12. However in so far as the petitioner's effort to seek priority in the matter of re-employment by virtue of Section 25-H it concerned, I feel inclined to sustain her cause despite a serious objection of the Management on whose behalf, it was contended that since she had not put in one year's continuous service within the meaning of Section 25-B therefore, she was not entitled for such benefit. They relied on Rules 76 and 78 to support the view point.

13. Seemingly the aforesaid Rules do contain a rider to the affect that the claimant workman should have put in a minimum service of 240 days in the preceding 12 calender months but one has to bear in mind that the Rules are a sort of tributory or channel sprouting from the Section as their source. In other words, they are sub-servient to the Sections and have no over-riding effect on them.

14. As a matter of fact the point in issue requires appraisement within the frame work and total scheme of the Enactment "Retrenchment" as defined by Section 2(oo) is wide enough to include the termination of an employee recruited on Temporary, Ad hoc or even fixed tenure basis. For my views I draw support from the observations in the cases of Mohan Lal Vs. Management of M/s. Bharat Elec. 1981(2) S.L.R. 11(SC) and Nawa Shahr. Central Coonerative Bank Ltd. Vs. Lab. Court Jullundher (57) ; 1980 Ind. Jour. Reports 206.

15. In the later case His Lordship was dealing with a situation where a person was employed on ad hoc basis for a period of 3 months whose tenure was extended by another

2 months on different occasions before the termination with the afflux of time. In short, he had not completed 240 days service in 12 Calender Months. When the Industrial dispute arose between the parties, the concerned labour Court allowed his prayer for a preferential treatment in the matter of re-employment by virtue of Section 25-H and this proposition was approved by the High Court, I find no reason to walk out of the ratio of the Case.

16. Section 25-F imposes certain statutory obligations on an Employer towards a retrenched workman who had put in a minimum continuous service of one year as defined by Section 25-B. But significantly enough no such qualification was required of a workman seeking re-employment with the aid of 25-H. To put it in other words, in its wisdom the Legislature laid down that a retrenched workman seeking monetary benefits of retrenchment within the purview of Section 25-F must have put in a minimum of one year's continuous service where as no such pre-condition was imposed in his attempt to seek preferential treatment in the matter of re-employment by virtue of Section 25-H; and I refuse to believe that the Legislature lacked the imagination to appreciate the distinction arising out of the missing phraseology.

17. On behalf of the Management it was urged that in view of the Rules of Recruitment Exb. M.2. and M.3. they could not possibly consider the proposition of petitioner's re-employment till she qualifies the reguisite written test. But the objection failed to carry conviction with me because as a necessary implication of Section 25-J the Recruitment Rules must give way to the Legislative mandate of Section 25-H.

18. Since no other point was raised before me; therefore, to sum up my aforesaid discussion on the entire available date, I find no illegality or impropriety etc. in termination of the petitioner's services by the Respdt. Bank Management and to that extent I return my Award against her, but keeping in view the statutory intent of Section 25-H, I direct the Management to afford her due opportunity, of course subject to suitability and eligibility, in the matter of re-employment.

CHANDIGARH

Dated the 1st of March, 1984.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-12012/52/82-D.II(A)]

S.O. 1094.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank, Bhopal and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th March, 1984.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE (RETD.) PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

Case No. CGIT/LC(R)(18) of 1982

Employers in relation to the Management of Punjab National Bank, Bhopal.

AND

Their Workman.

PRESENT :

Shri M. L. Sabharwal—for the workman

Shri R. P. Razada—for the management.

INDUSTRY : Banking. STATE : M.P.

DISTRICT : Indore. Date of decisions : 23-2-1984

AWARD

By this reference under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government vide notification No. L-12012/314/80-D.II(A) dt. 3-2-1982 has referred the following question for adjudication :—

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, Bhopal in relation to its Mhow Cantt. Br. in not appointing Shri V. R. More, Clerk as permanent Teller with effect from 29-12-1979 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?".

2. More was initially appointed in the Punjab National Bank services on 21-9-1949 in subordinate cadre as a Peon and worked in the same cadre upto 19-9-1966. Subsequently, he was promoted as Cashier-cum-Godown Keeper in the clerical cadre with effect from 20-9-1966. He continued in the same capacity upto September, 1976 and thereafter his designation was changed on his own request to Clerk-cum-Cashier vide Regional Manager's office letter dated 23-9-1976. In about August, 1977, he was transferred from Ratlam to Mhow Cantt. on a request made by him. It is undisputed that during his tenure in the subordinate cadre and subsequently as Cashier-cum-Godown Keeper from 21-9-1949 to September, 1976, he had no occasion to work on ledger keeper during this period. So far these facts are not in dispute.

3. On 29-12-1979 vacancy arose of a post of permanent Teller in the Mhow Cantt. branch. The post has to be filled in accordance with the policy laid down in the Settlement of 1973 between the Punjab National Bank and All India Punjab National Bank Employees Federation. The relevant terms of the Settlement referred to as 2-73 are reproduced below :—

"Selection of Tellers

1. The selection of tellers shall be made on the basis of the priority marks determined with reference to the length of service and educational qualifications as prescribed in this settlement relating to the promotion as Special Assistants subject to the condition that the candidate should have atleast one year's experience as ledger keeper. If, however, persons with requisite experience are not forth-coming, those with longest service as ledger keeper shall be given preference.

2. The selection of tellers shall be made on the basis of town as a unit.

3. The priority marks shall be determined as on 1st October as provided in the Settlement referred to above.

4. One year's ledger keeping experience shall be counted as on the date when the vacancy is filled. For illustration : a permanent vacancy is to be filled on 7-7-1974. In that case the priority marks as per priority list on 1-10-73 are to be taken into account for determining the seniority. For the purposes of counting ledger keeper's experience as gained upto 7-7-74 is to be taken into account.

5. The ledger keeper's experience for the purpose of selection of clerks as tellers shall relate to Current, Savings Fund, Fixed Deposit, Cash Credit, Overdraft ledgers and experience on Recurring Deposit Ledgers only.

6. The refusal to officiate or to accept permanent posting as a teller shall result in debarring the employee from officiating and permanent posting as teller for full one year. In case of refusal to accept permanent posting debarring shall commence ten days after the date of offer and in case of refusal to officiate from the date of refusal."

4. According to the management, at the relevant time when the post was to be filled on 29-12-1979, more did not have the requisite experience of one year as ledger-keeper. He could not, therefore, be considered for selection for the post. This, however, is the point of difference between the workman and the management. The Union representing the workman contended that the management was bound to take into consideration the Sundays, the Bank holidays and also the leave days without loss of pay of the workman while reckoning the length of the experience as ledger keeper. If these are taken into account the number of days would exceed 365 days. However, if such days are excluded, the total experience would work out to be less than 365 days.

The question, therefore, is as to what interpretation should be placed on the expression 'one year's experience as ledger keeper' occurring in the clauses 1 and 4 of the Settlement quoted above. The management has filed documentary and given oral evidence to show that More was wholly incompetent to shoulder the responsibilities of a teller and therefore being unfit could not be promoted. The Bank's justification here as to the competency of a probationer clerk was of importance but I would have to be guided by the Settlement terms which have been fully reproduced above and I do not find any thing in them that would warrant consideration of such matter in judging the justifiability of not promoting more. The voluminous evidence produced to show incompetence is wholly misplaced here and will have to be ignored by me.

More was the senior most clerk on 29-12-1979 at the branch and in all the branches of the town. In Ex. W/16, More has given an account of the experience as ledger keeper from 1977 to 29-12-1979. This stand is further reiterated by an affidavit sworn on 23-11-1982. A perusal of this statement would show that he claims to have worked on Recurring Deposit ledger on 364 days. Then he claims to have done work on 15 Sundays, thus making the total to 379 days. He also claims that he had worked as teller for 4 days from 29-10-79 to 31-10-79 and for one day on 7-11-1979. Thus, according to him, he had had experience of 383 days as ledger keeper. This position is not accepted by the management. They have also filed a list of the days on which More had worked as ledger keeper. They had deputed Shri N. K. Misra an officer to find it out and this officer after personally checking and verifying the number of days More had worked as ledger keeper had given a list of dates on which he worked as ledger keeper. Shri N. K. Mishra who had been entrusted with the job had given the entire list of the days of working as ledger keeper by More and the manner in which he discharged these duties, from 20-7-1978 to 29-12-1979. This Ex. M-28 is a reliable list and gives the actual working dates of the workman as ledger keeper. A date-wise detailed chart of his findings is given at the end of the list. On some of the days, More besides himself had worked along with others. The experience seems to be only on recurring deposit ledgers. From the note given by Mishra it is clear that during 12 days of Sundays service as claimed between period 19-10-77 to 16-7-78. More had been given the duties of a Head Cashier, and he had done the posting of vouchers only on 6 days and on the remaining 6 days, the posting of ledger work was either not done or it had been completed with major assistance given to More. On the basis of the verification, Mishra found that More had worked on recurring deposit ledgers (mostly posting of credit vouchers) for 187 days, on Sunday service posting of S.F., C.A., R.D., etc. 6 days, on recurring deposit ledgers jointly and in calculating interest etc. and closing accounts with the asistance of other staff members for 26 days. Therefore, even if all the experience on ledger working of More is taken into consideration whether done by him singly or jointly it does not exceed 219 days, and even if 6 days more are added it will work out to 225 days. In his evidence More admitted that list given by him includes the Bank holidays and Sundays and his earned leave. He stated that the 383 days are inclusive of bank and general holidays and days of his absence on leave. He was again asked to clarify in his cross examination that when he was working as Head Cashier on Sundays how could he have worked on ledger on those days and he replied that on those Sundays he used to work both as Head Cashier as also worked on the ledger. I need not go into the question of the possibility or the truth of the statement made for even then the number of days would work out to 225 days. The question therefore boils down is whether in terms of the Settlement More was equipped with the necessary experience as ledger keeper. A 'year' has been defined under General Clauses Act to mean as 365 days. The intention appears to be that before qualifying for the post of a teller the candidate must have gained experience by actually working on ledgers. Now the experience could only be gained by physically working and the period of holidays should not be added to such period of work. The ledger work is given to such senior clerk as and when a vacancy arises or with increase in the work. More had not been given any appointment as such to work on a ledger for a year. But as has been seen earlier he was a clerk-cum-cashier and the management had giving him the ledger work whenever they found his services could be utilised either because there was extra work to be done or some one had absented himself. In such situation it is not permissible to include the leave period or the holidays in the number of days the clerk had worked on ledger. It would be further seen that the Mhow bank had been working on Sundays and the work done on Sundays cannot be twice counted i. e. to say he may have worked on ledger on a Sunday and he was quite right in including this days as one on which he had gained the experience as a ledger keeper. But to this again another day cannot be added because normally a bank employee was entitled to off day on Sunday and for the purposes of pay, pension, increment and seniority such holidays must not be taken into account. The two concepts are entirely different, and the experience gained and the length of service.

7. The Manager has explained why he had been given the opportunity to work as a teller despite the fact that More had not the requisite experience. This was because More had represented to him that he had already had the experience and the management, it appears permitted him to work as a teller because he was the seniormost clerk. When however, Khanuja took an objection that More did not have the requisite qualifications, i.e., he has not the experience of one year, he was withdrawn from the post. This is quite understandable, and the management would not be estopped from challenging the position that More did not have the requisite experience of a ledger keeper merely because they had permitted him to work as teller on th footing that he had the necessary experience. Subsequently, when More had in fact completed one year's experience, the management had offered him to work as teller but now More had hesitated to accept it as in his opinion he had already completed the one year's experience and his acceptance may prejudice the case.

8. It was pointed out that the word 'experience' could not be given one meaning when it occurs in the same settlement in sub-para (b) of para 1 relating to promotion as Special Assistant and a different meaning when the Settlement deals with selection of Tellers in paragraph 1. The fallacy in the argument can easily be seen. To begin with the two terms are different and the provision of one cannot be imported into the other. This confusion was noticed in the argument in the case. The two terms of Settlement are independent dealing with separate topics and there is no warrant for reading the clauses of one into another. The one deals with promotion as Special Assistant and the other selection of Tellers. But even otherwise there is no antithesis between the meaning assigned to the expression 'experience' occurring at both the places pointed above.

9. It would appear from sub-paragraph 1 that the selection of Teller would have to be made on the basis of priority marks determined with reference to length of service and educational qualifications as prescribed in the Settlement relating to promotion as Special Assistant subject to the condition that the candidate should have atleast one year's experience as Ledger Keeper's. This expression again occurs in paragraph 4 wherein it is stated that the duration of Ledger Keeper's experience as gained shall be counted as on the date when the vacancy is filled. Sub paragraph 5 deals with what would be Ledger Keeper's experience for the purpose of selection of Clerk as Tellers.

10. The expression 'experience' has also been used while dealing with the promotion policy of Special Assistant in the same Settlement. Pargraph 1 relating to promotion as Special Assistant, of the Terms of the Settlement says that an employee coming higher in the priority list and not assessed as 'below average' shall be promoted subject to certain conditions. Condition No. (a) lays down that such candidate must have continuously served (emphasis supplied by me) in clerical cadre for a minimum period of 7 years and on clerical duties for a period of atleast two years. Seven years' period, may be reduced suitable in the areas where persons of this minimum service are not available. Now, the language used does not present any difficulty. Continuously served for a minimum period of seven years in clerical cadre, and on clerical duties for a period of atleast two years as a Clerk refer to continuous officiation in clerical cadre for a period of seven years and officiation for a minimum period of two years as a Clerk. During such officiation, there would be bank holidays, leave days, Sundays all according to service conditions. These days would undoubtedly fall within the span of seven years and they cannot be excluded from the length of service of the employee. If the holidays fall during the officiation as Clerk they would not reduce the length of officiation. In such cases what is required is that the candidate served for a span of two years and when it is said that he will serve for a minimum period of two years as Clerk the broken periods of service must be added to know the length

of service. It has, however, to be remembered that it is the span of service that is material.

"The holidays and non-working days and even the leave days cannot in such cases be excluded from such officiation. This has been made further clear while dealing with the length of service in the same agreement clause. Sub para 2 (f) lays down that leave without pay shall be deducted from total length of service only in those cases where increment have been deferred for such period of leave on loss of pay. This is what is to be excluded and the exclusion has to be from the total length of service. It would not cause interruption in the service but would merely be excluded or not counted while computing the length of service. We have, therefore, the concept of the length of service which is to be taken into consideration in paragraph 1. Now, sub-paragraph (b) says that the condition of two years' clerical experience (emphasis supplied by me) shall not apply in case of employees having worked for seven years in the clerical cadre, and carrying composite designation of Clerk-cum-..... The two years' experience alluded to here makes a reference of the length of service provided in clause (a) stated above. The clerical experience of two years in the clause takes its shade of meaning from the expression and language used in clause (a). The clerical experience refers to service put in for two years and that is what is meant by the word 'clerical experience' falling in clause (b). The two years' clerical experience mentioned here referes to the same concept of length of service as provided in clause (a) and which in fact is not independent of it and as I have already stated that no new meaning could be given to experience here as in the context. It merely shows the span of service and nothing else. This is however, not true of the one year's experience as Ledger Keeper occurring in paragraph 1, in case of promotion to post of Teller. Here experience refers to actual experience and not the span of service because it is the experience gained while working in a particular type of work which is material. The type of work is provided in sub-paragraph (5) which is that it should relate to Current, Savings Fund, Fixed Deposit, Cash Credit, Overdraft Ledgers and expreience on Recurring Deposit Ledgers only. It is difficult to see how the experience could be gained without working on ledgers. The experience gained has to be actually with reference to the ledgers and type of work mentioned in paragraph 5 and not otherwise. There is no room for adding holidays or bank holidays or leave to such experience. It is not where the span of service is material but it is the actual working on special type of work that qualifies the candidate. While in one case the holidays and the leave have to be always counted subject to such exceptions as may otherwise be provided, in another case the experience has to be on the basis of working on those days. While in one case a long period is provided, in case of ledger experience, a shorter period is prescribed. It is the total number of days, when experience on ledgers is counted, that is of essence, and material, for acquiring the qualification.

12. It would also be seen that while in case of promotion as Special Assistant, the management has the discretion to reject a candidate on the ground that he was otherwise unsuitable and unfit for promotion for exceptional reasons which they had to give in writing, there is no such clause in case of selection of Tellers. Once a man gains the necessary experience of one year as Ledger Keeper, he becomes entitled to be promoted unless he is hit by paragraph 6 for a period of one year. It may be another matter that when such a person is wholly unsuitable, the management can, after giving him a show-cause notice on the ground of inefficiency and after a departmental inquiry in that regard, take such suitable action as it deems fit, but he is first to be considered and also promoted once he acquires the necessary experience of one year as Ledger Keeper and fulfils the conditions laid down in paragraph 1 to 5. The importance of the necessary experience can be noticed here.

13. It is clear that More did not have the requisite experience of one year. This is clear from the evidence and from his written statement. According to him, unless the day of leave and bank holidays and Sundays are counted, he would not be qualified to be considered as Teller. Therefore, I have no hesitation in holding that More was not qualified to be considered as Teller on the day when the vacancy was filled.

14. A plethora of evidence from both sides was led to show the efficiency or inefficiency of More. This, in my view, is wholly irrelevant in the present case. Despite the fact that every attempt had been made to controvert the charges levelled against More, I do not think it is necessary to examine it as in my opinion, nothing would turn on these allegations. This may be taken into consideration or my appropriately be made subject matter of charge in any departmental proceedings if the management deems it necessary in future, but today the dispute can easily be resolved by calculating the experience as ledger keeper. The management was, therefore, wholly justified in not considering More as eligible for the post of Teller when the vacancy arose.

Order

I accordingly render this Award holding that V.R. More was not eligible to be considered for selection to the post of Teller on 29-12-79 as he had not the requisite experience as Ledger Keeper for one year. The Management was therefore, justified in not appointing him as Teller on 29-12.1979. In the peculiar circumstances of the case there shall be no order as to costs.

Justice K.K. DUBE, Presiding Officer.

[No. L-12012/314/80-D.II(A)]

S.O. 1095.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby pubilshes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. II, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Maharashtra, Pune and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th March, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/38 of 1983

Employers in relation to the management of Bank of Maharashtra, Pune

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri R. M. Nijampurkar, Officer, Bank of Maharashtra.

For the Workman—Shri R. D. Jog, President, Bank of Maharashtra Karmachari Sangh.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra

Bombay, the 24th February, 1984

AWARD

(Dictated in the Open Court)

By their order No. L-12012(80)/83-D.III(A), dated 28-10-83 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the management of Bank of Maharashtra, Pune in relation to their Parali Branch in withdrawing post of Head Cashier from Shri S. M. Godse, Clerk from 10-9-82 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. Before we turn to the pleadings and issues involved certain dates would be material. Shri Godse who is the Clerk concerned joined the services of the Bank of Maharashtra in the clerical cadre on 20-12-1978. He was a confirmed clerk and on his request he was transferred to Parali Branch of the Bank on 26-10-1981. It is not disputed that staff of Parali Branch consisted of a Manager, a Clerk and a Peon. Formerly one Mr. Deshpande was working as a Cashier in the said branch but he was transferred sometime in the month of April, 1981 and from the said time onwards till 5-8-1981 the post of the Clerk-cum-Cashier was lying vacant, which was filled in on 5-8-1981 by appointing Shri Gavandi as a probationer. Now although Shri Godse was posted on Parali Branch on 26-10-1981 he was not given the charge of the Cashier's post, though till 5-2-1982 Shri Gavandi continued to work as a probationer and it was on 5-2-1982 that he was confirmed. During the period from 22-1-1982 on account of an application by Shri Godse dated 12-1-1982 protesting the continuance of Shri Gavandi as

Cashier the charge of the said post was given to Shri Godse and he continued to hold it till 28-9-1982 but from that date onwards Shri Gavandi was again posted as the Cashier and since it is a post carrying allowance Shri Godse protested against Shri Gavandi getting the same.

3. The contention of the Union who has espoused the cause, called Bank of Maharashtra Karamchari Sangh, relying on the Bank's circular dated 5-8-1974 is that on posting of Shri Godse in the Branch a post carrying allowance viz. Cashier's post should have been allotted to Shri Godse he being the sole confirmed employee in the Bank and Shri Gavandi then being a probationer and therefore not entitled to hold the post on joining of Shri Godse in the Branch. It is therefore urged that withdrawal of the post and denial of allowance was bad.

4. By their written statement at Ex. 2/M the Bank admits all the facts but contends that clause 6 of the circular dated 5-8-1974 was not a mandatory clause but conferred the discretion on the Manager to take suitable decision. It is contended that though Shri Godse joined the post on 26-10-1981, till 12-1-1982 he never advanced any claim for the post and therefore when the Central Office when contacted decided the claim in favour of Shri Godse he was allowed to hold the post from 23-1-1982. The Bank contends that since Shri Godse's transfer was a request transfer, since Shri Gavandi was confirmed on 5-2-1982 between these two employees Shri Gavandi was senior and as such entitled to the allowance post and accordingly he was put in charge of the Cashier's post on 28-9-1982.

5. On the above pleadings following issues arise for determination.

Issues	Findings
Whether because Mr. Godse's transfer to Parali Branch was request transfer, he could not be considered as senior to Mr. Gavandi as per the Bank's circular ?	He should be considered.
2. If yes, was Mr. Godse entitled to the post of Head Cashier ?	Yes
3. Was the action of the Bank in withdrawing the post justified ?	No.
4. What award ?	As per award.

REASONS

6. Really speaking when the Bank themselves issued a circular dated 5-8-1974 which circular makes the whole provision clear, the Bank or any authority serving in the Bank should not have acted in any manner derogatory to the circular. As already stated Shri Godse was a confirmed Clerk and although it was his request transfer on the day when he joined the Bank at Parali i.e. on 26-10-1981 in between the two viz. confirmed employee and the probationer Shri Godse in his capacity as a confirmed employee had the better right. Under clause (2) of the relevant circular it has been laid down, for comparing/deciding seniority, employees belonging to the same class (confirmed employees, probationer and temporary employees) shall be considered separately and they will rank for seniority in the same order i.e. confirmed employees will rank first, probationers second and temporary employees last.

7. Much has been tried to be made of the fact that the transfer of Shri Godse was a request transfer. However clause (4) has considered this eventuality and laid down that persons transferred on request shall rank for seniority last vis-a-vis persons of the same class already working there.

8. Now, when on 26-10-1981 Shri Godse was the sole confirmed employee in the branch in clerical cadre, it did not really matter whether it was a request transfer or a regular one because there being no other confirmed employee his name stood at serial no. 1 in the order and the claim of Shri Gavandi who was a probationer till then could not have been entertained from 26-10-1981. In this connection there is a clause no. (6) which says that ordinary, allowance post should not be allotted to probationers. It further says, however, if an allowance post is required to be allotted to a probationer, it shall be deemed to be allotted temporarily till availablity of a eligible confirmed employee. It is the case of the Bank that this clause is not mandatory but the discretion vested in the Branch Manager but a plain reading of the clause does not support this plea of the Bank. Consequently on 26-10-1981 the allowance carrying post of the Cashier which in the absence of a confirmed employee was allotted to Shri Gavandi, a probationer, from 26-10-1981 should have been allotted to Shri Godse and merely because he did not apply he could not have been deprived of the said post when he was entitled to the same. Only effect of the silence maintained by Shri Godse would be that from 26-10-1981 to 22-1-1982 when he was for the first time appointed as Cashier on account of his application dated 12-1-1982, we may hold that he is not entitled to the Cashier's allowance because he allowed somebody else to hold that post.

9. Such, however, would not be the case from 28-9-1982 onwards. Although on 5-2-1982 Shri Gavandi was confirmed that confirmation would not give him any priority over Shri Godse whose right to hold the post of a Cashier arose on 26-10-1981, and infact held the post from 22-1-1982 onwards atleast. While allotting the post the crucial date would be 22-1-1982 and that day Shri Godse had a better right. Confirmation from 5-2-1982 assuming that it related back to 5-8-1981, since when Shri Gavandi was working in the Bank, still it would never confer better right because Shri Godse has joined the Bank on 28-1-1978. The situation might have been different in case the confirmed employee had joined the Bank and not the branch subsequent to the date from which the confirmation of the probationer related back. However such is not the case here and since in seniority order once the right of Shri Godse was established, merely on the ground that another probationer was appointed and was confirmed subsequently and that initially Shri Godse's transfer was a request transfer, that right can not be withdrawn particularly when in service as it stands Shri Godse is admittedly senior. As I have held that Shri Godse was wrongly deprived of Cashier's post from 28-9-1982, he shall be entitled to the said post as well as shall be entitled to the Cashier's allowance from 28-9-1982 till he is reposted as a Cashier.

Award accordingly.

M. A. DESPANDE, Presiding Officer
[No. L-12012/80-83-D II(A)]

S.O. 1096.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Patiala, Patiala and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th March, 1984.

BEFORE SHRI J. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL

CHANDIGARH

Case No. I.D. 162/83 (N. Delhi), 61 of 1983 CHD

PARTIES :

Employers in relation to the Management of State Bank of Patiala, Patiala.

AND

Their workman Shri Ashok Kumar.

For the Employers—Sarvashri Dr. Anand Prakash and B. K. Gupta.

For the Workmen—Shri Tajinder Singh.

INDUSTRY : Banking STATE : Punjab

AWARD

Dated, the 1st March, 1984

The Central Govt., Miinstry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the

Act, vide their Order No. L-12012/20/82-D.II(A) dated the 6th of November, 1982 read with S.O. No. S-11025(2)/83 dated the 8th of June, 1983 referred the following Industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Management of State Bank of Patiala, the Mall, Patiala in relation to their Samana (ADS) Branch in terminating the service of Shri Ashok Kumar, Clerk-cum-typist, with effect from 10-11-1978 and in not providing him the opportunity of re-employment in the Bank's service, is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. According to the petitioner, Workmen, on recruitment by the Respondent Bank, he served them as a Clerk-cum-Typist at their Samana Branch for 93 days w.e.f. 10-8-1978 to 10-11-1978 and was entitled, to confirmation on a regular post on completion of 90 days' service since he had a clean record. It was complained that instead of being absorbed against a permanent post, the Management acted in an arbitrary, unjustified, illegal and malafide manner in terminating his services w.e.f. 10-11-1978. It was pleaded that no notice or compensation in lieu thereof was given to him and that there was no occasion to do away his services, particularly when at least three junior and raw hands viz. Ramesh Kumar Jain, Tarsem Kumar and Amrit Lal Singla were retained in service. He, therefore raised an Industrial dispute for his reinstatement and full back wages.

3. Despite the intervention of the A.L.C. (C) during the conciliation proceedings the dispute could not be settled amicably and, hence the Reference.

4. Contesting the proceedings on all counts, the Respondent, Bank Management questioned the propriety of the reference in view of its belated nature and contended that since the workman had not put in a total service of 240 days within the preceeding 12 calendar months from the point of termination, therefore, he could not claim any relief against the termination; more so as he was appointed on purely temporary basis for a fixed duration to meet the momentary exigencies. According to the Management, the Workman had put in only 86 days of service, in parts, i.e. from 10-8-1978 to 9-10-1978 and 17-10-1978 to 10-11-1978.

5. Elaborating their case, the Management questioned the petitioner's claim of seeking confirmation on completion of 90 days' service and denied that any person junior to him or any new hand of his category was retained in service. For the obvious reasons, the allegations of any impropriety illegality, irregularity or malafides etc. were categorically denied.

6. The parties were put to trial on the following issues framed over and above the terms of Reference :—

(1) Whether the claim of the petitinoer is belated and if so whether the delay is fatal to his case? OPR

(2) Whether the claim petition is vague and legally incompetent? OPR.

(3) Relief.

7. In support of his case the petitioner/Workman examined himself and filed copy Exb. W.2 of the Order dated 22-4-1983 passed by the Central Labour Court, Jullunder in proceedings under Section 33-C(2) of the Act. Similarly the Management also produced a number of documents and examined the concerned Branch Manager Shri Y. L. Sahi and an Officer of the Personnel Department, Shri Dharam Paul. I have carefully perused the entire material on records and hears the parties.

8. In all fairness to them the Management did not press their objections giving rise to the additional issues and that directly confronts the Tribunal with the vires of their action in terminating the petitioner's service and also denying him any opportunity of re-employment. On behalf of the workman my attention was drawn towards the Order Ex W.2 passed by the Central Labour Court, Jullundher on 22-4-1983, for the proposition that he had served the Respondent/Bank even for the intervening period from 10-10-1978 to 17-10-1978: meaning thereby that he had a continuous service of 93 days w.e.f. 10-8-1978 to his credit, when the impugned termination was effected.

9. Of course on behalf of the Management it was urged and submitted that the Order Ex. W.2 was an ex-party one and an application seeking its removal was pending adjudication with the Court concerned, but I am inclined to accept the petitioner's contention primarily because till the time of its setting aside, an ex-party order is as good as a contested one, and then there is absolutely nothing on records to support the submission that the said order is a subject matter of further proceedings in the Court concerned.

10. However the pertinent point is as to whether on completion of 90 days' service the petitioner was entitled to be confirmed? I am afraid there is no warrant for the proposition either under the Act, the Bi-partite Settlement or even the Desai Award. At best it may be argued that if a temporary post is allowed to function continuously for a period of three months or more, the Bank may be called upon to convert it into a permanent one and also afford an opportunity of consideration to the temporary incumbent, subject to his suitability and eligibility. But at the same time one has also to keep in view the limitations of the Bank Management in filling up such posts because, of late, in the matter of recruitments all the Nationalised Banks have since been divided into a number of Groups and each stands allocated to its area (region) of operation, the member Banks of these Groups are controlled by specific rules and regulations, as all the regular and permanent vacancies can be filled up only through the recruitment Board as should be evident from the copy of the relevant Rules Exb. M.6. And for the obvious reasons, a person recruited through such Board cannot be relegated to a secondary position as against a Workman of the petitioner's class who was employed on a purely makeshift and a temporary arrangement for a particular period. For my views I draw support from the observations in the context of Vishwanathan and State of Kerala 1983 (2) Lab. Law Journal 309.

11. Moreover the petitioner's effort in impugning his termination by virtue of Section 25-G is thoroughly misconceived. His representative Shri Tajinder Singh was at pains to take me through the statement of M.W. 1. Shri M. L. Sahai who could not deny that S/Shri Ramesh Kumar, Tarsem Kuamr and Amrit Lal were appointed after the petitioner and at least two of them were still in the Bank employment.

12. I am not impressed with the submission because Shri Singh appears to have lost sight of the fact that the statement of Shri Sahai, taken as a whole, should leave no manner of doubt that Ramesh Kumar, Tarsem Kumar and Amrit Lal (Since resigned) were recruited against permanent posts whereas, on his own admission in the Cross-examination, the petitioner's appointment originated from the Orders Ex. M-2 and M.4 which clearly show that he was recruited on purely temporary basis for a fixed duration. Obviously he could not claim parity or equation with a person recruited against a permanent or regular post.

13. As a matter of fact, Article 508 of Shastri Award formulates different classifications of employees. It categories and places a temporary employee at an inferior position than a permanent hand as well as a probationer. Similarly Article 522 and 524 (1) provide sufficient justification for the action of the Management in distingiushing petitioners case from those of the aforesaid employees Ramesh Kumar and others. It is besides the point that during the course of hearing, the petitioner had desired that their appointment orders be called and examined here, the management was fair enough to produce the originals and they were seen by the workman also. Clause 2 thereof cleraly revealed that all the three of them were appointed on probation against regular posts.

14. Last, but not the least, the workman complained against the non-payment of compensation within the purview of Section 22 (2) of the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958. There is no dispute on the point of fact, but "per-se" that would not vitiate the Termination because the rectification can be made by making the Bank Management pay the compensation even at this stage, as was held in the case of Nawa-Shahr Central Co-operative Bank Ltd. Vs. Lab. Court Jullundher (57), 1980 Ind. Fac. Jour. Reports 206.

15. However insofar as the petitioner's effort to seek priority in the matter of re-employment by virtue of Section 25-H is concerned, I feel inclined to sustain his cause despite a serious objection of the Management on whose behalf, it was contended that since he had not put in one year's continuous service with the meaning of Section 28-B therefore, he was not entitled for such benefit. They relied on Rules 76 and 78 to support the view point.

16. Seemingly the aforesaid Rules do contain a rider to the effect that the claimant workman should have put in a minimum service of 240 days in the preceding 12 calender months but one has to bear in mind that the Rules are a sort of 'ributory or channel sprouting from the Section as their source. In other words, they are sub-servient to the Sections and have no over-riding effect on them.

17. As a matter of fact the point in issue requires appraisement within the frame work and total scheme of the Enactment "Retrenchment" as defined by Section 2 (00) is vide enough to include the termination of an employee recruitted on Temporary, Ad hoc or even fixed tenure basis. For my views I draw support from the observation in the cases of Mohan Lal Vs. Management of M/s. Bharat Elec. 1981 (2) S.L.R. 11(SC) and Nawa-Shahr Central Co-operative Bank Ltd. Vs. Lab. Court Jullundher (57), 1980 Ind. Jour. Reports 206.

18. In the later case His Lordship was dealing with a situation where a person was employed on Ad hoc basis for a period of 3 months whose tenure was extended by another 2 months on different occasions before the termination with the afflux of time. In short, he had not completed 240 days service in 12 calender months. When the industrial dispute arose between the parties, the concerned Labour Court allowed his prayer for a preferential treatment. in the matter of re-employment by virtue of Section 25-H and this proposition was approved by the High Court, I find no reason to walk out of the ratio of the case.

19. Section 25-F imposes certain statutory obligations on an Employer towards a retrenched workman who had put in a minimum continuous service of one as defined by Section 25-B. But significantly enough no such qualification was required of a workman seeking re-employment with the aid of 25-H To put it in other words, in its wisdom the Legislature laid down that a retrenched workman seeking monetary benefits of retrenchment within the purview of Section 25-F must have put in a minimum of one year's continuous service whereas no such pre-condition was imposed in his attempt to seek preferential treatment in them matter of re-employment by virtue of Section 25-H, and I refuse to believe that Legislature lacked the imagination to appreciate the distinction arising out of the missing phraseology.

20. On behalf of the Management it was urged that in view of the Rules of Recruitment Exb. M.6 they could not possibly consider the proposition of petitioner's re-employment till he qualifies the requisite written test. But the objection failed to Carry Conviction with me because as a necessary implication of Sction 25-J the Recruitment Rules must give way to the Legislative mandate of Section 25H

21. Since no other point was raised before me; therefore, to sum up my aforesaid discussion on the entire available data I find no illegality or impropriety etc. in termination of the petitioner's services by the Recdt. Bank Management and to that extent I return my Award against him, but keeping in view the statutory intent of Section 25H. I direct the Management to afford him due opportunity, of course subject to suitability and eligibility, in the matter of re-employment.

Chandigarh,

Dated the Ist of March, 1984

I.P. VASISHTH Presiding Officer
[No. L-12012/63/82-D.II(A)]

New Delhi, the 14th March, 1984

S.O. 1097.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India, Chandigarh and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th March, 1984.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I. D. 43/83 CHD; 11/80 (Delhi)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Bank of India, Chandigarh.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES .

For the Employers—Shri S. Trevedi.

For the Workmen—Shri R. K. Sharma.

Central Bank of India STATE : Chandigarh

AWARD

Dated, the 2nd of March, 1984

The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, vide their Order No. L-12011/22/79-D.II(A) dated the 28th February, 1980 read with S.O. No. S-11025(2)/83 dated the 8th of June 1983 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Central Bank of India in unilaterally stopping the practice of supplying one woollen jersey once in two years to each of the members of watch and ward staff employed in Chandigarh Region of the Bank consisting of the States of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Chandigrah (Union Territory), since 1977 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

2. Today when the case came up for hearing the parties reported a compromise and filed their 'settlement' Ex. C. 1 revealing "inter-alia" that the management has conceded to the workmen demand in its pith and substance; accordingly I took down their statement also.

3. On hearing the parties and persuing the record I hereby return a No-dispute Award in the light of the terms and conditions incorporated in the settlement Ex. C-1 which shall be deemed to be a part thereof.

Chandigarh,

Dated : 2-3-1984

I. P. VASISHTH, Presiding Officer
[No. L-12011/22/79-D.II(A)]

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

I. D. No. 43/83

Ref. No. L-12012/31/78-D.II(A) of 1978

In the matttr of reference under Section 70 of the I. D. Act 1947 (14 of 1947)

Central Bank of India Employees' Union Punjab

Versus

Central Bank of India, Chandigarh.

Respectfully Showeth .

Whereas an industrial dispute is pending before this Hon'ble Tribunal in respect of supply of woollen jerseys at place in the State of Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Haryana and Chandigarh where this facility was allowed in the past and

Whereas both the parties have resolved to settle the matter on the following terms and conditions, it is hereby submitted that the disptue may be resolved on the following terms :—

1. The Bank shall provide to watch and ward staff woollen jerseys once every two years with effect from September, 1983, at those places where this facility had been extended by the Bank in the past. Such woollen jerseys will not be provided in this manner at places where they were not earlier provided.

2. The Union agrees to accept the above in full and final settlement of all its claims in regard to supply of woollen jerseys for past periods or any other incidental demands made by the Union.

3. It will be entirely at the discretion of the Management to decide the quality and type of woollen jerseys to be supplied to the watch and ward staff as also the price of the jersey.

4. It is agreed that this settlement shall not be treated as a precedent.

Signed for and on behalf of Central Bank of India

(B. N. KAPOOR)

Chief Manager

Signed for and on behalf of CBIEU (Punjab)

(R. K. SHARMA)

General Secretary

Witnesses :

Sh. S. B. Kapur, Sub-Accountant
Sh. Lalji Verma, Sub-Accountant,
Sector 17B, Chandigarh.

March 1st, 1984

New Delhi, the 15th March, 1984

S.O. 1098.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur (M.P.) in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Satna (M.P.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th March, 1984.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(25)/1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India, Regional Office, Jabalpur and their workman, Kapoor Chand Aggarwal, Clerk, P.O. Barhi, Teh. Katni, District Jabalpur (M.P.)

APPEARANCES :

For Bank—Shri G. C. Jain, Advocate.

For Workman—Shri K. C. Agarwal, workman concerned.

INDUSTRY : Bank DISTRICT : Jabalpur (M.P.)

AWARD

Dated, the 29th, February, 1984

The Central Government in exercise of its powers under Section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal vide Notification No. L-12012(228)/81-D.II(A) dated 19th March, 1982 :—

"Whether the action of the management of State Bank of India, Satna Branch, Satna (M.P.) in terminating the services of Shri Kapoor Chand Aggarwal, Clerk with effect from 15-10-1967 without assigning any reason is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. The workman, K. C. Aggarwal, had been working with the State Bank of India, Satna Branch, Satna (M.P.). His services were terminated as he was a temporary employee. The employee concerned claims that he is entitled to be absorbed in the services of the Bank.

3. The Bank after protracted negotiations has come to a settlement. Parties have filed a duly signed settlement. It appears that the employee, K. C. Aggarwal, has passed the test conducted by the Bank. Therefore the Bank agrees to take him in its employment, as a fresh appointee. The workman concerned has agreed to the above conditions and has further agreed not to claim any back wages, seniority in service etc.

4. I have gone through the settlement arrived at between the parties and is of the opinion that the settlement is fair and is in the interest of both the parties. I therefore give an award in terms of the aforesaid settlement. There shall be no order as to costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer

[No. L-12012/228/81-D.II(A)]

New Delhi, the 19th March, 1984

S.O. 1099.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Jabalpur and their workmen which was received by the Central Government on the 7th March, 1984.

BEFORE JUSTICE SRI K. K. DUBE, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(7)/1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India, Jabalpur and their workman, Shri Hemant Ghoshal Clerk, represented through the Asstt. General Secretary, State Bank of India and Subsidiary Bank Employees Union, C/o State Bank of India, Regional Office, Jabalpur (M.P.)

APPEARANCES :

For Bank—Shri G. C. Jain, Advocate.

For Workman—Shri Hemant Ghoshal.

INDUSTRY : Bank DISTRICT : Jabalpur (M.P.)

AWARD

Dated, the 27th February, 1984

The Central Government in exercise of its powers under Sec. 30 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute between the Bank and its employee for adjudication to this Tribunal, vide Notification No. L-12012(74)/82-D.II(A) dated 26th March, 1983 :—

"Whether the action of the management of State Bank of India, Civil Line Branch, Jabalpur in terminating the services of Shri Hemant Ghoshal Clerk, with effect from 8th August, 1972 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The workman Hemant Ghoshal, had been working with the State Bank of India. His services were terminated as he was a temporary employee. The employee claimed that he is entitled to be absorbed in the services of the Bank. The Bank after protracted negotiations has come to the settlement. Parties have filed a duly signed settlement. Under this settlement the employee concerned was to appear in a test examination. The employee has appeared and passed the test. It is agreed between the parties that Hemant Ghoshal having passed the test conducted by the Bank, the State Bank of India shall take him in its employment, without back wages, as Cashier-cum-Clerk forthwith and Hemant Ghoshal has agreed to relinquish all the back wages, if any. The appointment would be treated as a fresh one for all purposes.

3. I have gone through the case and is of the opinion that the settlement is fair and is in the interest of both the parties and should be given effect to. I therefore record my award in terms of the settlement stated above arrived at between the parties. There shall be no order as to costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer

[No. L-12012/74/82-D.II(A)]

New Delhi, the 19th March, 1984

S.O. 1100.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Jabalpur, and their workmen which was received by the Central Government on the 7th March, 1984.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(8)/1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India, Jabalpur and their workman, Krishan Shanker Chandra, Clerk, represented through the State Bank of India and Subsidiary Bank Employees Union, C/o State Bank of India Regional Office, Marhatal, Jabalpur (M.P.).

APPEARANCES :

For Bank.—Shri G. C. Jain, Advocate.
For Workman.—Shri Krishan Shanker Chandra.

INDUSTRY : Bank DISTRICT : Jabalpur (M.P.)

AWARD

Dated : February, 28, 1984

The Central Government in exercise of its powers under Sec. 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute between the Bank and its employee for adjudication to this Tribunal, vide Notification No. L-12012/75/82/D-II(A) dated 26th March, 1983 :—

"Whether the action of the management of the State Bank of India Civil Lines Branch, Jabalpur is not offering re-employment in service in terms of Section 25H of the I.D. Act, to Sri Krishan Shanker Chandra, Clerk whose service was terminated by the Bank with effect from 18-1-73, is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The workman, Krishan Shanker Chandra, had been working with the State Bank of India. His services were therefore agrees to appoint the workman, Krishan Shanker concerned claimed that he is entitled to be absorbed in the services of the Bank. The Bank after protracted negotiations has come to a settlement.

3. Parties have filed a duly signed settlement. The workman concerned was allowed to appear in the personal interview and was declared successful. The management has therefore agrees to appoint the workman, Krishan Shanker Chandra as Cashier-cum-clerk. The wokman has now agreed not to claim any back wages and other benefits of seniority in service etc. It is agreed between the parties that the appointment shall be a fresh appointment.

4. I have gone through the settlement and is of the opinion that the settlement stated above arrived at between the parties is fair and is in the interest of both the parties and should be given effect to. I therefore pass an award interms of the settlement. There shall be no order as to costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer
[No. L-12012/75/82-D. II(A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

New Delhi, the 14th March, 1984

S.O. 1101.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamadoba washery of M/s. Tata Iron and Steel Company Ltd., Post Office Jamadoba, District Dhanbad, and their workmen which was received by the Central Government on the 6th March, 1984

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 46/83

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jamadoba Washery of M/s. Tata Iron and Steel Co. Ltd., P.O. Jamadoba, Distt. Dhanbad.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.
For the Workman—None.

INDUSTRY : Coal STATE : Bihar

AWARD

Dated, the 25th February, 1984

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/s 10(1)(d) for the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(201)/83-D.III(A) dated the 9th November, 1983.

SCHEDULE

"Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh for continued service of Shri Seonath Singh in Clerical Grade-II with effect from 17-8-1972, of Jamadoba Coal Washery of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., is justified ? If so to, what relief is the workman entitled ?"

2. On 24-2-83 both the parties have filed a joint petition of compromise duly signed on their behalf and they pray that an award be passed in terms of the settlement.

3. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.

4. In the circumstances the award is passed in terms of the settlement which shall form part of the award.
Encl :—Settlement.

J. N. SINGH, *Presiding Officer*
[No. L-20012(201)/83-D.III(A)]

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 3 DHANBAD
Reference No. 46 of 1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jamadoba Washery of M/s. Tata Iron and Steel Co. Ltd., Jamadoba, P.O. Jamadoba, Distt. Dhanbad.

AND

Their Workmen.

1. That the Ministry of Labour, New Delhi has referred the following dispute for adjudication by the Honourable Tribunal by their Order No. L-20012(201)/83-D.III(A) dated 9th November, 1983.

SCHEDULE

"Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh for continued service of Sri Seonath Singh in Clerical Grade-II with effect from 17-8-1972, of Jamadoba Coal Washery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited is justified ? If so, to what relief is the workman entitled ?"

2. That it is submitted that the parties above named have discussed the matter mutually and it is found that the terms of reference is contrary to the actual dispute. The concerned workman, Sri Sheonath Singh ceased to be an employee of the company from 9-6-1979 and was re-employed vide letter dated 23-1-1981 and therefore his demand was to grant him continuity for the break in service as mentioned above.

That the parties above armed have discussed the matter along with the Union, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh which has sponsored the dispute on behalf of the concerned workman and decided to settle the dispute amicably on the following terms :—

(i) That Sri Sheonath Singh, Clerk Grade II, Jamadoba washery will be granted continuity of service from 9-6-1979 to 31-1-1981.

(ii) That Sri Sheonath Singh will not be entitled to back wages or any other monetary benefit for the above period.

(iii) That the above continuity of service is granted only for the purpose of gratuity and matters related to his employment.

That the above terms of settlement fully resolves the dispute pending before the Hon'ble Tribunal for adjudication.

That the above terms of settlement are fair.

It is therefore humbly prayed that the terms of settlement may be accepted and an Award be passed in terms thereof.

Workmen

For Union For Employer

Witness :—

Sd/- Illegible

S. K. TRIPATHI, Personnel Officer.

New Delhi, the 15th March, 1984

S.O. 1102.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Damodar Valley Corporation's Bermo Colliery, Post Office Bermo, District Giridih and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th March, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 110 of 1982

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Damodar Valley Corporation's Bermo Colliery, P.O. Bermo District Giridih and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers : Shri S. S. Mukherjee Advocate.

On behalf of the workmen : Shri J. D. Lall, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, 6th March, 1984

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under section 10(1)(d) of the I. D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012 (137)/82-D. III (A) dated the 28th August, 1982

SCHEDULE

"Whether the decision of the management Damodar Valley Corporation's Bermo Colliery, Post Offices Bermo, District Giridih to retire Shri C. S. Ghosh, Clerk Grade-I from service with effect from the 30th November, 1982 (afternoon) is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

The case of the management is that the concerned workman Shri C. S. Ghosh was appointed on 1-12-54 in Damodar Valley Corporation's Bermo Colliery. The age of C. S. Ghosh was recorded by him in his own handwriting and signature as 32 years as on 1-12-54, the date of his appointment, in the old B Form Register of 1956. By an Office Order dated 28-9-73 the management issued a general circular to all the workmen of Damodar Valley Corporation's Bermo Mines mentioning there Father's name, date of appointment and age/date of birth as recorded in B Form register and requested the workmen to check the same and in case of discrepancy the same was to be brought to the notice of the management with documentary evidence for correction. A reminder to the above effect was issued by another circular dated 18-1-74 asking all workmen to take action on the Office Order dated 28-9-73. In the above circular dated 28-9-73 the date of birth of Shri C. S. Ghosh was wrongly typed as 39 years as on 1-12-54 instead of 32 years as per B Form Register. Shri C. S. Ghosh submitted an application dated 31-1-74 stated therein that his age was 29 years as on 1-12-54, the date of his appointment, and in support of the claim he submitted a copy of Horoscope. The management doubted the entry of age in the Horoscope and refused to rely on it in proof of age of Shri C. S. Ghosh. The age in Form B Register was written by Shri C. S. Ghosh himself as 32 years as on 1-12-54. The said register is a staturory register and has no reliable document was produced by Shri C. S. Ghosh the management confirmed his age as 32 years as on 1-12-54 The management by a letter dated 1-6-76 informed Shri C. S. Ghosh that his date of birth has been calculated as 1-12-1922 on the basis of the age recorded in Form B Register. The management informed Shri C. S. Ghosh by a notice dated 9-10-81 that he would retire on 30-11-82 on superannuation on attaining the age of 60 years. The management did not change the date of birth or make any overwriting in Form B Register. There was no reason for the management for overwriting or for making any false entry of the age of Shri C. S. Ghosh. The assertion of Shri Ghosh that his date of birth is 15-10-26 is with the purpose for deferring the date of his retirement. The declaration of age in Form A in the CMPF is not a reliable document for the purpose of determining the age of Shri C. S. Ghosh. As the date of birth of Shri Ghosh was 1-12-22 the decision of the management to retire him from service w. e. f. 30th November, 1982 is justified and Shri Ghosh is not entitled to any relief.

The case of the concerned workman Shri C. S. Ghosh is that he was originally appointed as Grade III Clerk on 1-12-54. Thereafter he was promoted to Clerk Grade II and subsequently as Clerk Grade I w. e. f. 1966. Shri Ghosh is an active member of the Union known as D. V. C. Karamchari Sangh and the management is very much biased against the members of D. V. C. Karamchari Sangh. The management with an ulterior motive to victimise and remove him from service tampered the entries in Form B Register in respect of his date of birth by overwriting the same. The management for the first time informed him about the date of his birth as 1-12-22 by a letter dated 1-6-76. Shri Ghosh immediately protested against the illegal action of the management for changing his date of birth as 1-12-22 in place of 15-10-26. He also drew the attention of the management towards the declaration of his age in Form A submitted in the C.M.P.F. and the Family Pension Card issued by the Management. Inspite of the fact that Shri Ghosh had pointed all the facts, the management refused to correct his date of birth. The management decided to retire Shri Ghosh from service w. e. f. 30-11-1982 which was illegal arbitrary, unjustified and against the principles of natural justice The entries made in B Form Register were filled up by the Clerk concerned after the workman had put his signature in B Form Register. The entries made in B Form Register regarding the age differs from year to year. In B Form Register of 1955 the age of Shri Ghosh was recorded as 29 years. Form B Register is a continuous register but the management has been changing Form B Register every year and as such there were contradictory entries of age in the Register from year to year. The management itself did not attach any reliance on the entries in Form B register in respect of age of the workmen and as such the circular was issued informing the workmen to apply for the removal of discrepancy if any in respect of the age. The age of Shri Ghosh was recorded in Form B Register as 29 years as on 1-12-54 but the management made an overwriting and made it 39 years. The concerned workman had submitted before the management that his date of birth as recorded in declaration in Form A as 16-10-1926 be accepted as correct date of birth. If the management had any doubt regarding the age of Shri Ghosh, the management should have referred him to Medical Board for assessment of his correct age. The management had allowed the workmen to inspect the registers in B Form which contained contradictory entries in regard to the age of Shri Ghosh from year to year. On the above facts the concerned

workman has prayed that he may be reinstated with full back wages with other consequential benefits as he has been illegally retired from service w.e.f. 30-11-82.

The point for decision is whether the retirement of Shri C. S. Ghosh from service w.e.f. 30-11-82 is justified. The decision of the above dispute rests on the fact as to what was the date of birth of Shri C. S. Ghosh.

According to the management an entry regarding the age of the concerned workman was made by the workman himself as 32 years on 1-12-56 and as such the management has rightly decided the date of superannuation of the concerned workman on 30-11-82. The case of the concerned workman on the other hand is that his date of birth was 15-10-1926 and that in the Register B Form of the year 1955 his age was recorded as 29 years as on 1-12-54 and as such he was to retire on superannuation on 30-11-85. The management has examined two witnesses and the workman has examined one witness in support of their respective case. Both the parties produced some documents which have been exhibited in proof of the age being asserted by the respective parties.

It will appear from the evidence of MW-1 Shri S. F. Francis who is working as Time Keeper of Damodar Valley Corporation's Bermo Mines that the main prop of evidence adduced on behalf of the management is Ext. M-1 which is a register in Form B. In Sl. No. 38 of this register relevant entry has been made in respect of the concerned workman Shri C. S. Ghosh. There is a column in it regarding age and sex in which there is an entry as M/32 (M stands for male). There is another column meant for "date of commencement of employment" in which 1-12-54 has been written in respect of Shri C. S. Ghosh. The said entry is in respect of the month of August, 1956 regarding Damodar Valley Corporation's Bermo Colliery. MW-2 has stated that entry in Form B Register are filled in at the time of appointment of the concerned workman. He has further stated that at the time when the concerned workman was appointed there was no Form B Register and that this Form B Register was started in the year 1956. This evidence of MW-1 is contradicted and falsified by the evidence of MW-2 himself. MW-2 has stated in his cross-examination that the register in Form B was started after passing an Act (Rules under the Mines Act) in 1952 and that his name was entered in Form B Register in the year 1955. It will thus appear that the B Form Register was actually started since Damodar Valley Corporation's Bermo Mines was started in 1953 and that there was the register in B Form in the year 1955 also. In his cross-examination MW-1 has stated that he did not know if every year new Form B Register was being maintained. It will appear from the evidence of MW-1 that there is entry in B Form Register at Sl. No. 8 and the same has been marked as Ext. W-1. It will appear from the entries in Ext. W-1 that the age of MW-1 was recorded as 30 years and the date of commencement of his employment was 4-10-53. In the evidence MW-1 has stated that his age on 19th January, 1984 was 57 years. Thus MW-1 will be retired on superannuation sometime in 1987. But if we take the age of MW-1 as 30 years on 4-10-53 it will appear that his age of superannuation will be in the year 1983. Thus it will appear that the entry of age of MW-1 Shri S. F. Francis as 30 in the B Form Register of 1956 was not on 4-10-53 but it was in the year 1956 His evidence further is that the age of the workman entered in Form B Register is as in the year 1956. He has stated that the concerned workman was aged 32 years in the year 1956 on the basis of the entry at Sl. No. 38 of the Register in Form B in the month of August, 1956. Thus it is quite clear from his evidence also that the entry of the age of the concerned workman as 32 years was as in the year 1956 and not on the date of his appointment. If the age of MW-1 was recorded in this Register in the month of August, 1956 as 30 years, it will appear that the age of the concerned workman recorded as 32 was also as in the year 1956 and not as on 1-12-54.

MW-2 Shri M. P. Sinha is presently working as Office Superintendent in the Damodar Valley Corporation's Bermo Mines. It will appear from his evidence that his name is entered at Sl. No. 39 of Ext. M-1. He has stated that the age entered against his name is the age at the time of his appointment. It will appear from the age Column recorded against the name of MW-2 M. P. Sinha that his age has been recorded as 28 years and that he was appointed on 1-10-55. This entry has been made in the Form B Register of Damodar Valley Corporation's Bermo Colliery for the month of August 1956. In his cross-examination he has stated that his name is entered in Form B Register in the year 1955. But the management has withheld the said register in B Form for the year 1955. The said register of 1955 also would have shown the age of the concerned workman. Even MW-1 expressed his ignorance if the entries in B Form Register in respect of the concerned workman was made in the year 1954 when he was appointed. Thus from the trend of the evidence of MW-1 and MW-2 it appears that the register in B Form was being maintained since after the opening of the Bermo Mines of Damodar Valley Corporation in 1953 and I think as the maintenance of the said registers was a statutory obligation, the same must have been maintained under the rules of the Mines Act since after the operation of mines. The concerned workman WW-1 has asserted that his age was recorded as 29 years in the Register in B Form in the year 1955 after his appointment. Thus there is no positive and cogent evidence adduced on behalf of the management to falsify the evidence of WW-1 that no register was maintained for the year 1955. Even the register of 1955 which according to MW-2, had been prepared is not produced in the case to show as to what was the age of the concerned workmen entered in the Register of 1955. In the above view of the matter it appears that the management has withheld the register in B Form of the period prior to 1956.

MW-2 has stated that the entries in Ext. W-2 regarding age was made on the basis of Form B Register but he was unable to say the year of Form B Register from which the entries of age were made in Ext. W-2. Ext. W-2 was the schedule attached along with the circular of the management by which the management had given a notice to the workmen to verify their age and to file any objection if there was any discrepancy in the entry of their age. In Sl. No. 203 of Ext. W-2 there is the relevant entry in respect of the concerned workman Shri C. S. Ghosh. MW-1 has stated that in Sl. No. 203 there is an overwriting in the age column from 29 to 39. He has denied that the entry "29" in Ext. W-2 was correct and the subsequent overwriting in the age of the concerned workman was wrong. Admittedly, overwriting of age as 39 was wrong. It is nobody's case that the concerned workman Shri C. S. Ghosh was aged 39 years on the date of his appointment. It will appear from the evidence of MW-2 that there is overwriting in the age column from 29 to 39. There is no evidence adduced on behalf of the management that in Ext. W-2 there was any other age recorded except 29 or the overwriting 39. It will thus be clear that the age of the concerned workman was recorded as 29 in Ext. W-2 and a subsequent overwriting was made on it as 39. The case of the concerned workman is that his age was recorded as 29 years in the register for the year 1954 when he was appointed and this case of the concerned workman tallies if we take into consideration the evidence of MW-2 coupled with the original age entry of 29 in Ext. W-2. On this score as well the case of the concerned workman finds support.

The management has produced register in B Form for the month of August, 1960 and the same has been marked as Ext. M-2. In Sl. No. 6 is the entry in respect of MW-1 S. F. Francis in which his age has been recorded as 27 years and in the column of the date of commencement of his employment 4-10-53 is recorded. If this entry of age of MW-1 taken to be his age on the date of appointment I think the same is quite correct. This entry supports the fact that MW-1 had entered his service at the age of 27 as has been discussed by me above. In this very Register in Sl. No. 4 there is an entry in respect of the concerned workman Shri C. S. Ghosh. It will appear from the entries of age column that the age was entered as 32 years and there is an overwriting to make the same as 34 years. It is submitted on behalf of the management that this overwriting in Ext. M-2 and the overwriting in Ext. W-2 was made by the concerned workman. The concerned workman had no interest in increasing his age from 32 to 34 in Ext. M-2 as that would be against his interest and it cannot be imagined that the concerned workman had made any overwriting in Ext. M-2 against his interest. According to MW-2 there was an overwriting on 29 to make it 39 in Ext. W-2. The concerned workman had no interest in overwriting in Ext. W-2 to increase his age for about 10 years against his interest. The management was asserting that the concerned workman was not aged 29 years at the time of his appointment as such the overwriting made in Ext. W-2 could not be by the concerned workman but

the same may have been done on behalf of the management. I hold, therefore, that the overwriting in Ext. M-2 and W-2 was not made by the concerned workman.

The concerned workman has examined himself as WW-1. He has stated that he was appointed on 1-12-54. He has further stated that in 1955 entries in respect of his particulars was made in the Form B Register and his age was recorded as 29 years on the date of appointment. According to him his age entered in Ext. M-1 as 32 years was in the year 1956. He has stated that Form B Register was prepared every year upto the year 1971. He has stated that there was overwriting in the schedule to the circular (Ext. W-2) and the age 29 was overwritten as 39 years. Ext. M-4 is the Form of Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 regarding the concerned workman in which the date of birth has been noted as 16th July, 1926. It is alleged on behalf of the management that there is overwriting in the year 1926 but on careful perusal it will appear that there is no overwriting in the year 1926 in Ext. M-4. Ext. M-3 is the C.M.P.F. declaration form of the concerned workman in which the date of birth is noted as 15th October, 1926. It will further appear that formally in the month column "May" was written and the said month "May" was penned through and in it's place October was written. There is, no doubt, cutting and overwriting in this Ext. M-3. Ext. W-3 is the Horoscope of the concerned workman from which it will appear that the date of birth of the concerned workman was 16th October, 1926. Thus from Ext. M-3 M-4 and W-3 the date of birth of the concerned workman Varies and as the date of birth as given in all those documents are unilateral documents it may not be safe to rely on them. Ext. M-5 to M-9 are admitted documents but they throw no light for decision on the question of age and as such they need no discussion. But since the management rely on the age of the concerned workman on the original entry made in their register in Form B, I think it is better to proceed on the assumption that the age or the date of birth as originally declared by the workman is his correct age.

In view of the discussions made above it will appear that the age of the concerned workman recorded in the register in B Form for the year 1956 as 32 years was as in the year 1956 and not on the date of his appointment. In the above view of the matter it has to be held that the date of birth of the concerned workman was 1-12-1924 and accordingly the date of superannuation of the concerned workman will be 30-11-84.

In view of the above, the decision of the management of Damodar Valley Corporation's Bermo Colliery to retire Shri C. S. Ghosh from service w.e.f. 30th November, 1982 was not justified and that the date of superannuation of the concerned workman will be 30-11-84. As the concerned workman has been illegally retired from service w.e.f. 30-11-82 he is reinstated in service with full back wages and other consequential benefits since after 30-11-82 till the date of his superannuation.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer.
[No. L-20012(137)/82-D.III(A)]
A. V. S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली 5 मार्च 1984

आदेश

का० आ० 1103.—मैसर्स डी० अब्राहम एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड बम्बई के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच जिनका प्रतिनिधित्व सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स यूनियन बम्बई करती है एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को जो उसे 22 फरवरी 1984 को मिला था एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. मैसर्स डी० अब्राहम एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड हेग बिल्डिंग सप्रोट रोड बैलार्ड ईस्टेट बम्बई-400038 जिनका प्रतिनिधित्व श्री एम० एम० साह सेक्रेटरी ने किया है ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक वर्क यूनियन बम्बई पी० डीमेलो भवन दूसरी मंजिल पी० डी० मेलो रोड कर्नाइ बन्दर बम्बई-400038

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को

1. श्री एम० के० दास डिप्टी चेयरमैन बम्बई डाक लेबर बोर्ड कृपनिधि 9 बालचन्द्र हीराचन्द्र मार्ग बैलर्ड इस्टेट बम्बई 400038

2. श्री एम० आर० सामन्त (सेवा निवृत्त) औद्योगिक अधिकरण महाराष्ट्र स्थानिय 10 सत्य निवास राजाराम तवाडे रोड, दाहीसर (पश्चिमी) बम्बई-400062 के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय :

क्या मैसर्स डी० अब्राहम एण्ड संस प्राईवेट लिमिटेड और ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स यूनियन बम्बई के बीच 4 नवम्बर 1981 को हुए समझौते के अनुच्छेद-II के साथ पठित उपदान संदाय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन श्री टी० डी० परब के सम्बन्ध में परिकलित और भुगतान किया गया उपदान सही है ? यदि नहीं तो तारीख 4 नवम्बर 1981 के उक्त समझौते के उपबन्धों के साथ पठित उपदान संदाय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उपदान की कितनी राशि श्री परब को देय है ?

पक्षकारों के नाम

(2) विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें अंतर्वलित स्थापन या : 1. मैसर्स डी० अब्राहम एण्ड संस प्राईवेट लि०, हेग बिल्डिंग, सप्रोट रोड,

उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है।	बलार्ड इस्टेट, बम्बई-400038
	2. ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्क्स यूनियन, बम्बई, पी० डी० मेलो भवन, दूसरी मंजिल पी० डी०, मेलो रोड, कार्नाई इन्दर, बम्बई-38
(3) कर्मकार का नाम यदि वह स्वयं ही अंतर्ग्रस्त हो या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम	श्री टी० डी० परब, जिनका प्रतिनिधित्व ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक वर्क्स यूनियन बम्बई करती है ।
(4) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या	70
(5) विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या	एक

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थों का एकमत विनिश्चय हम पर आबद्ध कर होगा यदि मध्यस्थमों के बीच मतैक्य न हो तो वे आपस में स्वीकार्य किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थम के रूप में नियुक्त करेंगे, जिसका विनिश्चय हम पर आबद्ध होगा ।

मध्यस्थ अपना पंचाट इस करार को समुचित सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित करने की तिथि से छह मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर, जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए, देंगे ।

न्याय निर्णयन की लागत कम्पनी द्वारा वहन की जाएगी।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : हस्ता०/-
डी० अब्राहम एण्ड संस प्राइवेट लि०
हस्ता० -
निदेशक

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : हस्ता०/-
सैकेट्री,
ट्रांसपोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स यूनियन

साक्षी

1. हस्ता०/-
(आई० एस० सावन्त)

साक्षी

1. हस्ता०/-
(एम० एम० साह)

2. हस्ता०/-
(एम० एस० टेम्कर)

2. हस्ता०/-
(वी० एल० संघवी)

मध्यस्थों की सहमति

श्री टी० डी० परब को देय उपदान के मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए मैसर्स डी० अब्राहम एण्ड संस प्राइवेट लि०, हेग बिल्डिंग, स्प्रोट रोड, बलर्ड इस्टेट, बम्बई-400038 द्वारा किए गए अनुरोध पर मैं एतद्द्वारा उक्त मामले में मध्यस्थ के रूप में काम करने की सहमति देता हूं ।

ह०/-
(एस० आर० सामन्त)
एडवोकेट, उच्च न्यायालय

श्री टी० डी० परब को देय उपदान के मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए सचिव, ट्रांसपोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स यूनियन, बम्बई द्वारा किए गए अनुरोध पर मैं एतद् द्वारा उक्त मामले में मध्यस्थ के रूप में काम करने की सहमति देता हूं ।

ह०/-
(ए० के० दास)
डिप्टी चेयरमैन
बम्बई डाक लेबर बोर्ड

[एल-31013/2/84-डी-4(ए)]
एस० एस० पराशर, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 5th March, 1984

S.O. 1103.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of M/s. D. Abraham & Sons Pvt. Ltd., Bombay and their workmen represented by Secretary, Transport and Dock Workers Union, Bombay.

And whereas, the said employers and their workmen have by written agreements under sub-section (1) of Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbiration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

Now therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10-A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which was received by it on the 22nd February, 1984.

AGREEMENT

[Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947]

BETWEEN

NAME OF THE PARTIES :

Representing Employers :	1. M/s. B. Abraham & Sons Pvt. Ltd., Hague Building, Sprott Road, Ballard Estate, Bombay-400038. Represented by Mr. M.M.Shah Secretary.
Representing workmen/workman.	Transport & Dock Workers Union, Bomay. B.D. Mello Bhavan, 2nd Floor, P.D. Mello Road, Carnac Bunder, Bombay-400038.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of—

1. Shri S.K. Das, Deputy Chairman, Bombay Dock Labour Board, Krupanidhi, 9 Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Bombay-400038.
2. Shri S.R. Samant Retired, Industrial Tribunal, Maharashtra residing at 10, Satya Niwas, Rajaram Tawade Road, Dahisar (West), Bombay-400062.

(i) Secific matters in dispute.	"Whether gratuity calculated and paid to Mr. T.D. Parab under the provisions of the payment of Gratuity Act, read with clause 11(b) of Settlement dated 4th November 1981 between M/s. D. Abraham & Sons Private Limited, and the Transport & Dock Workers Union, Bombay is correct. If not what amount of gratuity becomes payable to Mr. Parab under the provisions of the Payment of Gratuity Act, read with the provisions of the said Settlement dated 4th November 1981."
(ii) Details of the parties to the disputes including the name and address of the establishment or undertaking involved.	(a) M/s. D. Abraham & Sons Private Ltd. Hague Building, Sprott Road, Ballard Estate, Bombay-400038. (b) Transport & Dock Workers Union Bombay, P.D. Mello Bhavan, 2nd Floor, P.D. Mello Road, Carnac Bunder, Bombay-400038.
(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the union if any representing the workman or workman in question.	Sh. T.D. Parab, represented by Transport & Dock Workers' Union, Bombay.
(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected in India.	
(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.	1

We further agree that the unanimous decision of the Arbitrators shall be binding on the parties. In case the Arbitrators are divided in their opinion they shall appoint another person mutually acceptable as umpire whose award shall be binding on the parties.

The Arbitrators shall make their Award within a period of six months from the date of publication of this Agreement in the Official Gazette by the appropriate Government or within such or further time as is extended by mutual agreement by the parties in writing.

The cost of the arbitration will be borne by the Company.

Signatures of the Parties

Representing employers : Signatures of the parties.

D. Abraham & Sons Private Ltd.

Sd/
Director

Representing workman ;
Sd/
Secretary
Transport & Dock Workers Union, Bombay.

Witnesses :	Witnesses
(1) Sd/ (I.S. Sawant)	(1) Sd/ (M.M. Shah)
(2) Sd/ (M.S. Tenkar)	(2) Sd/ (V.L. Sanghavi)

Consent of the Arbitrators

As per the request made by M/s. D. Abraham & Sons Private Limited, Hague Building, Sprott Road, Ballard Estate, Bombay-400038 to act as an Arbitrator in the matter of Gratuity payable to Shri T.D. Parab, under the Industrial Disputes Act, 1947, I hereby give my consent to act as an Arbitrator in the aforesaid matter.

Sd/
(S.R. Samant)
Advocate, High Court

As per the request made by the Secretary, Transport and Dock Workers' Union, Bombay to Act as an Arbitrator in the matter of Gratuity payable to Shri T.D. Parab, under the Industrial Disputes Act, 1947, I hereby given my consent to act as an Arbitrator in the aforesaid matter.

Sd/
(S.K. DAS.)
Deputy Chairman,
Bombay Dock Labour Board.
[No. L-31013/2/84-D IV (A)]
S. S. PRASHER, Desk Officer.

New Delhi, the 15th March, 1984

S.O. 1104.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. II, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. General Superintendence Co. (India) Pvt. Limited, Goa and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th March, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/6 of 1978

Employers in relation to the Management of M/s. General Superintendence Co. (India) Pvt. Ltd., Goa.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—No appearance
For the workmen—No appearance

INDUSTRY : Ports and Docks STATE : Goa, Deman and Diu

Bombay, dated the 24th February, 1984

ORDER

By order in Special Civil Application (Writ Petition) No. 67/B of 1980 the Hon'ble High Court of Bombay, Panji Bench held that what was referred to this Tribunal is not an industrial dispute concerning the Major Port and that Iron Ore Complexe are not Dock Workers and that Central Government is not the State Government for the Union territory of Goa under Section 2(a)(ii), allowed the petition and accordingly decided the Special Civil Application. In view of this Rule the Reference cannot servive being not sustainable and hence disposed of.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer.

Date 23-2-84.

[No. L-36011/1/78-D.IV(A)]

नई दिल्ली 24 फरवरी 1984

आदेश

का० आ० 1105—बम्बई पत्तन न्यास, बम्बई के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व बम्बई पत्तन न्यास जनरल वर्कर्स यूनियन, बम्बई करती है, ने संयुक्त रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है कि उनके बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को, जो उनके आवेदन में उठाए गए मामलों से सम्बन्धित है, और जिन्हें इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, औद्योगिक अधिकरण को भेजा जाए ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नम्बर 1 बम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या पाइलट वेसल वीनू में कार्य दशाओं और अन्य संगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मांग न्यायोचित है कि बारह घंटों, जितना कि वेनु पाइलट वेसल के स्यारंग लस्करों के टिंडल, सी-करी, लस्कर, पैन्ट्रीमैन, जनरल अटेन्डेन्ट, जूनियर कुक, भंडारी का मेट, और टोपाज श्रेणियों के डेक कर्मीदलों का ड्यूटी के प्रत्येक दिन काम किया समझा जाता है, में सम्मिलित समयोपरि काम के घंटे बढ़ाए जाने चाहिए। और यदि हां तो कितने घंटों तक ?"

[एल० 31013/1/84- डी० 4 (ए०)]

एस० एस० पराशर, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th February, 1984

ORDER

S.O. 1105.—Whereas the employers in relation to the management of Bombay Port Trust, Bombay and their workment represented by the B.P.T. General Workers' Union, Bombay, have jointly applied to the Central Government under Sub-Section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matters set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the persons applying represent the majority of each party;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay constituted under section 7A of the said Act.

"Whether having regard to the conditions of work on the Pilot Vessel Venu and other relevant circumstances the demand that the hours of overtime work included in the twelve hours which the dock crew of the Pilot Vessels Venu in the categories of Syrang, Tindal of Lascars, Seacunny, Lascar, Pantryman, General Attendant, Junior Cook, Bhandary's Mate and Topass are deemed to have worked on each day of duty should be increased is justified and, if yes, by how many hours?"

[No. L-31013/1/84-D.IV(A)]

S. S. PRASHER, Desk Officer.

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1984

का. आ. 1106.—मैसर्स अमर टैक्सटाईल्स लिमिटेड, पोस्ट, बाक्स नं. 154, गांधी नगर, पी. ओ. तिरुपुर (तमिल नाडु) (टी.एन./46), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/16/84-एफ.पी.जी.]

New Delhi, the 14th March, 1984

S.O. 1106.—Whereas Messrs Asher Textiles Limited, Post Box No. 154, Gandhi Nagar, P.O. Tirupur-638603 (TN/46), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest

of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(16)/84-PG]

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1984

का. आ. 1107.—मैसर्स चण्डीगढ़ मोटरम, पोस्ट बाक्स नं. 636, 4, इण्डस्ट्रियल एरिया, चण्डीगढ़ और इसकी शाखा चण्डीगढ़ मोटरम् लुधियाना (पंजाब/1940 एवं पंजाब/3608), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार

नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/15/84-एफ. पी. जी.]

New Delhi, the 14th March, 1984

S.O. 1107.—Whereas Messrs Chandigarh Motors, Post Box No. 636, 4, Industrial Area, Chandigarh (and its branch M/s. Chandigarh Motors, Ludhiana) (PN/3608 and PN/4940), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said estalishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insuracne corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his estabilshment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(15)/84-FPG]

का. आ. 1108.—मैसर्स बेम ऑरगनिक केमिक्लस लिमिटेड स्काईलाईन हाउस, तीसरी मंजिल, 85, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 19 (दिल्ली/5470), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/14/84-एफ.पी.जी.]

S.O. 1108.—Whereas Messrs Vam Organic Chemicals Ltd., Skyline House (3rd Floor), 85, Nehru Place, New Delhi-19 (DL/5470), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the

Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(14)/84-FPG]

का. आ. 1109.—मैसर्स नेवली गिरेमिक्स एण्ड रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, वादालूर डाकघर, पिन कोड नं. 607303, साउथ आर्क डिस्ट्रिक्ट (तमिलनाडु/3967), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2-क) के अधीन नैमित्तिक आधार पर या ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित से भिन्न अपने विभागीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. नियोजक ऐसे कर्मचारी की बाबत, जो स्थापन छोड़ देता है और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले किसी अन्य स्थापन में नौकरी आरम्भ करता है, उस अन्य स्थापन की बाबत बीमा निधि में जाने वाले कर्मचारी के नाम में आनुपातिक प्रीमियम का अन्तरण कराएगा।

6. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

7. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

8. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

9. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

10. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट उस तारीख से रद्द समझी जाएगी और उस स्थापन को उक्त स्कीम के अधीन समझा जाएगा।

11. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम

का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकेगी और नियोजक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

12. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो उक्त स्कीम के अन्तर्गत आते हैं, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

13. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/13/84-एफ. पी. जी.]

S.O. 1109.—Whereas Messrs Neiveli Ceramics and Refractories Limited, Vadolur P.O. Pin Code 607303 South Arcot District (TN/3967), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2B) of section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) in respect of their departmental employees other than those employed on casual basis or through contractors.

And whereas, the Central Government is satisfied that the departmental employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in the enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2B) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the departmental employees of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts and payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government as and when amended alongwith a translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. The employer shall arrange in respect of an employee who leaves the establishment and joins another establishment covered under the said Act to transfer to the Insurance Fund in respect of the other establishment, the proportionate premium to the credit of the outgoing employees.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

7. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

8. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable, had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

9. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

10. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be deemed to have been cancelled with effect from that date and the establishment shall be treated as covered under the said Scheme.

11. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled and the employer proceeded against.

12. 'In the case of default, if any, made by employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee/legal heirs of deceased members who are covered under the scheme will be that of the employer'.

13. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(13)/84-FPG]

का. आ. 1110.—मैसर्स अहरा वेल्डिंग इलैक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, एफ-139 एण्ड 144/3, थिरुन्डायामपालायम, पालघाट रोड, कोयम्बतूर-5 (तमिल नाडु/9488), (जिसे इसमें

इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/12/84-एफ.पी.जी.]

S.O. 1110.—Whereas Messrs Ahura Welding Electrode Manufacturers Limited, SF. 139 and 144/3, Thirumalayampalayam, Palghat Road, Coimbatore-641105 (TN/9488), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than

the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employes.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014 (12)/84 FPG]

का. आ. 1111.—मैसर्स राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर (राजस्थान/694) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितीयों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/11/84-एफ.पी.जी]

S.O. 1111.—Whereas Messrs Rajasthan Rajya Sahakari Krya Vikraya Sangh Limited, Bhawani Singh Road, Jaipur (RJ/694), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits availble to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount

payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum asured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(11)/84-FPG]

का. आ. 1112.—मैसर्स परियार डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर्स को-आपरेटिव होलसेल स्टोर लि., इरोड (तमिल नाडु/4891). (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के निबंधों की एक प्रति, और जब उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुकी भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के

अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितीयों/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/10/84-एफ.पी.जी.]

S.O. 1112.—Whereas Messrs The Periyar District Consumers Co-operative Wholesale Store Limited, Erode, (TN/4891), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit–Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(10)/84-FPG]

का. आ. 1113.—मैसर्स प्रताप राजस्थान स्पंशन स्टील लि., 10-पार्क स्ट्रीट एम. आई. रोड, जयपुर (राजस्थान) 2960) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितीयों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/9/84-एफ.पी.जी.]

S.O. 1113.—Whereas Messrs Partap Rajasthan Special Steel Limited, 10, Park Street, M. I. Road, Jaipur (RJ/2960), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nothwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(9)/84-FPG]

का. आ. 1114.—मैसर्स वालचंद हास्पीटल मिरज मेडिकल सेन्टर, मिरज-10, (महाराष्ट्र/3664/पी. एफ/इएक्सएम-17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/8/84-एफ.पी.जी.]

S.O. 1114.—Whereas Messrs Wanless Hospital Medical Centre, Miraj-416410 (Maharashtra) (MH/3864/PF/Exm. 17), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(8)/84-FPG]

का आ. 1115.—मैसर्स तमिलनाडु हैण्डीक्राफ्ट्स डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि., 26, डा. मुनिअप्पा रोड, मद्रास (तमिल नाडु/9055) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन जक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम

के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितीयों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/7/84-एफ.पी.जी.]

S.O. 1115.—Whereas Messrs Tamil Nadu Handicrafts Development Corporation Limited, 26, Dr. Muniappa Road, Madras-600010 (TN/9055), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nothwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(7)/84-FPG]

का.आ. 1116 :—मैसर्स यूनिवर्सल स्टील एण्ड एलोइज लि., 20-के. एम. मथुरा रोड, फरीदाबाद (पंजाब/4119) (रजिस्टर्ड आफिस, नई दिल्ली) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को, जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/5/84-एफ. पी. जी.]

S.O. 1116.—Whereas Messrs Universal Steel & Alloys Limited, 20, K. M. Mathura Road, Faridabad (Registered Office, New Delhi) (PN/4119) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nothwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees, to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(5)/84-FPG]

का. आ. 1117 :—मैसर्स हितकारी पोट्रीज (प्रा.) लिमिटेड, 63-64 इंडस्ट्रियल एरिया एन. आई. टी., फरीदाबाद (पंजाब/994) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/4/84-एफ. पी. जी.]

S.O. 1117.—Whereas Messrs Hitkari Potteries (Private) Limited, 63-64, Industrial Area, N.I.T. Faridabad (Registered Office, New Delhi) (PN/944), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notbwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(4)/84-FPG]

का. आ. 1118 :—मैसर्स इन्जेक्टो प्राईवेट लिमिटेड, 20/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा (पंजाब/2775) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या

विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/3/84-एफ. पी. जी.]

S.O. 1118.—Whereas Messrs Injecto (Private) Limited, 20/5, Mathura Road, Faridabad-121006 (Haryana), (I 2757) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme, are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(3)/84-FPG]

का. आ. 1119 :—मैसर्स पी. एच. डी. चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री 9-ए, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-1 (दिल्ली/3671), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध ...बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के ...रियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि ...व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए ...उस स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से ...अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

...बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, ...किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/2/84-एफ. पी. जी.]

S.O. 1119.—Whereas Messrs P.H.D. Chamber of Commerce and Industry, A-A, Connaught Place, New Delhi, (DL/3671), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nothwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(2)/84-FPG]

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1984

का० आ० 1120—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि कलकत्ता, दीघी (पूणे) और दोड़ स्थित विदेश संचार सेवा कर्मशालाओं के कर्मचारी अन्यथा ऐसे फायदे प्राप्त कर रहे हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबंधित फायदों के सारतः समरूप हैं ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 91क के साथ पठित धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् ऊपर उल्लिखित कारखाने को, 1 जनवरी, 1973 से 30 सितम्बर, 1985 तक की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देय थी ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी :—

(i) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित सभी अभिलेख उक्त अवधि के लिए थे या नहीं ; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफल स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे वह आवश्यक समझता है ;

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियों और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उसे उनकी परीक्षा करने दे, या उसे ऐसी जानकारी दे जिसे वह आवश्यक समझता है ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या

(घ) ऐसे कारखाने स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखा बही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना ।

[सं० एस-38014/29/81-एच० आई०]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में भूतलक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट की मंजूरी के लिए प्रार्थनापत्र देर से प्राप्त हुआ । तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

New Delhi, the 18th March, 1984

S.O. 1120.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of Overseas Communication Service Workshops at Calcutta, Dighi (Punc) and Dhond are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 read with section 91A of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for a period with effect from 1st January, 1973 upto and inclusive of the 30th September, 1985.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the optration of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the said period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, estabilshment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/29/81-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late. However, it is certified that the exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का० आ० 1121.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3200 तारीख 30 जुलाई, 1983 के अनुक्रम में मैसर्स साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड आसनसोल को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जून 1982 से 31 मई 1983 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तनमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ।

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने में, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को, उसके अभिकर्ता सेवक की, ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे क... स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर, में पाय जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास य विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्म चारी है, परीक्षा करना ;

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिस में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना ।

[संख्या-एस-38014/9/81-एच०आई०]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट के आवेदन पर कार्रवाई करने में कुछ समय लग गया है, इसलिए छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

S.O. 1121.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3200 dated the 30th July, 1983, the Central Government hereby exemption M/s. Cycle Corporation of India Limited, Asansol from the operation of the said Act, for a period of one year with effect from 1st June, 1982 upto and inclusive of the 31st May, 1983.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifynig the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period'; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider neccssary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other permises.

[No. S-38014/9/81-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely

का०आ० 1122.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील प्लान्ट लिमिटेड राउरकेला के अधीन राउरकेला स्टील प्लान्ट और फ़र्टिलाइजर प्लान्ट के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के 26 सितम्बर, 1982 से 30 सितम्बर, 1984 तक की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संवत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संवत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(3) यह अधिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर के किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखा-बहियां और अन्य दस्तावेजें, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना ।

[संख्या एस-38013/32/82-एच आई]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में भूतलक्षी प्रभा से छूट देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि मामले में कार्रवाई करने में समय लगा। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एस० 38013/32/82-एच०आई]

S.O. 1122.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of Rourkela Steel Plant and Fertilizer Plant under M/s. Hindustan Steel Plant Limited, Rourkela from the operation of the said Act for the period from the 26th September, 1982 upto and inclusive of the 30th September, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforsaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates ;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the notification; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating

to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38013/32/82-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption to this case, as processing the case took time. However, it is certified that the exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का०आ० 1123.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड, कानपुर के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 मार्च, 1975 से 30 सितम्बर, 1984 तक की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छूट देती है ।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त दायों के आधार पर हकदार हो जाते;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं :

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(3) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के संबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा —

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझें; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके कारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेजें ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक को उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है परीक्षा करना; या

(ध) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस०-38014/3/82-एच० आई०]

S.O. 1123.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the registered office of the National Textile Corporation (Uttar Pradesh) Limited, Kanpur from the operation of the said Act for the period from 1st March, 1975 upto and inclusive of the 30th September, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which the exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to in cash and kind being benefits in consideration be entitled to benefits provided by the employer of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, of any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/3/82-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

शुद्धिपत्र

का० आ० 1124.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 25 दिसम्बर, 1982 के पृष्ठ 4467 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के श्रम विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 4398, तारीख 8 दिसम्बर, 1982 में दूसरी पंक्ति में "श्री वेंकटरमन राइस ग्राउंड नट एंड आयल मिल" शब्दों के स्थान पर "श्री वेंकटरमन राइस एंड ग्राउंड नट आयल मिल" शब्द पढ़ें।

[सं० एस० 35019/297/82-भ०नि० II]

CORRIGENDUM

S.O. 1124.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation Department of Labour S.O. 4398 dated the 8th December, 1982 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 25th December, 1982 at page 4467 in lines 3 and 4 for the words "Shri Venkataramana Rice Ground Nut and Oil Mill, read "Shri Venkataramana Rice and Ground Nut Oil Mill."

[No. S. 35019/297/82-PF. II]

नई दिल्ली 15 मार्च 1984

शुद्धिपत्र

का० आ० 1125 .—भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) तारीख 18 दिसम्बर, 1982 के पृष्ठ 4380 पर प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 4262 तारीख 20 अगस्त 1982 में :—

(1) पंक्ति 6 में "2क" के स्थान पर "2ख" पढ़ें ।

(2) पंक्ति 8 में "कर्मचारी" के स्थान पर "नियमित कर्मचारी" पढ़ें ।

(3) पंक्ति 15 में "2क" के स्थान पर "2ख" पढ़ें ।

(4) पंक्ति 16 में "उक्त स्थापन" के स्थान पर "उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारियों" पढ़ें ।

[संख्या एस०-35014/264/82-पी० ए०-2]

ए० के० भट्टराई, अवर सचिव

New Delhi, the 15th March, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 1125.—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.O. 4262 dated 20th August, 1982, published in the Gazette of India, Part II Section 3 Sub-section (ii) dated the 18th December, 1982 at pagt 4381,—

(i) in line 4, for "2A" read "2B";

(ii) in line 9, for "employees" read 'regular employees';

(iii) in line 18, for "2A" read "2B";

(iv) in lines 20 and 21 for 'the said establishment' read "regular employees of the said establishment".

[No. S. 35014(264)/82-PF. II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984